चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

वामपंथ जीता पर वामपंथी हार गए

पेज-3

ममता सफल होंगी या असफल मुख्यमंत्री

पेज-4

कैसी जीत कैसी हार

पेज-5

साई की महिमा

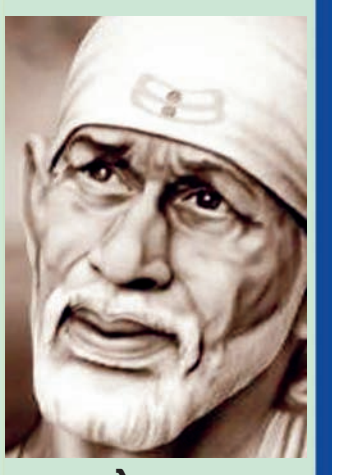

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 23 मई–29 मई 2011 | मूल्य 5 रुपये

चुनाव परिणाम सभी राजनीतिक दलों के लिए

ख़तरे का संकेत है

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

देश का अगला आम चुनाव न कांग्रेस के लिए आसान होगा और न भाजपा के लिए. कांग्रेस आगे बढ़ नहीं रही है, उसमें उत्साह नहीं पैदा हो रहा है. दूसरी तरफ़ भारतीय जनता पार्टी सिकुड़ रही है, विपक्ष का रोल नहीं निभा पा रही है और भरोसा नहीं जगा पा रही है कि वह लोगों की समस्याओं, चिंताओं और दर्द के निदान के लिए आंदोलन करेगी. अभी 2014 थोड़ी दूर है, तब तक हो सकता है कि इन चुनावों के संकेतों को समझ कर कोई नया समूह तैयार हो, जिसे देश के लोगों का समर्थन मिल सके.

संतोष भारतीय

इतिहास करवट लेने जा रहा है और जब इतिहास करवट लेने वाला होता है तो इसके संकेत वह पहले से दे देता है. पांच विधानसभा चुनावों के परिणाम हमारे सामने हैं, जो किसी की जीत या किसी की हार से बड़ा संकेत हमें दे रहे हैं. हम इससे सीख लें या न लें, यह हम पर निर्भर करता है. पर अगर हम सीख लेना चाहें तो वह बिल्कुल साफ़ और स्पष्ट है कि इतिहास करवट लेने वाला है. भारत के मतदाताओं, जिनमें असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लोग शामिल हैं, ने प्रतिनिधिक निर्णय दिया है. यह प्रतिनिधिक निर्णय बताता है कि बहुत सारे मुद्दे जिन्हें हमने मान लिया था कि वे अब मुद्दे नहीं हैं, दरअसल वे मुद्दे हैं. हम भले ही कहें, इन चुनावों से पहले लोग कहते थे, जिस तरह के सर्वे आए थे और ख़ासकर हमारे साथी मीडिया के लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है और तमिलनाडु में बराबर की लड़ाई होगी. हो सकता है कि करुणानिधि की सरकार बन जाए या हो सकता है कि जयललिता की सरकार बने, पर जयललिता की सरकार बनेगी तो बहुत थोड़े मतों से बनेगी. मतदाताओं ने इस धारणा को ख़त्म कर दिया कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है. उन्होंने साफ़ कर दिया कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है. इन चुनावों ने साबित कर दिया कि अब यह संभव नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव में अपने दावे करें, ज़्यादा पैसा ख़र्च करें, पैसा बांटे, मीडिया को ख़रीदें, फ़र्ज़ी सर्वे रिपोर्ट छपवाएं और यह आशा करें कि लोग उन्हें वोट दे देंगे. परफार्मेंस ज़रूरी है. निगेटिव वोटिंग की जगह पॉजिटिव वोटिंग भी होती है. पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पॉजिटिव वोटिंग हुई. असम में फ्रैक्चर्ड पॉजिटिव वोटिंग हुई. इसी तरह पुडुचेरी में पॉजिटिव वोटिंग हुई. मतदाता परिपक्व हो गया है, उसने एक झटके में सभी को सीख दी और बहुत सारी ग़लतफ़हमियां भी दूर कीं.

कांग्रेस पार्टी को मतदाताओं ने यह सीख दी कि अगर वह भ्रष्टाचार के साथ खड़ी दिखाई देती है और परफार्मेंस नहीं करती है तो इससे सारे देश में नुक़सान होने वाला है. देश में संदेश गया कि करुणानिधि की पार्टी के भ्रष्टाचार के साथ कांग्रेस खड़ी है. क्या कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार अलग है? अगर अलग है तो इसका सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है और अगर पार्टी और सरकार एक है तो फिर इस पार्टी का ख़ुदा ही मालिक है. जब राजा को हटाना चाहिए था तब नहीं हटाया, जब राजा पर मुक़दमा चलाना चाहिए था, तब नहीं चलाया. जब राजा को हटाया तो इसका श्रेय सरकार को न जाकर सीबीआई को मिला. कांग्रेस ने बंगाल में लगातार ग़लती की और हालत यह हुई कि कांग्रेस आधी से ज़्यादा सीटें हार गई. ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ राहुल गांधी ने बंगाल में जाकर बयानबाज़ी की. हालांकि वह संभल गए और बाद में इन बयानों से ख़ुद को दूर कर लिया. वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी का कहना है कि वे सीटें कांग्रेस इसलिए हारी, क्योंकि वहां उसने उन उम्मीदवारों को खड़ा किया, जो ममता के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे थे.

कांग्रेस पार्टी आंध्र में भी चुनाव हारी. दोनों जगह उसके फ़ैसले ग़लत साबित हुए. देश के पैमाने पर मोटे तौर पर यह लगा कि कांग्रेस पार्टी उन विषयों के प्रति गंभीर नहीं है, जिनका रिश्ता इस देश की जनता के मर्म, दर्द और तकलीफ़ से है. असम में कांग्रेस जीती, लेकिन मनमोहन सिंह या सोनिया की कांग्रेस नहीं जीती. वहां कांग्रेस जीती तरुण गोगोई के काम, दिग्विजय सिंह की रणनीति और परवेज़ हाशमी की मुसलमानों के बीच की गई कोशिशों की वजह से. चुनाव परिणामों से बहुत पहले दिग्विजय सिंह ने कह दिया था कि असम में कांग्रेस जीतने वाली है, क्योंकि वहां विपक्ष बंटा हुआ है. दिग्विजय सिंह का यह राजनीतिक आकलन बहुत सही था. उन्होंने होशियारी के साथ यह आकलन तब किया, जब वहां आख़िरी दौर का मतदान समाप्त हो गया. अगर वह यही बात पहले कह देते तो शायद विपक्ष वहां एक होने की कोशिश करता. एक होने के बाद भी शायद कुछ संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उन सभी के हित अलग-अलग थे. कांग्रेस इस सरकार के बनने से ख़ुश हो सकती है, केरल में अपनी सरकार बनने से ख़ुश हो सकती है, लेकिन यह देखना होगा कि कितनी सीटों से उसने अपनी सरकार बनाई है. अगर केरल के वामपंथियों, ख़ासकर मॉर्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर्कलह नहीं होती और वह जी-जान से चुनाव लड़ती तो कांग्रेस के लिए वहां सरकार बनाना मुश्किल हो जाता. इसमें कोई दो राय नहीं है कि केरल का एक चरित्र बन गया है कि वहां की जनता सरकार बनाने वाली पार्टियों को हर पांच साल में बदल देती है.

पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने जो फ़ैसला लिया, वह ग़लत साबित हुआ. कांग्रेस के नेताओं को यह पता था कि उनका फ़ैसला ग़लत है, लेकिन उनमें ग़लत फ़ैसला लेने के बाद उसे सुधारने की कोई परंपरा है नहीं. इंदिरा जी के बाद यह परंपरा ख़त्म हो गई. अगर नेता अपने ग़लत फैसले को सुधार ले तो वह महान नेता कहलाता है. कांग्रेस में इस समय कोई महान नेता नहीं है, सिर्फ़ नेता हैं और उन्हें पांच राज्यों में हुए चुनाव से सबक लेना चाहिए.

सोनिया गांधी के लिए सोचने का वक़्त है कि वह कैसे कांग्रेस पार्टी को सक्रिय करें. अगर वह कांग्रेस को सक्रिय नहीं कर पातीं, अपने सांसदों को प्रेरित नहीं कर पातीं कि वे चुनाव क्षेत्रों में जाएं और पार्टी की जीत के लिए जी-जान लगाएं तो उन्हें कम से कम गुजरात और उत्तर प्रदेश में वैसी ही हार का सामना करना पड़ेगा, जैसे इस बार तमिलनाडु या बंगाल में करना पड़ा है. सोनिया गांधी समझदार हैं. जो उनसे मिलने जाता है, उनकी समझदारी की दाद देता हुआ वापस लौटता है, पर विडंबना यह है कि सोनिया गांधी उन बातों, जिन्हें आम आदमी समझता है, जिन्हें पार्टी का साधारण कार्यकर्ता समझता है, को समझ कर भी पार्टी चला नहीं पातीं. यह यक्ष प्रश्न है, जिसका उत्तर अगर कहीं है तो सिर्फ़ सोनिया गांधी के पास. कांग्रेस के नेताओं के पास भी इसका उत्तर नहीं है. जिन नेताओं से हम बात करते हैं, वे भी आश्चर्यचकित रहते हैं. पर कांग्रेस इस मामले में ज़्यादा अनुशासित है कि उसके नेता बंद कमरों में एक-दूसरे का विरोध करते हैं, ताकि जनता के सामने उनके मतभेद न आने पाएं. लेकिन कांग्रेस कितनी सीख लेगी, पता नहीं. उसने सीख न लेने की कसम खाई है. उसके सांसद घरों में, दिल्ली में या विदेशों में आराम फरमाते रहते हैं. कांग्रेस के पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि वह अपने सांसदों को उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों में उतारे या उन प्रदेशों में साल भर पहले उनकी ड्यूटी लगा सके, जहां चुनाव होने वाले हैं. कांग्रेस के पास सांसदों की अच्छी-ख़ासी संख्या है, लेकिन कोई रोड मैप नहीं है, इच्छाशक्ति नहीं है कि वह अकेले सरकार बनाने की योजना बना सके.

भारतीय जनता पार्टी इन पांच राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की ख़राब हालत पर बहुत ख़ुश है. एक तरफ़ जहां कांग्रेस ख़ुश है कि वह ममता के साथ बंगाल में अपने को हारा हुआ नहीं मान रही है, असम और केरल में उसने सरकार बना ली. वह तमिलनाडु को याद नहीं करना चाहती. भारतीय जनता पार्टी इससे बिल्कुल उलट अपनी हार को देखना ही नहीं चाहती. उसके अध्यक्ष नितिन गडकरी एक अक्षम अध्यक्ष के रूप में सामने आए हैं. न तो वह पार्टी को उत्साहित कर सके, न कार्यकर्ताओं में जोश भर सके, न गुटबाज़ी दूर कर सके और न ख़ुद को एक ऊर्जावान, उत्साही, विवेकशील अध्यक्ष के रूप में स्थापित कर सके. नतीजे के तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, चाहे आडवाणी जी हों, चाहे सुषमा जी हों, अरुण जेटली हों, राजनाथ सिंह हों, मुरली मनोहर जोशी हों, किसी को भी वह संगठन के काम में लगने के लिए प्रेरित नहीं कर सके. नितिन गडकरी जसवंत सिंह जैसे लोगों को पार्टी में ले तो आए, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं कर सके. अब वह कोशिश कर रहे हैं कि उमा भारती को पार्टी में ले आएं, लेकिन उमा भारती को मध्य प्रदेश नहीं जाने देंगे. उन्हें यदि पार्टी में आना है तो उत्तर प्रदेश में काम करना होगा. ऐसा लगता है, जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास ऐसा कोई नेता नहीं बचा है, जो वहां पार्टी को पुनर्जीवित कर सके. यह पहला उदाहरण होगा,जिसमें कोई राजनीतिक पार्टी अपने वरिष्ठ नेता को आईएएस अफसरों की तरह एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित करेगी. यह नितिन गडकरी की सोच का दिवालियापन है. भारतीय जनता पार्टी मूर्छित अवस्था में जाती दिख रही है. इन चुनावों में इसका जैसा हाल हुआ है, उससे डर इस बात का है कि लोकसभा में अब इसकी बात में कोई दम रहेगा या नहीं. इन पांच प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के पास पहले जितनी सीटें थीं, इनमें एक भी सीट का इज़ाफ़ा नहीं हुआ, बल्कि आधे से ज़्यादा सीटों का नुक़सान हुआ है. असम इसका उदाहरण है. सवाल सीटों का नहीं है, पार्टी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

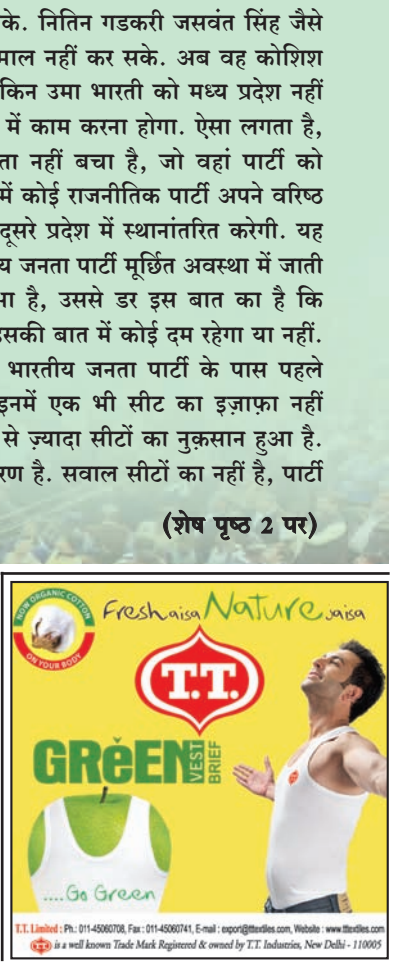

जबसे कैबिनेट में फेरबदल हुआ था और मुरली देवड़ा की जगह जयपाल रेड्डी को लाया गया था, तभी से यह अफ़वाह ज़ोरों पर थी कि पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव एस सुदर्शन को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

चतुराई भरी चाल

वित्त मंत्रालय में विशेष सचिव जी सी चतुर्वेदी का नाम सरकार ने नए पेट्रोलियम सचिव के रूप में प्रस्तावित क्या किया, इस पर कई लोगों की भौंहे तन गईं. पीएमओ में कुछ रुकावट के बाद अंततः चतुर्वेदी की फाइल पर हस्ताक्षर तो हो गए, लेकिन इस बीच दिल्ली में सरगर्मियां तेज रहीं. जबसे कैबिनेट में फेरबदल हुआ था और मुरली देवड़ा की जगह जयपाल रेड्डी को लाया गया था, तभी से यह अफवाह जोरों पर थी कि पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव एस सुदर्शन को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. आखिरकार, ऐसा ही हुआ और सुदर्शन को अब भारी उद्योग मंत्रालय में भेज दिया गया है. चतुर्वेदी को अपनी नई जिम्मेदारी के तौर पर कुछ कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. मसलन, विश्व स्तर पर क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत और उस वजह से आम आदमी पर पड़ने वाला असर, कारपोरेट मर्जर और गैस उत्पादन में आ रही कमी. उन्हें ओएनजीसी के लिए एक पूर्णकालिक चेयरमैन भी तलाशना है.

पीएसी के निशाने पर बाबू

पीएसी चीफ के रूप में फिर से नियुक्त मुरली मनोहर जोशी ने 2–जी घोटाले पर दी गई अपनी रिपोर्ट में यूपीए के बड़े–बड़े नामों को शामिल करके राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट में बाबुओं के रोल पर जो कुछ लिखा गया है, उसे बेहतर समर्थन मिल सकता है. जोशी की अगुवाई वाले पैनल ने बाबुओं को लेकर जो सिफारिशें की हैं, उनमें यह सिफारिश भी शामिल है कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम तीन साल के भीतर किसी भी वरिष्ठ बाबू को किसी ट्रिब्यूनल या निजी क्षेत्र की कंपनी ज्वाइन करने से रोका जाना चाहिए. जाहिर है, यह पैनल इन सिफारिशों के जरिए कुछ ऐसे वरिष्ठ बाबुओं की ओर इशारा कर रहा है, जिनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि वे दूरसंचार नीति के समर्थन में हैं और जिसकी वजह से 2–जी जैसे घोटाले ने जन्म लिया. क्या उक्त सिफारिश बाबुओं को मान्य होगी? ज़ाहिर है, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि पीएसी की रिपोर्ट पर राजनीतिक हवा का रुख़ कैसा होगा?

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

वर्मा पहुंचे साई

देश दीपक वर्मा उत्तर प्रदेश कैडर और 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें यह आशा थी कि वह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. उन्हीं के बैच के अनूप मिश्रा यह बाजी मार ले गए. वर्मा उपभोक्ता मंत्रालय के खाद्य एवं जन वितरण विभाग में अतिरिक्त सचिव सह वित्तीय सचिव के रूप में काम कर रहे थे और समय से पहले ही अपने मूल कैडर (उत्तर प्रदेश) में इसी साल जनवरी में वापस लौटे थे. राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में उनके नाम के कयास भी लगाए जा रहे थे. फिलहाल, वर्मा को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का महानिदेशक नियुक्त किया गया है. यह पद अतिरिक्त सचिव के समकक्ष है.

बसिल की जगह मित्रा

1995 बैच के आईसीएएस अधिकारी गोविंद गोपाल मित्रा फर्टिलाइजर विभाग के तहत आने वाली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कोऑर्डिनेशन कमेटी में संयुक्त निदेशक का पद संभाल सकते हैं. वह 1991 बैच के आईसीएएस अधिकारी टी ए बसिल की जगह ले सकते हैं.

जितेंद्र वाणिज्य मंत्रालय में जेएस

1983 बैच के आईएएस अधिकारी जितेंद्र कुमार दादू को वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. ऐसी ख़बर है कि वह राजीव खेर की जगह लेंगे.

मीनाक्षी जाएंगी महिला आयोग

ऐसी संभावना है कि 1981 बैच की आईए एंड एएस अधिकारी मीनाक्षी घोष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग में जाएंगी. वह एस एस पुजारी की जगह पर नियुक्त की जाएंगी.

पंकज बनेंगे जेएस

गुजरात कैडर और 1986 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज कुमार का नाम संयुक्त सचिव पद के लिए बनाई गई सूची में शामिल कर लिया गया है.

चुनाव परिणाम सभी राजनीतिक दलों के लिए ख़तरे का संकेत है

पृष्ठ एक का शेष

को मुखर बनाने का है, पार्टी में ऊर्जा भरने का है, हारने के बावजूद पार्टी में लड़ाई लड़ने की क्षमता विकसित करने का है. नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते इनमें से कुछ नहीं कर सके.

मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं देंगे और वह इस हार को अपनी हार के रूप में नहीं लेंगे. भारतीय जनता पार्टी से कोई सहमत हो या न हो, लेकिन उसका विपक्ष का रोल सक्षमता से कैसे निभे, इसमें हर उस आदमी की रुचि होगी, जिसका लोकतंत्र पर विश्वास है. ज़रूरत इस बात की है कि पार्टी को एक ऐसा अध्यक्ष मिले जो पूरे संगठन में नए सिरे से ऊर्जा भर सके. आज ऐसे दो लोग हो सकते हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी, जिन्हें अध्यक्ष के रूप में पार्टी का पूरा संचालन सौंपा जाए और आज़ादी दी जाए कि वह किस तरह का दिशानिर्देश या दिशा लोकसभा और राज्यसभा के लिए तय करना चाहते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में अपना रोल निभा सके. दूसरा नाम जसवंत सिंह का है. जसवंत सिंह को शायद आज भी पता नहीं होगा कि उन्हें क्यों पार्टी से निकाल दिया गया, यह भी पता नहीं होगा कि उन्हें पार्टी में पुनः क्यों लिया गया. लेकिन अब जबकि वह पुनः पार्टी में ले लिए गए हैं और अगर आडवाणी जी पार्टी का संचालन स्वीकार नहीं करते हैं तो जसवंत सिंह दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें अध्यक्ष के रूप में पार्टी का संचालन दिया जा सकता है. उनकी छवि एक उदारवादी नेता की छवि है, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी की झलक दिखती है. भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय होना लोकतंत्र के लिए भी बहुत ज़रूरी है.

संपूर्ण वामपंथ अपनी राजनीति और बुनियादी उद्देश्यों से भटक गया है. उसकी पहचान केरल से नहीं, बंगाल से मानी जाती है. 34 साल का शासन और उसके बाद ऐसी विदाई! आज वामपंथ के सामने चुनौती है. वामपंथी अगर अपने बुनियादी उद्देश्यों को लेकर संघर्ष के रास्ते पर उतरते हैं और ग़रीबों के संघर्ष को उठाते हैं, लेकिन ग़रीबों का मतलब सिर्फ़ मज़दूरों का संघर्ष नहीं, किसानों, दलितों और अल्पसंख्यकों का संघर्ष भी इसमें शामिल है, तब शायद वामपंथ ख़ुद को पुनर्जीवित कर सके. बिहार में कभी वामपंथियों की थोड़ी सी पकड़ थी, इसके अलावा हिंदी क्षेत्र में कभी भी वामपंथियों की पकड़ नहीं रही. अब वामपंथी केरल और बंगाल से भी उखड़ गए हैं. केरल में अगली बार उनका सत्ता में आना इस पर निर्भर करेगा कि अच्युतानंदन जी की जगह नया नेता कौन होगा. बंगाल में मॉर्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास इस समय कोई नेता नहीं है. भूतपूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ज्योति बसु की सलाह नहीं मानी. ज्योति बसु को वी पी सिंह ने सलाह दी थी कि बंगाल में मुसलमानों से पिछले 34 सालों में किए गए वादों को अगर पूरा नहीं किया गया तो आपका सत्ता में वापस आना मुश्किल है. बुद्धदेव ने ज्योति बसु को आश्वासन दिया था कि वह उन वादों को पूरा करेंगे. विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपील की और मुसलमानों ने पिछले चुनाव में वामपंथियों का साथ दिया, लेकिन बुद्धदेव ने उन वादों को पूरा नहीं किया. इसका परिणाम इस चुनाव में निकला. संपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय, बंगाल में अल्पसंख्यक समुदाय से मतलब मुस्लिम समाज से है, वामपंथ से एकबारगी कटकर तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ गया. वामपंथी अपनी आलोचना करेंगे, आत्मावलोकन करेंगे, लेकिन असली जगह नहीं पहुंच पाएंगे. चुनाव से एक साल पहले कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ए वी वर्धन से मेरी बात हुई. वर्धन साहब इस राय से सहमत थे. चुनाव के चार महीने पहले मॉर्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव प्रकाश करात से मेरी बातचीत हुई, वह भी इस बात से सहमत थे, लेकिन उन्होंने बंगाल में अपनी ग़लतियां सुधारने की कोशिश नहीं की. हो सकता है कोशिश की हो और बुद्धदेव भट्टाचार्य ने न मानी हो. अंत में परिणाम निकला वामपंथियों की संपूर्ण सफाई. वामपंथियों के सामने अब एक अंतिम अवसर है. अगर वे जनता का संघर्ष लेकर खड़े रहेंगे तो उनकी प्रासंगिकता बची रहेगी, अन्यथा वह भी समाप्त होने का डर पैदा हो गया है.

करुणानिधि का साथ देकर कांग्रेस ने अपने लिए कांटे बो दिए हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसने भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर अपने मुख्यमंत्री, सांसद और सहयोगी दल के मंत्री के ख़िलाफ़ कार्रवाई की. सांसद सुरेश कलमाडी पर कार्रवाई तब हुई, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तब उन्हें पार्टी से निकाला गया. सारी कार्रवाई वक़्त निकल जाने के बाद की गई. हमारे यहां कहावत है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत. कांग्रेस, ख़ासकर सोनिया गांधी को ऐसा प्रभावी नेतृत्व देश को दिखाना होगा, जिसकी बात सरकार और पूरी पार्टी माने. अन्यथा कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना तो दूर की चीज, लोकसभा चुनाव में भी इतने सांसद जुटाने मुश्किल हो जाएंगे, जो सरकार या गठबंधन की सरकार बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं.

तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र के संकेत क्या हैं? जयललिता भी बहुत ईमानदार नहीं हैं. पिछली बार भ्रष्टाचार के आरोप में ही जनता ने उनके ख़िलाफ़ करुणानिधि को वोट दिया था, लेकिन करुणानिधि के परिवार, सहयोगियों, उनकी बेटी के सहयोग से ए राजा ने जिस तरह तमिलनाडु और सारे देश में लूट मचाई, उसने जनता को संशय में डाल दिया. करुणानिधि की हार या जीत का इंतजार सारे देश को था. अगर उनकी पराजय पांच या दस सीट से होती तो यह देश के लोगों के लिए चिंता की बात होती, क्योंकि इससे यह संदेश

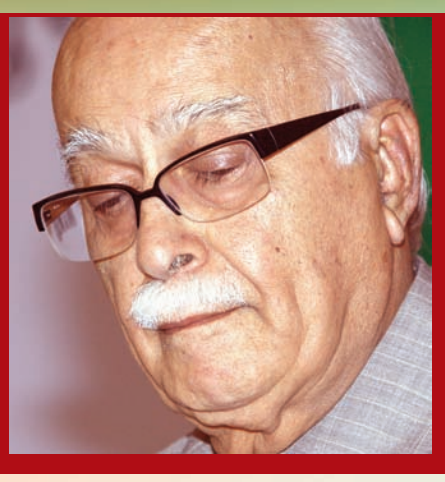

मिलता कि भ्रष्टाचार अब देश में चिंता का विषय नहीं रहा, लेकिन तमिलनाडु के लोगों ने ऐसा फ़ैसला लिया, जैसा देश के लोग उम्मीद कर रहे थे. देश के लोग चाहते थे कि करुणानिधि बुरी तरह हारें, क्योंकि उनकी पार्टी और उनके रिश्तेदारों का भ्रष्टाचार जयललिता के भ्रष्टाचार से हज़ार गुना बड़ा था. तमिलनाडु के लोगों ने एक सच्चे हिंदुस्तानी मतदाता होने का कर्तव्य निभाया. हिंदुस्तान में जब मतदाता को मौक़ा मिलता है, वह अपना कर्तव्य निभाता है. यही कर्तव्य मतदाता ने बंगाल में निभाया. वहां पिछले 34 सालों में पहली बार लोगों ने आज़ादी से वोट डाले. ममता बनर्जी की छवि, उनका लड़ाकू चेहरा, लोगों को दिए आश्वासन, वामपंथ से निराशा और ममता के प्रति आशा जैसे कई सवाल थे. लेकिन जब आप वोट ही न डाल पाएं तो ये सवाल सिर्फ़ दिमाग़ मे बने रह जाते हैं. बंगाल में चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण रही. बंगाल से मेरे दोस्तों ने मुझे फोन करके बताया कि पिछले 30–35 सालों में पहली बार लोगों ने अपनी मर्जी से अपने उम्मीदवारों को वोट दिए. जब लोगों ने वोट डाले तो ऐसा बदला लिया, जो इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ गया.

पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने जो फ़ैसला लिया, वह ग़लत साबित हुआ. कांग्रेस के नेताओं को यह पता था कि उनका फ़ैसला ग़लत है, लेकिन उनमें ग़लत फ़ैसला लेने के बाद उसे सुधारने की कोई परंपरा है नहीं. इंदिरा जी के बाद यह परंपरा ख़त्म हो गई. अगर नेता अपने ग़लत फैसले को सुधार ले तो वह महान नेता कहलाता है. कांग्रेस में इस समय कोई महान नेता नहीं है, सिर्फ़ नेता हैं और उन्हें पांच राज्यों में हुए चुनाव से सबक लेना चाहिए. ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों ने जिताया, चुनाव आयोग ने भी रास्ता साफ़ किया. अब ममता की बारी है. उनके पास सिर्फ़ छह महीने का वक़्त है. डॉ. लोहिया कहा करते थे कि जो सरकार छह महीने के भीतर आगे किए जाने वाले कामों की नींव न डाल सके और अपना रोडमैप जनता के सामने न रख सके, वह बचे हुए साढ़े चार सालों में भी कुछ नहीं कर सकती, सिवाय जनता को निराशा देने के. बंगाल में इन्हीं छह महीनों में तय होगा कि ममता बनर्जी एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल तय करेंगी या ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगी, जिससे लोगों ने आशा तो बहुत लगाई थी, लेकिन हाथ लगी सिर्फ़ निराशा.

देश का अगला आम चुनाव न कांग्रेस के लिए आसान होगा और न भाजपा के लिए. कांग्रेस आगे बढ़ नहीं रही है, उसमें उत्साह नहीं पैदा हो रहा है. दूसरी तरफ़ भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष के करिश्मे की वजह से लगातार सिकुड़ती जा रही है. राहुल गांधी 2014 में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं. कांग्रेस के लोगों का कहना है कि 2014 में अपने दम पर 200 से ज़्यादा सांसद जिताकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 2014 राहुल के लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाला है. अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत कहीं सही न हो जाए. दूसरी तरफ़ भारतीय जनता पार्टी सिकुड़ रही है, विपक्ष का रोल नहीं निभा पा रही है और भरोसा नहीं जगा पा रही है कि वह लोगों की समस्याओं, चिंताओं और दर्द के निदान के लिए आंदोलन करेगी. उसी तरह एनडीए, जिसके साथ पार्टियां जुड़ी थीं और जिसकी वजह से अटल जी की सरकार चली, वह भी निष्क्रिय हो गया है. शायद इसलिए कि शरद यादव की कोशिशों पर भारतीय जनता पार्टी रोक लगा रही है और शरद यादव को लगता होगा कि जब वक़्त आएगा तो देखेंगे कि क्या स्वरूप होगा. इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरद यादव के दिमाग़ में कोई राजनीतिक नक्शा होगा, जिसकी वजह से वह एनडीए को निष्क्रिय किए हुए हैं. कुल मिलाकर ये चुनाव पार्टियों के लिए निराशाजनक हैं, ख़तरे का संकेत हैं. ये उन्हें संभलने, चेतने और अपनी कार्य प्रणाली सुधारने की चेतावनी देते हैं. वहीं दूसरी ओर देश के लोगों के लिए ये चुनाव आशा की किरण हैं. आशा की किरण इसलिए कि कोई ऐसा समूह, व्यक्ति, सपना और वादा अगर सामने आता है, जिसमें लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान निकलता दिखे तो लोग उसके साथ ज़रूर खड़े होंगे. अब यह समूह या व्यक्ति कौन होगा, अभी नहीं पता. अभी 2014 थोड़ी दूर है, तब तक हो सकता है कि इन चुनावों के संकेतों को समझ कर कोई नया समूह तैयार हो, जिसे देश के लोगों का समर्थन मिल सके.

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 3 अंक 11
दिल्ली, 23 मई–29 मई 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

विशेष संवाददाता
सरोज कुमार सिंह (बिहार)

प्रबंध संपादक (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)
डॉ. सुनील कौशिक

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9871194800
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4+4+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली में बैठे देश चलाने वाले लोग इस चुनाव नतीजे की अपने ही अंदाज़ में व्याख्या करने में जुटे हैं. वाममोर्चा की हार को नव उदारवाद की जीत समझा जा रहा है.

बंगाल चुनाव

वामपंथ जीता पर वामपंथी हार गए

राजनीतिक दलों को एक बीमारी लगने लगी है. यह बीमारी पहले भारतीय जनता पार्टी को लगी थी, अब कम्युनिस्ट पार्टियों को लग गई है. बीमारी यह है कि इन पार्टियों के पास विचारधारा तो है, लेकिन ये उस पर चलती नहीं हैं. इनके पास कार्यकर्ता हैं, लेकिन जनता से तालमेल बनाने की क्षमता नहीं है. मज़बूत संगठन भी है, लेकिन दिशाहीनता की चपेट में है. ज़मीन से जुड़े नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है. पार्टी की नीतियों का फ़ैसला वे करते हैं, जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, जिन्हें जनता के वोट से मतलब नहीं है. एयरकंडीशन कमरों में बैठकर, टेलीविजन चैनलों के स्टूडियो में बहस करके अपनी राजनीति चमकाने वाले नेता जिस किसी पार्टी के कर्ताधर्ता होंगे, चुनाव में उसका हाल यही होगा. देश की जनता ने इस बीमारी को अब पहचान लिया है.

मनीष कुमार

वाममोर्चा का सफ़ाया क्यों हुआ, दुनिया के दूसरे देशों की तरह क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में भी मॉर्क्सवाद अप्रासंगिक हो गया है, क्या पश्चिम बंगाल और केरल की हार से वामपंथ मृतप्राय: हो गया, क्या भविष्य में वाममोर्चा फिर से मजबूत हो सकता है, क्या भारत में वाम राजनीति का स्थान नहीं रहा, इस हार के बाद वाममोर्चा के पास क्या विकल्प बचा है और आने वाले समय में वामपंथ की मुश्किलें क्या-क्या हैं आदि ऐसे कई सवाल हैं, जिन्हें समझना महत्वपूर्ण है.

बर्लिन की दीवार ढहने और सोवियत संघ के विघटन के कई सालों बाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा लगने लगा है कि हथौड़ा और हंसिया वाला लाल झंडा बंगाल की खाड़ी में विलीन होने वाला है. पश्चिम बंगाल और केरल में एक साथ वाममोर्चे का सफ़ाया होना भारत ही नहीं, विश्व के लिए एक ऐतिहासिक घटना है. वह इसलिए, क्योंकि भारत में पहली बार दुनिया की पहली चुनी हुई वामपंथी सरकार केरल में बनी और सबसे ज़्यादा दिनों तक वहां रही. दुनिया के कई देशों में मॉर्क्सवाद का सफ़ाया हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में यह मज़बूती से डटा रहा. वाममोर्चा के लिए पश्चिम बंगाल का नतीजा मनोबल तोड़ने वाला नतीजा है. बंगाल की खाड़ी से हिमालय की गोद तक 34 सालों तक यह परचम लहराता रहा. अफ़सोस इस बात का है कि इस झंडे को लेकर चलने वालों को इसका रंग तो याद रहा, लेकिन उन्होंने इसके हथौड़ा और हंसिया को ही भुला दिया. सोनार बांग्ला कब पीतल और तांबे की बन गई, यह वाममोर्चा सरकार को पता ही नहीं चला. जब जनता को ख़बर लगी तो उसने इतिहास लिख दिया.

कोई भी दल अगर 34 सालों तक सत्ता में रहता है तो ज़रूर कोई बात होगी. अचानक से यह नहीं हो सकता है कि वाममोर्चा ने सब कुछ ग़लत किया है. अगर ऐसा होता तो अब तक वह चुनाव जीतता नहीं आता. वैसे भी किसी प्रजातंत्र में कोई भी दल हार सकता है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है. यह बिल्कुल ग़लत होगा अगर हम मान लें कि एक चुनाव हारने से किसी पार्टी का अंत हो जाता है. पर समस्या यह है कि पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों से वाममोर्चा को हर छोटे-बड़े चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है. वाममोर्चा चुनाव क्यों हार गया, इसे समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि बंगाल में वाममोर्चा ने 34 सालों तक सत्ता में बने रहने का इतिहास कैसे रचा.

वाममोर्चा की सबसे बड़ी ताकत उसकी विचारधारा है. मॉर्क्सवाद की गहराई और उसकी त्रुटियों को अगर हम नज़रअंदाज़ कर दें, इससे जुड़े वैचारिक एवं सैद्धांतिक सवालों और विवादों को छोड़ दें तो मॉर्क्सवाद भारतीय परिवेश में सरकार चलाने का सबसे सटीक मूलमंत्र देता है. कहने का मतलब यह है कि सरकार उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों के बजाय मज़दूरों और किसानों के विकास के लिए काम करे, समाज में जो लोग शोषित हैं उनके उत्थान और सशक्तिकरण के लिए काम करे, ग़रीबों के लिए विशेष नीतियां और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान हों तथा समाज के निचले तबके के लोगों का जीवन स्तर सुधारे, यही किसी भी सरकार का पहला दायित्व होना चाहिए. हालांकि 1991 से केंद्र की सरकार ठीक इससे उल्टा काम कर रही है. नव उदारवाद का सबसे बुरा असर ग़रीबों पर ही दिखता है. निजीकरण और उदारवाद की लपटें बंगाल तक पहुंच गईं. जो विचारधारा वामपंथी दलों की सबसे बड़ी ताक़त होती थी, उसके साथ समझौता करना महंगा पड़ गया. कल-कारखाने बंद हो गए, मज़दूर बेरोज़गार हो गए. जिन्हें काम मिलता भी है तो पैसे कम मिलते हैं. नए उद्योग लगाने में सरकार विफल रही. जबकि दूसरे राज्यों में तेज़ी से विकास हुआ. शिक्षा का स्तर तो बेहतर था, लेकिन शिक्षा व्यवस्था ख़राब होती चली गई. युवाओं के सामने अवसरों की कमी हो गई. मज़दूर, किसान, युवा और कामगार पश्चिम बंगाल से पलायन करने लगे. वैचारिक दृष्टि से सरकार के ये महत्वपूर्ण दायित्व थे. वामपंथी सरकार ने विचारधारा और दायित्व दोनों को भुला दिया. नतीजा हमारे सामने है.

कोई भी सरकार या राजनीतिक पार्टी सिर्फ़ विचारधारा की पवित्रता पर नहीं चलती. उसकी नीतियां ही बताती हैं कि वह जनता के साथ खड़ी है या फिर उसके ख़िलाफ़. पिछले तीन दशकों से अपनी नीतियों की वजह से वाममोर्चा ने बंगाल के ग्रामीणों के दिलों पर राज किया. ग्रामीण क्षेत्र वामपंथ का गढ़ माना जाता था. शहरी इलाक़ों में निचले एवं मध्य वर्ग का साथ मिला. वाममोर्चा का समर्थन इतना सशक्त और संपूर्ण था कि जब उसकी सरकार पश्चिम बंगाल में आई, तब उसने भूमि सुधार जैसे क्रांतिकारी क़दम उठाए. जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्हें ज़मीन मिली. पूरे देश के लिए पश्चिम बंगाल एक उदाहरण बन गया. मज़दूरों के विकास और कल्याण के लिए भी क़दम उठाए गए. कई सालों तक पश्चिम बंगाल सबसे ख़ुशहाल राज्य रहा. समय के साथ-साथ परिस्थितियां भी बदल जाती हैं. अच्छी सरकार का मतलब होता है, जो समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बदलती है. वाममोर्चा की सरकार यही काम नहीं कर सकी. जब केंद्र सरकार ने उदारवाद की नीतियों को अपनाया तो वाममोर्चा ने इसका विरोध किया, सही किया, लेकिन उसके स्थान पर वह कोई वैकल्पिक योजना देने में कामयाब नहीं हुआ. राज्य की आर्थिक स्थिति ख़राब होने लगी. सरकार ने जब बदलाव का दामन थामा तो सबसे बड़ी चूक हो गई. इस बदलाव में किसानों और मज़दूरों के लिए कोई जगह नहीं थी. नतीजा यह हुआ कि दार्जिलिंग के चाय बगानों से लेकर कोलकाता-आसनसोल-दुर्गापुर और हुबली के दोनों किनारों पर बसे उद्योगों ने दम तोड़ दिया. गेहूं, दाल और तिलहन के उत्पादन में राज्य पिछड़ गया. बंगाली मध्य वर्ग भी नाराज़ हो गया. भूमि सुधारों वाली दुधारू गाय सूख गई. जमींदारों का एक वर्ग गया तो 32 सालों से बिल्डरी और सरकारी ठेकों का माल खा रहा एक नया मालदार वर्ग तैयार हो गया. जनता को यह लगने लगा कि कभी भूमिहीनों को भूमि देने वाली सरकार किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीन छीन रही है, उद्योगपतियों के ख़िलाफ़ बोलने वाली पार्टी अब उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है. चुनाव नतीजे लोगों के इसी एहसास का निष्कर्ष हैं.

नेतृत्व का राजनीति पर गहरा असर होता है. यही किसी भी राजनीतिक दल का चेहरा होता है. 34 सालों तक पश्चिम बंगाल पर शासन करने का श्रेय वाममोर्चा को तो है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान ज्योति बसु का भी है. ज्योति बसु की कार्यकुशलता और लोकप्रियता बेमिसाल थी. ज्योति बसु ने जब सक्रिय राजनीति को अलविदा कहा तो उनके पीछे नेताओं की फ़ौज खड़ी थी. ज्योति बसु के जाते ही पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा की स्थिति ख़राब होने लगी. अगर नेता पार्टी का चेहरा है तो पार्टी संगठन बेशक़ उसका शरीर है. किसी भी पार्टी को अपनी लोकप्रियता और अपना समर्थन बनाए रखने और फैलाने के लिए एक सशक्त संगठन की ज़रूरत पड़ती है. वामपंथी पार्टियां इसमें सबसे आगे हैं. इनके संगठन के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन भी फीका दिखाई पड़ता है. बंगाल का ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई पंचायत नहीं है, जहां वामदलों का कार्यालय नहीं है. वहां पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हर रोज मिलते-जुलते हैं, देश-विदेश की घटनाओं पर बातचीत और बहस करते हैं. कार्यकर्ताओं की बाक़ायदा ट्रेनिंग होती है, कैंप लगाए जाते हैं. वामपंथी दलों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने बंगाल की जनता को राजनीतिक परिपक्वता दी है. समाज के हर क्षेत्र में इनकी शाखाएं हैं. शहर हो या गांव, सीपीएम और सीपीआई का आधिकारिक कार्यकर्ता होना गर्व की बात होती थी. लोग भी इनका आदर करते थे, लेकिन समय के साथ-साथ इसमें बदलाव आया. पढ़े-लिखे और भद्र लोगों की जगह गुंडे और बदमाशों ने ले ली. पार्टी संगठन विकृत और पथभ्रष्ट हो गया. लोग वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं से डरने लगे. सीपीएम के कार्यकर्ता दुर्गा पूजा या फिर किसी और कार्यक्रम का बहाना बनाकर लोगों से वसूली करने लग गए. पार्टी कार्यकर्ता गुंडों में परिवर्तित हो गए. छात्र राजनीति भी गुंडागर्दी का अड्डा बन गई. पुलिस भी पार्टी के इशारे पर काम करने लगी. ग्रामीण इलाक़ों में कार्यकर्ता खुलेआम पुलिस के सामने हथियार लेकर लोगों को डराने और धमकाने लग गए. पार्टी कार्यकर्ताओं की अकड़ और घमंड से लोग सहम गए.

पश्चिम बंगाल का बुद्धिजीवी वर्ग वाममोर्चा के साथ रहा. बंगाल के बुद्धिजीवियों ने हमेशा वाममोर्चा की विचारधारा, योजना, लीडरशिप और संगठन की सिर्फ़ हिमायत ही नहीं की, बल्कि यह प्रचार किया और संदेश दिया कि वाममोर्चा दूसरी किसी भी पार्टी से बेहतर है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह बुद्धिजीवी वर्ग वाममोर्चा से दूर चला गया. इतना दूर कि नंदीग्राम, सिंगूर और लालगढ़ की घटनाओं के बाद ये लोग सरकार के ख़िलाफ़ सड़क पर उतर आए. कभी वाममोर्चा से काफ़ी नजदीक रहने वाले लेखक अतिन बंदोपाध्याय कहते हैं कि वाममोर्चा को तो बीस साल पहले ही सत्ता से बाहर कर देना चाहिए था, क्योंकि वामदलों के आतंक और अहंकार से लोग तंग आ चुके हैं. बंगाल के कलाकारों और लेखकों के बीच बुद्धदेव भट्टाचार्य काफ़ी लोकप्रिय हुआ करते थे. फिर ऐसी क्या ग़लतियां हुईं, जिनसे बंगाल का बुद्धिजीवी वर्ग समर्थक से विरोधी बन गया. लेखक सिर्शेंदु मुखोपाध्याय कहते हैं कि वामदलों के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और नकारापन वाममोर्चा की हार की वजह है. अब तक वे सिर्फ़ फ़र्ज़ी मतदान की वजह से जीतते आ रहे थे. जो बुद्धिजीवी तीन साल पहले तक वामदलों के सक्रिय समर्थक थे, मॉर्क्सवाद में विश्वास रखते थे, वे आज ख़िलाफ़ हो गए.

विचारधारा, संगठन, नीतियां, नेतृत्व और बुद्धिजीवियों का समर्थन वाममोर्चा की असली ताक़त थी. वामपंथी दलों की ताक़त कमज़ोरी में बदल गई. ऐसे में बंगाल की राजनीति में धीमी गति से ही सही, मगर सतत एक ज़मीनी नेतृत्व छाने लगा. नीले बॉर्डर वाली सफेद साड़ी और पैरों में हवाई चप्पल. पानी और कीचड़ भरी सड़कों पर चलते तेज कदम, नाकामियों से निराश न होने वाला आक्रामक चेहरा, जनता के दु:ख-दर्द को अपना समझने वाला भाव, पश्चिम बंगाल की तीन दशकों की वाम राजनीति के कुरुक्षेत्र में यह चेहरा हर जगह दिखा है. ममता बनर्जी ने कुछ नया नहीं किया. उन्होंने वामपंथी सरकार द्वारा दिए गए मौक़े का फ़ायदा उठाया. ममता की कोई विचारधारा नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई संगठन नहीं है. बुद्धिजीवी ममता को हमेशा अपरिपक्व मानते रहे. लेकिन ममता में जज्बा है. दबी-कुचली, शोषित, बेरोजगार और असहाय जनता के लिए लड़ने का जज्बा. जब सिंगूर में टाटा का नैनो कारखाना लगने के समय ममता को लगा कि बहुत सारे किसान अनिच्छुक हैं और सरकार उन्हें पर्याप्त मुआवज़ा दिए बिना ज़मीन ले रही है तो उन्होंने आंदोलन किया. किसानों की ज़मीन बचाने के लिए जो काम वामपंथी दल करते आए, वही काम ममता बनर्जी ने किया. फिर नंदीग्राम के केमिकल हब के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होते ही आंदोलन भड़का. ममता का वह आंदोलन पूरे दक्षिण बंगाल में फैल गया. समय के साथ-साथ ममता में मुद्दों की समझ भी बढ़ती गई. बांग्ला भद्रलोक को भी लगने लगा है कि ममता अब परिपक्व हो गई हैं. ममता ने आंधी-पानी, जलती दुपहरिया में और धूल भरे रास्तों पर जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष किया. यही तो वामपंथ की आत्मा है. वामपंथियों को इस बात से ख़ुश होना चाहिए कि ममता की जीत उन मूल्यों की जीत है, जिन मूल्यों का आधार वामपंथ है.

दिल्ली में बैठे देश चलाने वाले लोग इस चुनाव नतीजे की अपने ही अंदाज में व्याख्या करने में जुटे हैं. वाममोर्चा की हार को नव उदारवाद की जीत समझा जा रहा है. यही ख़तरा है. कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि जिस तरह महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में उदारीकरण और निजीकरण की वजह से तरक्की हुई है, वैसा विकास बंगाल में नहीं हुआ. इसलिए लोगों ने वाममोर्चा को उखाड़ फेंका. यूरोप और अमेरिका के अख़बारों में यह लिखा जा रहा है कि कांग्रेस की यूपीए सरकार को पीछे खींचने, उदारवाद पर ब्रेक लगाने, न्यूक्लियर डील को पटरी से उतारने और भारत की छवि बिगाड़ने की वजह से लोगों ने वामपंथियों को सबक सिखाया है. आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली में बैठे कई लोग इसी दलील को सही मान रहे हैं. इस तरह के विश्लेषण से बचने की ज़रूरत है. अगर वामपंथ की हार को उदारवाद और बाज़ारवाद के चश्मे से देखा गया तो हम ग़लत नतीजे पर पहुंच जाएंगे, जो घातक साबित हो सकता है. पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों की हार नव उदारवाद की नहीं, वामपंथ के मूल्यों की ही जीत है.

manish@chauthiduniya.com

ममता बनर्जी ने कुछ नया नहीं किया. उन्होंने वामपंथी सरकार द्वारा दिए गए मौक़े का फ़ायदा उठाया. ममता की कोई विचारधारा नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई संगठन नहीं है. बुद्धिजीवी ममता को हमेशा अपरिपक्व मानते रहे. लेकिन ममता में जज़्बा है. दबी-कुचली, शोषित, बेरोज़गार और असहाय जनता के लिए लड़ने का जज़्बा.

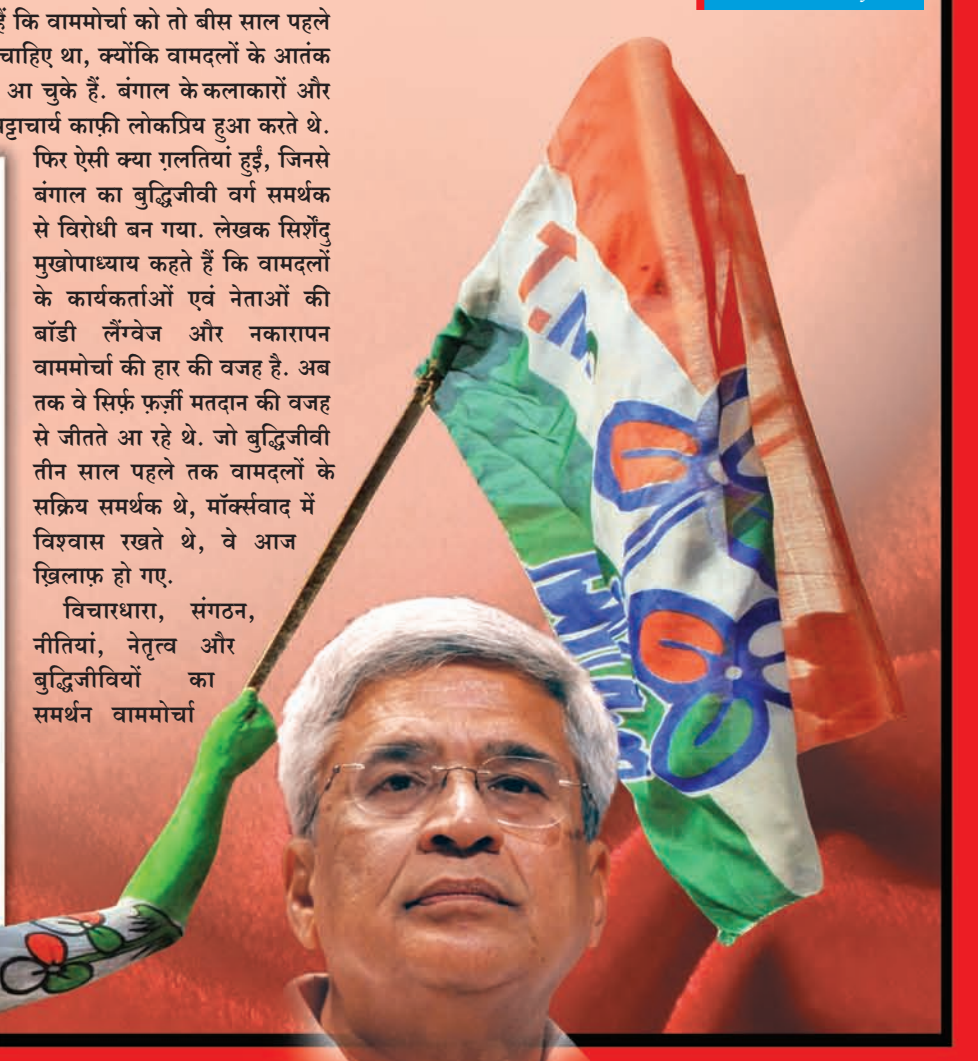

कांग्रेस को जीत तो मिल गई, लेकिन अब उसे अपना ध्यान जनता की समस्याओं पर केंद्रित रखना होगा.

सिर्फ़ छह महीने में पता चल जाएगा

ममता सफल होंगी या असफल मुख्यमंत्री

राजेश एस कुमार

जनता ने तो सत्ता का पोरिवर्तन कर दिया है, अब पोरिवर्तन करने की बारी ममता बनर्जी की है. अकेले दम पर लगभग दो तिहाई सीटें बटोरने के बाद भी अगर ममता बनर्जी कांग्रेस को सरकार में शामिल होने का न्योता देती हैं तो इसे सिर्फ उनकी भलमनसाहत या कहें कि गठबंधन धर्म निभाने की बात नहीं माना जाना चाहिए. वैसे भी राजनीति में भलमनसाहत जैसे शब्दों के लिए जगह नहीं होती. पश्चिम बंगाल में सालों तक विपक्ष की भूमिका निभाने वाली ममता बनर्जी को यह अच्छी तरह मालूम है कि जनता ने जो पोरिवर्तन किया है, वह महज 34 साल पुरानी सत्ता की वजह से ही नहीं किया है. जनता ने यह बदलाव इस आशा के साथ भी किया है कि ममता अब उनकी जिंदगी और पश्चिम बंगाल का पोरिवर्तन करेंगी.

जाहिर है, ममता के लिए यह भारी जीत एक भारी जिम्मेदारी भी साथ लेकर आई है. अपने प्रचार के दौरान तृणमूल ने वामपंथियों पर यह आरोप भी लगाया कि उनके 34 सालों के शासन में राज्य में 72 हज़ार छोटी–बड़ी औद्योगिक इकाइयां बंद हुईं. सिर्फ हावड़ा में 12 हज़ार कल–कारखाने बंद हो गए. नतीजतन, बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन जब वाममोर्चा की सरकार ने नंदीग्राम और सिंगूर में उद्योग लगवाने की कोशिश की तो ममता बनर्जी ने इसका जमकर विरोध किया. इस मुद्दे पर कि किसानों से जबरन जमीन छीनी जा रही है. लेकिन अब ममता सत्ता में हैं और वामपंथी विपक्ष में. सवाल यह है कि अब ममता बंगाल में उद्योगपतियों को कैसे बुला पाएंगी, कैसे और किन नीतियों के आधार पर जमीन का अधिग्रहण करेंगी, क्या वह लगभग सवा सौ साल पुराने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव करने के लिए यूपीए सरकार पर दबाव बनाएंगी? दूसरी ओर, नक्सलवाद को लेकर तृणमूल का जो रुख रहा है और जिस तरह प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष तौर पर नक्सलवादियों ने तृणमूल का समर्थन किया है, उसे देखते हुए ममता बनर्जी के समक्ष इस समस्या का समाधान निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है. जाहिर है, यह मुद्दा भी तृणमूल के लिए एक भारी टास्क साबित होने वाला है. गौरतलब है कि जमीन पर अधिकार न होना और रोजगार के घटते अवसर जैसी वजहों ने भी नक्सल समस्या को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. ऐसे हालात में बंगाल के औद्योगिक विकास का खाका तैयार करना ममता बनर्जी के लिए दोधारी तलवार पर चलने जैसा होगा, क्योंकि यह मामला सीधे–सीधे रोजगार और जमीन से जुड़ा है और जनता इनमें से किसी एक को पाने के लिए दूसरे को खोना नहीं चाहेगी. इसके अलावा पश्चिम बंगाल के युवाओं की एक बड़ी संख्या (करोड़ों में) ने इस चुनाव में तृणमूल का समर्थन किया है. बेरोजगारी से त्रस्त इस युवा ऊर्जा का इस्तेमाल ममता बनर्जी कैसे करेंगी, कहां और किस रचनात्मक कार्य में? इस चुनाव में पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक समुदाय ने भी तृणमूल का आंख मूंदकर समर्थन किया है. यहां मुस्लिम आबादी लगभग 25 फीसदी से भी ज्यादा है, लेकिन उसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालत क्या है, यह सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट देखकर पता चल जाता है. सरकारी नौकरी में इस समुदाय की हिस्सेदारी महज 2.1 फीसदी है. ममता बनर्जी ने वैसे तो अपने घोषणापत्र में अल्पसंख्यकों के लिए नए मदरसों और एक विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के हित से जुड़े सबसे अहम मुद्दे यानी रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट पर तृणमूल का रुख अब तक साफ नहीं हो सका है. यह रिपोर्ट, अल्पसंख्यक समुदाय में भी जो वंचित तबका है, उसे शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात कहती है. यूपीए गठबंधन में शामिल तृणमूल कांग्रेस की ओर से अब तक इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू कराने के लिए न तो कोई दबाव बनाया गया और न कोई पहल होती दिखी. जाहिर है, तृणमूल को इस मसले पर अपना पक्ष साफ करना चाहिए. न सिर्फ इतना, बल्कि इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू कराने के लिए एक नई पहल भी करनी चाहिए.

तृणमूल ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि सत्ता में आने के सौ दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल में शासन–प्रशासन की कार्यप्रणाली बदल दी जाएगी और लोगों को अंतर दिखने लगेगा. इसके अलावा तृणमूल ने सत्ता मिलने के बाद अगले 200 दिनों का एजेंडा भी पहले से तय कर लिया था, जिसमें कोलकाता को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाने की योजना शामिल है. साथ ही नए मेडिकल कॉलेज, मदरसे, मुस्लिम विश्वविद्यालय, हिंदी स्कूल और 300 नए आईआईटी खोलने की बात है, दार्जिलिंग एवं जंगल महल के लिए विशेष विकास योजना बनाने की बात है, सार्वजनिक क्षेत्र के बंद कारखानों को फिर चालू करना और नए कारखाने खोलने की बात है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी ये सारे काम महज़ 200 दिनों के भीतर कर पाएंगी? क्योंकि विकास का जो खाका इस एजेंडे में दिख रहा है, उसके लिए एक बेहतर बुनियादी संरचना मसलन, बिजली, सड़क, बेहतर कानून–व्यवस्था की दरकार होगी. बिहार का उदाहरण बताता है कि नीतीश कुमार को सिर्फ सड़कों का जाल बिछाने में ही पांच साल लग गए. वह भी काम अभी अधूरा है. बिजली की स्थिति अभी भी बिहार में नहीं सुधर सकी है. कहने का मतलब यह कि एक बीमारू प्रदेश को फिर से पटरी पर लाने में काफी लंबा समय लगता है. ऐसे में ममता बनर्जी पर दबाव अधिक होगा.

जाहिर है, ममता बनर्जी को अपने पास उपलब्ध संसाधनों और विकास का जो स्वप्न उन्होंने जनता को दिखाया है, के बीच के गहरे अंतर का अंदाजा है. यही वजह है कि जब बात सरकार गठन और उसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस को निमंत्रण देने की आई, तो यह समझना मुश्किल नहीं था कि ममता ने यह कदम क्यों उठाया, क्योंकि वह उस अंतर को कम करने के लिए केंद्र सरकार यानी कांग्रेस की मदद भी चाहती हैं. बहरहाल, पश्चिम बंगाल की जनता को अब पोरिवर्तन का इंतजार है, जिसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी को निभानी है.

rajeshy@chauthiduniya.com

पश्चिम बंगाल
मतदाताओं की संख्या: 5.61 करोड़
मतदान का प्रतिशत: 84 फीसदी
प्रत्याशियों की संख्या: 1482

असम
मतदाताओं की संख्या: 1.81 करोड़
मतदान का प्रतिशत: 76 फीसदी
प्रत्याशियों की संख्या: 981

पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 25 फीसदी से भी ज्यादा है, लेकिन उसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालत क्या है, यह सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट देखकर पता चल जाता है. लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के हित से जुड़े सबसे अहम मुद्दे यानी रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट पर तृणमूल का रुख अब तक साफ नहीं हो सका है. यह रिपोर्ट, अल्पसंख्यक समुदाय में भी जो वंचित तबका है, उसे शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात कहती है.

गोगोई की जीत ने कांग्रेस की लाज रख ली

एस बिजेन सिंह

एक्जिट पोल से पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि असम में कांग्रेस को अपनी सरकार बचाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तरुण गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस आ गई. असम को लेकर एक सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि तरुण गोगोई तीसरी बार कांग्रेस को जिता ले गए. जबकि उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे थे और असम की जनता की समस्याएं भी अपनी जगह जस की तस मुंह बाए खड़ी थीं. दरअसल, गोगोई को जिस चीज का सबसे ज्यादा फायदा मिला, वह यह है कि असम में विपक्ष कहीं नहीं दिखा. अगर दिख भी रहा है तो बिखरा हुआ और असंगठित. चाहे वह असम गण परिषद हो या भारतीय जनता पार्टी. हां, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का प्रदर्शन ठीक रहा, लेकिन अंतत: एक मजबूत विपक्ष की कमी ने कांग्रेस को एक और मौका दे दिया. इस चुनाव परिणाम से असम गण परिषद काफी कुछ सीख सकता है. खासकर, प्रफुल्ल कुमार महंत. उन्होंने चुनाव से पूर्व एक महागठबंधन बनाने की कोशिश की थी, जो असफल साबित हुई. बहरहाल, कांग्रेस को जीत तो मिल गई, लेकिन अब उसे अपना ध्यान जनता की समस्याओं पर केंद्रित रखना होगा. घुसपैठ का मामला यहां हमेशा से विवाद और हिंसा का कारण बनता रहा है. इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति होती रही है. कांग्रेस पर तो यह आरोप भी लगता रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए उसका वोट बैंक हैं. इसके अलावा अल्पसंख्यकों की हालत भी दयनीय है. बाढ़ का मुद्दा ऐसा है, जिससे असम की जनता हर साल प्रभावित होती है. सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मनमोहन सिंह असम से ही राज्यसभा में आते हैं. ऐसे में असम की जनता को कांग्रेस से काफी उम्मीदें हैं, जिन्हें निश्चित तौर पर पूरा किया जाना चाहिए.

bijen@chauthiduniya.com

कहां-कहां कितनी सीटें

पश्चिम बंगाल
कुल सीटें–294

तृणमूल कांग्रेस	184
कांग्रेस	42
सीपीआई (एम)	40
सीपीआई	02
एआईएफबी	11
आरएसपी	07
सपा	01
अन्य	07

असम
कुल सीटें–126

कांग्रेस	78
एआईयूडीएफ	18
एजीपी	10
बीपीएफ	12
भाजपा	05
तृणमूल	01
अन्य	02

दरअसल, गोगोई को जिस चीज का सबसे ज्यादा फायदा मिला, वह यह है कि असम में विपक्ष कहीं नहीं दिखा. अगर दिख भी रहा है तो बिखरा हुआ और असंगठित. चाहे वह असम गण परिषद हो या भारतीय जनता पार्टी. हां, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का प्रदर्शन ठीक रहा, लेकिन अंतत: एक मजबूत विपक्ष की कमी ने कांग्रेस को एक और मौका दे दिया.

जनता जयललिता से कितनी उम्मीदें लगा कर बैठी है. भविष्य में जयललिता जनता के इस भरोसे को किस तरह टूटने से बचाती हैं, यह देखने की बात होगी.

केरल

कैसी जीत कैसी हार

यूडीएफ जीत तो गई है, लेकिन उसके सामने बहुत सी चुनौतियां है. सबसे पहली चुनौती है सरकार बनाने की. कांग्रेस के घटक दल उस पर दबाव बनाएंगे, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है. उधर कांग्रेस भी अंतर्कलह से जूझ रही है. अब चाहे ऊमेन चंडी या रमेश चेन्नीथाला मुख्यमंत्री बनें, लेकिन गठबंधन धर्म निभाने में कांग्रेस को ख़ासी मशक्कत करनी पड़ सकती है.

सिद्धार्थ राय

हाल में हुए विधानसभा चुनाव में केरल के लोगों ने फिर से साबित कर दिया कि वे अपने पुराने रवैये को भूले नहीं हैं. केरल हर पांच साल में सरकार में बदलाव देखता आ रहा है. इस बार भी ऐसा ही हुआ. वी एस अच्युतानंदन के नेतृत्व में मॉर्क्सवादी गठबंधन यानी एलडीएफ की हार तो हुई है, लेकिन कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी जीत नहीं कहा जा सकता. इस बार एलडीएफ 68 सीटों पर जीतने में कामयाब रहा, वहीं कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 72 सीटें मिली हैं, जो आम बहुमत से केवल एक सीट ज़्यादा है.

इस जीत से कांग्रेस को बहुत ख़ुश होने की ज़रूरत नहीं है और कांग्रेस के नेता भी इस बात को समझ रहे हैं. इतनी कम संख्या और बहुमत से केवल एक सीट अधिक होना कांग्रेस के लिए कांटों का ताज भी बन सकता है, जबकि अच्युतानंदन जैसे साफ़ छवि वाले नेता अब विपक्ष में बैठेंगे. अच्युतानंदन ने सरकार बनाने की कोई कोशिश न करते हुए विपक्ष संभालने की तैयारी कर ली है. वैसे कांग्रेस की इस जीत में उसके घटक दलों का बड़ा हाथ है, जबकि कांग्रेस का ख़ुद का प्रदर्शन अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसे केवल 23 सीटों पर ही जीत मिली है. इस गठबंधन केसबसे बड़े घटक दल मुस्लिम लीग का प्रदर्शन इस बार क़ाबिले तारीफ़ रहा है. उसने 24 सीटों पर लड़कर 20 सीटें हासिल की हैं.

यूडीएफ का प्रदर्शन इस बार मुस्लिम और ईसाई क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा रहा, जैसा कि चुनाव के पहले अटकलें लगाई जा रही थीं, मुसलमानों–ईसाइयों का एकतरफ़ा समर्थन कांग्रेस गठबंधन को मिला. याद रखने वाली बात यह है कि केरल में 44 फ़ीसदी मतदाता मुसलमान और ईसाई हैं, यानी 22–22 फ़ीसदी. ज़ाहिर है कि यदि मतदाताओं का इतना बड़ा तबका किसी भी पार्टी के पक्ष में एकतरफ़ा वोट देगा तो उसकी जीत सुनिश्चित हो ही जाएगी. इस बार के चुनाव में कांग्रेस को इसी का फ़ायदा मिला है, जैसे पिछली बार एलडीएफ को मिला था. वैसे कांग्रेस के पक्ष में मुसलमानों के रुझान को इस बात से भी समझा जा सकता है कि मुस्लिम लीग ने इस बार 20 सीटें जीतीं हैं. ईसाइयों ने भी कांग्रेस का खुला समर्थन किया है, क्योंकि अगर केरल कांग्रेस समिति को देखा जाए तो यहां कैथोलिक ईसाइयों का वर्चस्व है. यूडीएफ जीत तो गई है, लेकिन उसके सामने बहुत सी चुनौतियां है. सबसे पहली चुनौती है सरकार बनाने की. कांग्रेस के घटक दल उसपर दबाव बनाएंगे, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है. उधर कांग्रेस भी अंतर्कलह से जूझ रही है. अब चाहे ऊमेन चंडी या रमेश चेन्नीथाला मुख्यमंत्री बनें, लेकिन गठबंधन धर्म निभाने में कांग्रेस को ख़ासी मशक्कत करनी पड़ सकती है.

कुल सीटें 140

सीपीआई (एम)	– 45	केरल कांग्रेस (एम)	– 09
सीपीआई	– 13	मुस्लिम लीग	– 20
कांग्रेस	– 38	आरएसपी	– 02
राकांपा	– 02	अन्य	– 07
जनता दल सेकुलर	– 04		

वैसे भी कुछ दिनों पहले ही केरल कांग्रेस में अंतर्द्वंद ज़ोरों पर था और ए के एंटोनी की तमाम कोशिशों के बाद ही इसे ठंडे बस्ते में डाला जा सका. हो सकता है की यह जिन्न फिर बोतल से निकल आए. अब मुस्लिम जोकि कांग्रेस से बस 20 सीटें ही कम लाई हैं, वह अपना हिस्सा तो ज़ोर–शोर से मांगेगी ही. कांग्रेस का सरदर्द बढ़ाने वालों में सबसे बड़ा नाम केरल कांग्रेस के नेता के एम मणि का है. चुनाव से पहले ही उन्होंने दिखा दिया था की उनकी रुचि बस राजनीतिक लाभ में है न कि किसी भी तरीक़े के नैतिक या विचारधारात्मक लगाव में. जब चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा हो रहा था तब भी मणि ऐसा लगा की गठबंधन से रिश्ता तोड़ लेंगे. काफी प्रयासों के बाद ही मणि माने थे. अब जबकि उनकी पार्टी ने भी ठीक प्रदर्शन किया है और कांग्रेस की सीटों के मुक़ाबले उनकी भी सीटें मायने रखती हैं, तो यह अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि मणि कब तक कांग्रेस के वफ़ादार साथी बने रहेंगे. इन सारे अंतर्द्वंदों और तनावों को देखते हुए ऐसा लगता है कि गठबंधन धर्म के चलते केरल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार जम्बो कैबिनेट का निर्माण होगा. वैसे तो सीपीएम सबसे बड़े दल की तरह उभरा है, लेकिन इसमें भी इन चुनावों की वजह से बहुत सारे अंतर्द्वंद पैदा होने की उम्मीद लगाई जा सकती है. बात चाहे किसी भी दल की हो, लेकिन जीत में सब एक साथ होते हैं और हार में सब एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं. आपस के झगड़े तभी सतह पर आते हैं, जब हार का मुंह देखना पड़ता है. एलडीएफ के साथ कुछ ऐसा ही होने की संभावनाएं बन रही हैं. एलडीएफ के भविष्य का आकलन करते समय हमें याद रखना होगा कि मार्क्सवादियों को बंगाल में इतिहास का सबसे बड़ा झटका भी इसी चुनाव में लगा है. 34 साल के बाद लेफ्ट बंगाल को खो चुका है. एलडीएफ में दो धड़े हैं. एक के नेता हैं सीपीएम के पिनाराई विजयन और दूसरे के अच्युतानंदन. इन दोनों में छत्तीस का आंकड़ा है. इनके बीच का दुराव अब नए मोड़ पर जा सकता है, क्योंकि जहां अच्युतानंदन के गढ़ अलापुज़ा में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं पार्टी पिनाराई विजयन के गढ़ पलक्कड़ और कन्नूर में मटियामेट हो गई है. अच्युतानंदन इस मौक़े को शायद गवाएंगे नहीं. यह लड़ाई दिल्ली तक भी ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि विजयन के सरपरस्त प्रकाश करात पहले ही पश्चिम बंगाल में हुई ऐतिहासिक हार के लिए बहुत दबाव में हैं. यह तो ज़ाहिर है कि केरल सीपीएम में समीकरणों का बदलाव होगा और शायद अच्युतानंदन इस मौक़े का फ़ायदा उठा कर एक बार फिर पोलित–ब्यूरो में वापसी करेंगे. संक्रमण काल में बदलाव तो होते ही हैं. केरल के लिए आगामी साल कठिन साबित होंगे और उम्मीद है कि यहां की राजनीति शांत नहीं रहने वाली. अच्युतानंदन और सीपीएम अब विपक्ष में बैठे होंगे और मार्क्सवादी विपक्ष का मतलब हड़ताल और चक्का जाम ज़रूर होता है. ऐसा तब जबकि अच्युतानंदन ने कहा है कि वह अपनी कांग्रेस के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की जंग जारी रखेंगे. अब देखना यह है कि कांग्रेस अपने छोटे से बहुमत को कैसे फलित करती है और मार्क्सवादी गठबंधन अपनी नई भूमिका कैसे निभाता है.

रंगास्वामी जनता का नया हीरो

पुदुचेरी में कांग्रेस गठबंधन को ग़ज़ब का झटका लगा है. कांग्रेस को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इन चुनावों से कुछ दिनों पहले ही उससे अलग हुए एन रंगास्वामी ने एआईएडीएमके केसाथ मिल कर पुदुचेरी में एक तरह से एकाधिकार कर लिया है. याद रखने वाली बात यह है की एन रंगास्वामी पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं. कुल तीस सीटों में से रंगास्वामी के ऑल इंडिया एन आर कांग्रेस गठबंधन ने 20 सीटें जीत ली हैं और इस तरह कांग्रेस का पुदुचेरी में पिछले 12 साल का एकछत्र राज ख़त्म हो गया है. रामासामी की पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उसे 15 सीटों पर कामयाबी मिली है. एआईएडीएमके ने दस सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमे उसे 5 सीटें मिली हैं. लेकिन इस गठबंधन के दूसरे घटक यानी डीएमडीकेऔर सीपीआई को कोई सीट नहीं मिली. वहीं कांग्रेस को 17 सीटों में से बस 9 सीटें ही मिल पाईं. डीएमके को भी मुंह की खानी पड़ी और उसे 10 में से मात्र 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है. पीएमके, जिसने इस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, वह अपना खाता भी नहीं खोल पाई. यह चुनाव कांग्रेस और मित्र दलों केलिए बहुत सफल साबित नहीं हुआ है. बंगाल की सफलता कांग्रेस की नहीं बल्कि ममता की है और जहां भी कांग्रेस ने अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, वहां से उसे मन मुताबिक़ सफलता हासिल नहीं हुई है. शायद समय आ गया है की कांग्रेस संभल जाए, नहीं तो उसे अगले आम चुनावों में भी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ सकता है.

कुल सीटें – 30

ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस	– 15
कांग्रेस	– 07
एआईएडीएमके	– 05
डीएमके	– 02
अन्य	– 01

पुदुचेरी

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

भ्रष्टाचार पर जनता का क़हर बरपा

तमिलनाडु

महेंद्र अवधेश

तमिलनाडु में जनता ने करुणानिधि और कांग्रेस गठजोड़ को एक सिरे से नकार दिया है. डीएमके की यह 1991 के बाद अब तक की सबसे बुरी हार है, जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी. यह डीएमके के 1967 से अब तक के राजनीतिक इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा झटका है. स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि राज्य के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अनबढ़घन हार गए और उप मुख्यमंत्री एम के स्टालिन बस 2400 वोटों से अपनी साख बचा पाए. वैसे करुणानिधि ने अपने पैतृक स्थान से बारहवीं बार जीत कर रिकॉर्ड स्थापित तो किया, लेकिन उनकी इस जीत का कोई मतलब नहीं रह गया. डीएमके खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच गई. दूसरे स्थान पर हीरो विजयकांत की डीएमडीके रही, जिसे इस बार 29 सीटें हासिल हुई हैं और जिसकी पिछली बार बस एक सीट पर जीत हुई थी. कांग्रेस की भी मिट्टी पलीद हो गई है. 63 सीटों पर लड़ी कांग्रेस की झोली में बस 5 सीटें ही आई हैं. जनता का आक्रोश इस बात से देखा जा सकता है की राज्य के 29 मंत्रियों में से 18 मंत्री अपनी सीट गवां बैठे हैं. जयललिता की जीत में डीएमके गठबंधन का ही सबसे बड़ा हाथ है. जयललिता ने यह चुनाव जहां एक ओर राज्य में करुणानिधि के परिवारवाद के विरोध में लड़ा वहीं राष्ट्रीय स्तर पर डीएमके की 2–जी स्पेक्ट्रम मसले में हुई फ़ज़ीहत को भी बड़ा मुद्दा बनाया. जयललिता के इस दोहरे वार का सबब साफ़ दिख रहा है. जहां एक ओर शहरी जनता को करुणानिधि के परिवार का 2–जी घोटाले में लिप्त होना नागवार गुज़रा, वहीं ग्रामीण जनता के साथ करुणानिधि के परिवारवाद का मुद्दा सफल रहा. करुणानिधि ने तमिलनाडु को अपनी मिल्कियत समझ लिया था और इसका ख़ामियाज़ा उन्हें भुगतना पड़ा है. साथ ही वह कांग्रेस को भी अपने साथ ले डूबे हैं. चुनाव प्रचार के समय करुणानिधि–कांग्रेस गठबंधन ने जनता को मुफ्त में घर के सामान बांट कर लुभाने की कोशिश की थी. इसके पीछे सोच यह थी कि जनता को करुणानिधि और उनके परिवार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका घर तो भर ही रहा है. लेकिन इस मामले में जनता की राजनीतिक बुद्धिमत्ता को सलाम करना चाहिए कि उसने इस सोच को ग़लत साबित कर दिया. वैसे जयललिता को भी यह समझना होगा कि जिस तरह से करुणानिधि को जनता ने अपनी नज़रों से बिल्कुल उतार दिया है वैसे ही आने वाले समय में यदि उन्होंने जनता के हितों के लिए काम नहीं किया तो जनता उनको भी नहीं बख़्शेगी. इतने बड़ी जीत का मतलब यह भी है कि जनता जयललिता से कितनी उम्मीदें लगा कर बैठी है. वैसे उन्होंने कहा तो है कि वह अपने सारे वायदे बस डेढ़ साल में पूरे करेंगी, लेकिन भविष्य में जयललिता जनता के इस भरोसे को किस तरह टूटने से बचाती हैं, यह देखने की बात होगी.

कुल सीटें –234

एआईएडीएमके	– 150
डीएमके	– 23
सीपीआई	– 09
सीपीआई (एम)	– 10
कांग्रेस	– 05
फॉरवर्ड ब्लॉक	– 01
पीएमके	– 03
अन्य	– 33

जहां एक ओर शहरी जनता को करुणानिधि के परिवार का 2-जी घोटाले में लिप्त होना नागवार गुज़रा, वहीं ग्रामीण जनता के साथ करुणानिधि के परिवारवाद का मुद्दा सफल रहा. करुणानिधि ने तमिलनाडु को अपनी मिल्कियत समझ लिया था और इसका ख़ामियाज़ा उन्हें भुगतना पड़ा है. साथ ही वह कांग्रेस को भी अपने साथ ले डूबे हैं.

m_awdhesh@chauthiduniya.com

सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने अगस्त 2010 में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के सचिव को पत्र के माध्यम से एडसिल में होने वाली नियुक्ति में बरती गई अनियमितता के संबंध में सूचित किया.

एडसिल के सीएमडी की नियुक्ति का मामला

सिब्बल जी, यह भी भ्रष्टाचार है

शशि शेखर

लोकपाल विधेयक बनाने के लिए गठित ज्वाइंट ड्राफ्ट कमेटी में सरकारी नुमाइंदे के तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल भी शामिल हैं. यह कमेटी एक ऐसी संस्था के गठन का रास्ता निकाल रही है, जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके. लेकिन इसे दुर्भाग्य कहिए या संयोग, ख़ुद सिब्बल के मंत्रालय में जो कुछ हो रहा है, उससे यह साफ–साफ दिख रहा है कि चिराग तले अंधेरा कैसे होता है. चौथी दुनिया की पड़ताल से पता चलता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एक बार फिर एक महत्वपूर्ण संस्था में उच्च पद पर नियुक्ति को लेकर तमाम नियम–क़ानूनों को ताख पर रखा गया. ग़ौरतलब है कि चौथी दुनिया ने पहले भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति दीपक पेंटल की नियुक्ति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पक्षपाती रवैये का खुलासा किया था. वर्तमान मामले में भी कुछ–कुछ वैसा ही किया जा रहा है, जैसे कुलपति की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति के असफल प्रयास के समय किया गया था.

बहरहाल, यह मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एडसिल (ईडीसीआईएल) यानी एजूकेशनल कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड के सीएमडी (चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर) की नियुक्ति का है. दरअसल, अंजू बनर्जी को एक बार फिर से 5 साल के लिए एडसिल का सीएमडी नियुक्त किया गया है. चौथी दुनिया की तहकीकात से यह तथ्य सामने आया है कि पिछले कार्यकाल के दौरान अंजू बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे. यहां तक कि उनकी नियुक्ति की वैधता को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए थे. मसलन, नियम के मुताबिक़, सार्वजनिक क्षेत्र की किसी भी इकाई में उच्च पदों पर होने वाली नियुक्ति के पुष्टिकरण/स्वीकृति का काम पीएसईबी यानी पब्लिक इंटरप्राइजेज सेलेक्शन बोर्ड करता है. नियम के मुताबिक़, एक साल की अवधि पूरी होने पर उस नियुक्ति का पुष्टिकरण आवश्यक होता है. पीएसईबी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो इस तरह की नियुक्तियों का काम देखती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ. चौथी दुनिया के पास उपलब्ध मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के दस्तावेजों में यह साफ–साफ लिखा हुआ है कि 2005 में अंजू बनर्जी को एडसिल का सीएमडी नियुक्त किया गया, लेकिन एक साल की अवधि ख़त्म होने के बावजूद उनकी नियुक्ति का पुष्टिकरण पीएसईबी ने नहीं किया.

क्या है एडसिल

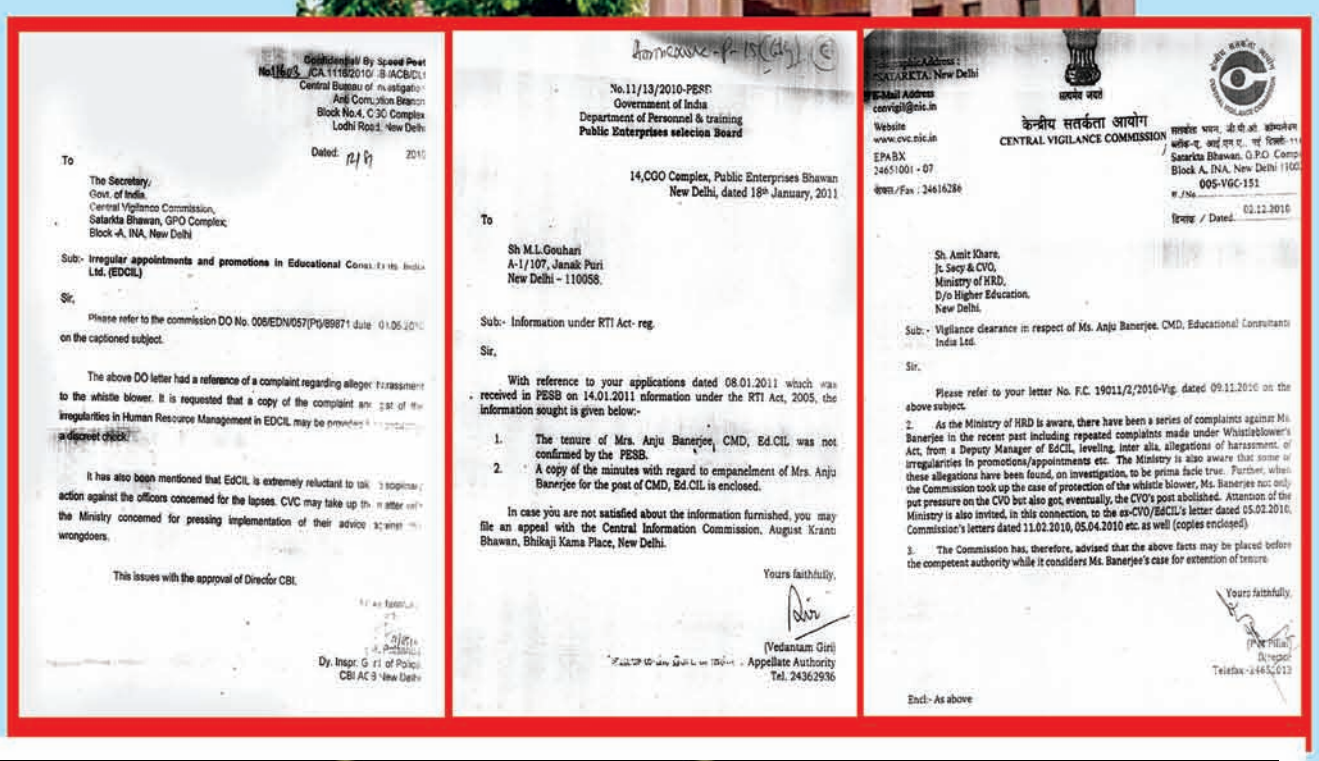

वर्ष 1981 में भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में एजूकेशनल कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी. पहले शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय, फिर 1985 में इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कर दिया गया. एडसिल इंडिया लिमिटेड शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत ही नहीं, बल्कि भारत से बाहर भी, ख़ासकर एशिया और अफ्रीकी देशों में अपनी सेवाएं यानी सलाह देने का काम करती है. इस संस्था पर ज़िम्मेदारी तो है देश के लिए एक बेहतर वर्क फोर्स तैयार करने की, लेकिन जिस तरह यह संस्था ख़ुद अनियमितताओं के जाल में फंसी हुई है, उससे तो यही लगता है कि यह महज़ एक सफेद हाथी बनकर रह गई है.

सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने अगस्त 2010 में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के सचिव को पत्र के माध्यम से एडसिल में होने वाली नियुक्ति में बरती गई अनियमितता के संबंध में सूचित किया. एडसिल एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने बनर्जी के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला भी दायर किया था. 2005 में सीएमडी नियुक्त किए जाने के 5 साल बाद जब 2010 में बनर्जी का कार्यकल ख़त्म हुआ, तब मंत्रालय ने पहले तो उन्हें 3 महीने का सेवा विस्तार दिया, जिस पर सीवीसी ने अपना एतराज भी दर्ज कराया था. फिर इसके बाद पुन: उन्हें 2015 तक के लिए सीएमडी नियुक्त कर दिया गया. मंत्रालय ने बनर्जी के ख़िलाफ़ लगे आरोपों की न तो जांच कराई और न ज़रूरी नियम–क़ानूनों का पालन किया.

चौथी दुनिया के पास सीवीसी का वह पत्र है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव सह मुख्य सतर्कता अधिकारी को दिसंबर 2010 में लिखा गया. इस पत्र में अंजू बनर्जी को सेवा विस्तार दिए जाने के लिए आवश्यक विजिलेंस क्लियरेंस से संबंधित मसले पर सीवीसी की तरफ़ से साफ–साफ कहा गया है, जैसा कि मंत्रालय को पता है कि अब तक अंजू बनर्जी के ख़िलाफ़ शिकायतों की एक लंबी सूची है, जिसमें व्हिसल ब्लोअर एक्ट के तहत भी एडसिल के एक डिप्टी मैनेजर की तरफ़ से शिकायत है. साथ ही बनर्जी पर एडसिल के भीतर नियुक्ति एवं पदोन्नति में पक्षपात एवं उत्पीड़न के भी आरोप हैं. पत्र में साफ तौर पर बताया गया है कि इनमें से कई आरोप जांच के बाद प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं. इसके आगे पत्र में यह भी लिखा है कि जब केंद्रीय सतर्कता आयोग ने व्हिसल ब्लोअर (भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति) की सुरक्षा का मामला संज्ञान में लिया, तब अंजू बनर्जी ने पहले तो मुख्य सतर्कता अधिकारी (एडसिल) पर दबाव बनाया और अंतत: सीवीओ का पद ही ख़त्म करा दिया. सीवीसी ने इस संबंध में मंत्रालय को एडसिल के सीवीओ की ओर से लिखे गए पत्र पर ध्यान देने की सलाह भी दी है. अंत में पत्र में सीवीसी ने मंत्रालय को यह सलाह दी है कि वह अंजू बनर्जी को सेवा विस्तार देने के लिए ज़िम्मेदार सक्षम प्राधिकार के समक्ष इन सभी तथ्यों को रखे और तब इस संबंध में कोई फ़ैसला ले. लेकिन, मंत्रालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के इस पत्र पर ध्यान न देते हुए अंजू बनर्जी को पुन: एडसिल का सीएमडी नियुक्त कर दिया. अब सवाल उठता है कि क्या अनियमित रूप से की गई इस नियुक्ति की जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को नहीं है? और अगर है तो फिर उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पद के लिए देश में अन्य कोई सक्षम उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाया या यह देश प्रतिभाविहीन हो चुका है या फिर कुछ और मामला है? बहरहाल, मानव संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में कपिल सिब्बल जैसे विधिवेत्ता मंत्री के रहते हुए इस तरह की नियुक्ति भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है?

shashishekhar@chauthiduniya.com

Confidential/ By Speed Post
No.1603 /CA 1116/2010/ B/ACB/DLI
Central Bureau of Investigation
Anti Corruption Branch
Block No.4, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi

Dated: 12/8 2010

To

The Secretary,
Govt. of India,
Central Vigilance Commission,
Satarkta Bhawan, GPO Complex,
Block-A, INA, New Delhi

Sub:- Irregular appointments and promotions in Educational Consultants India Ltd. (EDCIL)

Sir,

Please refer to the commission DO No. 006/EDN/057(Pt)/89871 date 01.06.2010 on the captioned subject.

The above DO letter had a reference of a complaint regarding alleged harassment to the whistle blower. It is requested that a copy of the complaint and list of the irregularities in Human Resource Management in EDCIL may be provided ... a discreet check.

It has also been mentioned that EdCIL is extremely reluctant to take ... action against the officers concerned for the lapses. CVC may take up the matter with the Ministry concerned for pressing implementation of their advice against the wrongdoers.

This issues with the approval of Director CBI.

Dy. Inspr. G... of Police
CBI ACB New Delhi

No.11/13/2010-PESB
Government of India
Department of Personnel & training
Public Enterprises selecion Board

14,CGO Complex, Public Enterprises Bhawan
New Delhi, dated 18th January, 2011

To

Sh M.L.Gouhari
A-1/107, Janak Puri
New Delhi – 110058.

Sub:- Information under RTI Act- reg.

Sir,

With reference to your applications dated 08.01.2011 which was received in PESB on 14.01.2011 nformation under the RTI Act, 2005, the information sought is given below:-

1. The tenure of Mrs. Anju Banerjee, CMD, Ed.CIL was not confirmed by the PESB.
2. A copy of the minutes with regard to empanelment of Mrs. Anju Banerjee for the post of CMD, Ed.CIL is enclosed.

In case you are not satisfied about the information furnished, you may file an appeal with the Central Information Commission, August Kranti Bhawan, Bhikaji Kama Place, New Delhi.

Yours faithfully,

(Vedantam Giri)
Appellate Authority
Tel. 24362936

Telegraphic Address: "SATARKTA: New Delhi
E-Mail Address convigil@nic.in
Website www.cvc.nic.in
EPABX 24651001 - 07
फैक्स/Fax : 24616286

सत्यमेव जयते
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

Satarkta Bhawan, G.P.O Complex, Block A, INA, New Delhi
005-VGC-151
दिनांक / Dated: 02.12.2010

Sh. Amit Khare,
Jt. Secy & CVO,
Ministry of HRD,
D/o Higher Education,
New Delhi.

Sub: - Vigilance clearance in respect of Ms. Anju Banerjee, CMD, Educational Consultants India Ltd.

Sir,

Please refer to your letter No. F.C. 19011/2/2010-Vig. dated 09.11.2010 on the above subject.

2. As the Ministry of HRD is aware, there have been a series of complaints against Ms. Banerjee in the recent past including repeated complaints made under Whistleblower's Act, from a Deputy Manager of EdCIL, leveling, inter alia, allegations of harassment, of irregularities in promotions/appointments etc. The Ministry is also aware that some of these allegations have been found, on investigation, to be prima facie true. Further, when the Commission took up the case of protection of the whistle blower, Ms. Banerjee not only put pressure on the CVO but also got, eventually, the CVO's post abolished. Attention of the Ministry is also invited, in this connection, to the ex-CVO/EdCIL's letter dated 05.02.2010, Commission's letters dated 11.02.2010, 05.04.2010 etc. as well (copies enclosed).

3. The Commission has, therefore, advised that the above facts may be placed before the competent authority while it considers Ms. Banerjee's case for extention of tenure.

Yours faithfully,

(P... Pillai)
Director
Telefax-2465...

Encl:- As above

मेरी दुनिया.... असली नकली

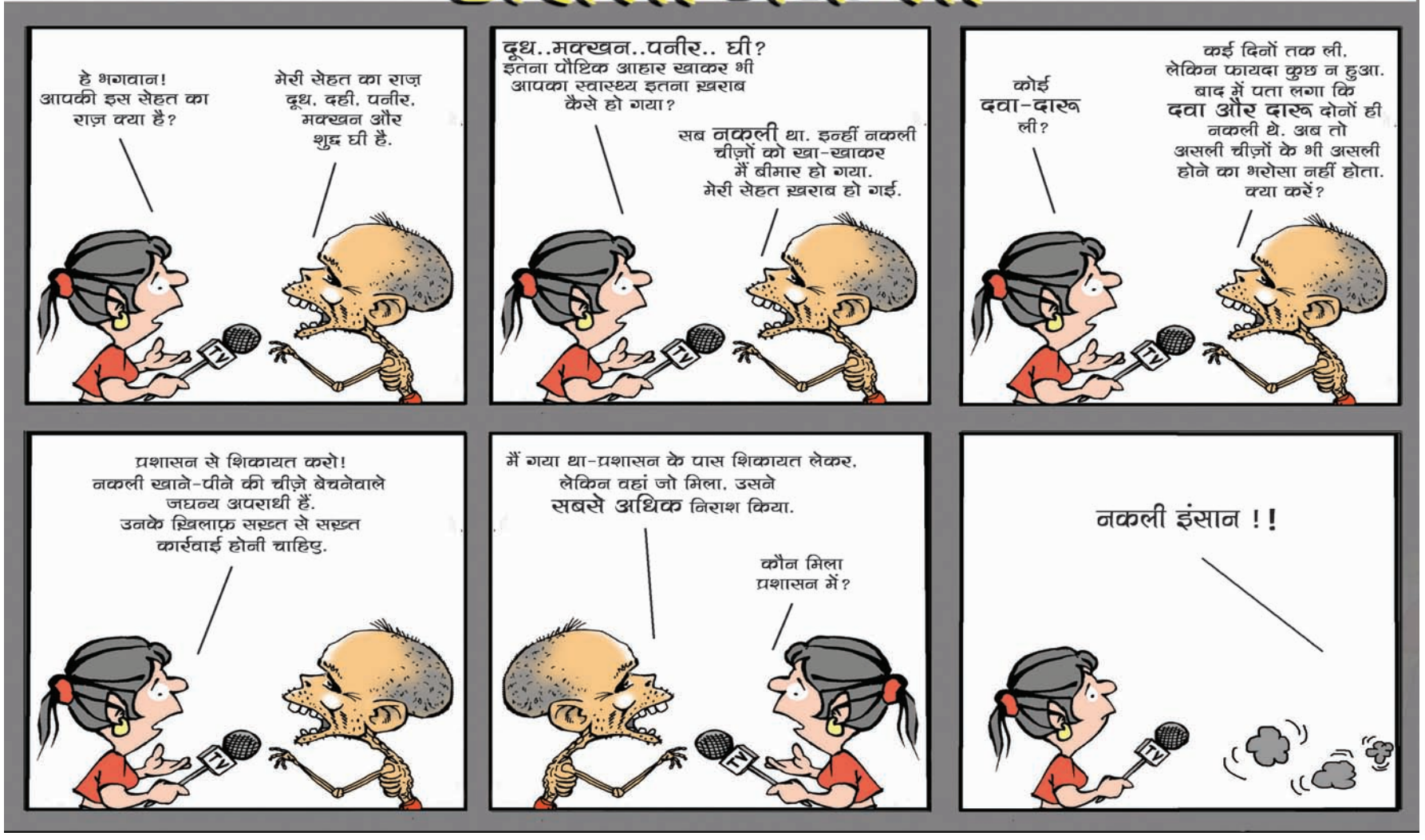

केंद्र की यूपीए सरकार ने बीते अप्रैल माह में महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले के जैतापुर इलाक़े में परमाणु संयंत्र को मंज़ूरी दी. हालांकि इसका भारी विरोध किया गया, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी और दो टूक कह दिया कि यह योजना बदस्तूर जारी रहेगी.

सिर्फ़ नोएडा नहीं पूरे देश के किसान हिंसक हो सकते हैं

फ़िरदौस ख़ान

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की नीतियां कुछ और हैं और राहुल गांधी कुछ और बात करते हैं. सरकार भूमि अधिग्रहण से संबंधित वर्षों पुराने कानून में संशोधन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाती और राहुल गांधी उसी कानून के तहत होने वाले भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हैं, लेकिन सिर्फ वहीं, जहां गैर कांग्रेसी दलों की सरकार है. यही रवैया उन्होंने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हुए भूमि अधिग्रहण मामले में अख्तियार किया. गौतमबुद्ध नगर के गांव भट्टा में भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे किसानों पर फायरिंग होती है, किसान मरते हैं, औरतें विधवा होती हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, लेकिन राहुल गांधी उनकी ख़बर लेने नहीं जाते. मगर जैसे ही हालात सुधरने लगते हैं और धारा-144 हटा ली जाती है, वह फ़ौरन मोटरसाइकिल द्वारा भट्टा गांव पहुंच जाते हैं, मानो आग ठंडी होने का इंतज़ार कर रहे हों और फिर राख के ढेर से चिंगारी तलाश कर उसे भड़काने की फ़िराक में हों, जिस पर वह अपनी सियासी रोटियां सेंक सकें. राहुल भट्टा गांव में घर-घर जाते हैं. रोती-बिलखती महिलाओं एवं बच्चों से मिलकर उन्हें सांत्वना देते हैं, उनके दु:ख-दर्द बांटने की कोशिश करते नज़र आते हैं. वह किसानों की मांगों के समर्थन में धरने पर भी बैठ जाते हैं और मीडिया में सुर्ख़ियां बटोरने में कामयाब हो जाते हैं. टीवी चैनलों से लेकर अख़बारों तक सिर्फ राहुल की तस्वीरें और उन्हीं के चर्चे हैं. राहुल किससे मिले, क्या कहा, क्या खाया, क्या पिया, वग़ैरह-वग़ैरह. यह तस्वीर का एक पहलू है. दरअसल, राहुल गांधी सिर्फ़ प्रचार के भूखे हैं और वह किसी भी तरह सिर्फ़ प्रचार चाहते हैं. अगर वाक़ई वह किसानों के सच्चे हितैषी होते तो गांव भट्टा जाने के बजाय सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय जाते और भूमि अधिग्रहण क़ानून के संशोधित विधेयक को पारित कराते, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया.

केंद्र की यूपीए सरकार ने बीते अप्रैल माह में महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले के जैतापुर इलाक़े में परमाणु संयंत्र को मंज़ूरी दी. हालांकि इसका भारी विरोध किया गया, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी और दो टूक कह दिया कि यह योजना बदस्तूर जारी रहेगी. राहुल गांधी वहां नहीं गए, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है. इसी तरह पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा समूह के नैनो कारखाने का विरोध करने वाले किसानों पर लाठियां भांजी गईं, महिलाओं पर भी डंडे बरसाए गए, लेकिन वहां भी राहुल गांधी नहीं आए, क्योंकि वहां यूपीए में शामिल वामपंथियों की सरकार थी. महाराष्ट्र सरकार ने दिसंबर 2007 में इंडिया बुल्स को अमरावती में सोफिया पावर प्लांट लगाने की मंज़ूरी दी. साथ ही 87 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पावर प्लांट को देने का फ़ैसला किया. हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2003 में विदर्भ में स्वीकार किया था कि पानी की कमी की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं. बावजूद इसके राज्य सरकार ने किसानों से उनके हक़ का पानी छीनने का काम किया. वहां के किसान कराह उठे, लेकिन राहुल गांधी वहां भी नहीं गए. उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती का यह कहना सही है कि राहुल को भूमि अधिग्रहण को लेकर जो भी लड़ाई लड़नी है, वह सबसे पहले केंद्र सरकार से लड़नी होगी, क्योंकि यह केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह भूमि अधिग्रहण से संबंधित संशोधित विधेयक को पारित कराए. हैरानी की बात है कि कांग्रेस की देखादेखी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी मायावती सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया. वे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन भूमि अधिग्रहण क़ानून के संशोधन के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं हैं. भाजपा के नेतृत्व में एनडीए ने भी केंद्र में शासन किया, लेकिन भाजपा ने भूमि अधिग्रहण क़ानून बदलने के बारे में नहीं सोचा. इसी तरह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह को किसानों के हितों का ख्याल नहीं आया. भूमि अधिग्रहण के मामले में मायावती सरकार को किसी भी लिहाज़ से ग़लत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह तो क़ानून के तहत ही कार्य कर रही है. मायावती का कहना है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर नई नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी गई, लेकिन केंद्र ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया. हालांकि ग्रेटर नोएडा में खूनखराबा होने के बाद प्रधानमंत्री अगले सत्र में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लाने की बात कर रहे हैं.

भूमि अधिग्रहण को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में ख़ूनी संघर्ष होते रहे हैं. उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री मायावती के गांव बादलपुर से ही हुई थी. यहां भी किसानों और महिलाओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थीं. इसी तरह गांव धूम मानिकपुर, बढ़पुरा, रानोली लतीफपुर एवं बिसाहड़ा के किसानों पर भी लाठियां भांजी गईं. घोड़ी बछेड़ी में पुलिस ने सात किसानों को गोलियों से भून डाला. इसके बाद गांव साखीपुर, डाढा, बख्तावरपुर, गढ़ी चौखंडी और टप्पल में भी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे किसानों पर ज़ुल्म किए गए. भट्टा में किसानों द्वारा गोलीबारी किए जाने से यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या यह सब पूर्व नियोजित था, क्योंकि किसानों के पास काफ़ी मात्रा में हथियार थे. बताया गया कि ये हथियार क़रीब दो माह पहले अलीगढ़, खुर्जा, बुलंदशहर और पड़ोसी राज्य हरियाणा से मंगाए गए थे. कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान आंदोलन की आड़ में प्रदेश में माओवाद पांव पसार रहा है. किसानों ने रोडवेज कर्मचारियों को बंधक बनाया और उन्हें छुड़ाने गए जिलाधिकारी पर गोली चलाई, दो पुलिसकर्मियों को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. ऐसे कारनामे तो माओवादी ही अंजाम देते रहे हैं. भट्टा के बाशिंदे इस बात को क़ुबूल करते हैं कि धरने में कुछ ऐसे बाहरी लोग भी शामिल थे, जिन्हें उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था. वे कहते हैं कि हम तो खेतीबाड़ी करने वाले मामूली किसान हैं, भला हम क्या जानें कि बंदूक़ कैसे चलाई जाती है. उनका आरोप है कि पुलिस ने निहत्थे ग्रामीणों पर गोलियां चलाईं और उनकी लाशों को जला दिया, ताकि कोई सबूत ही न बचे. कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब सरकार को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा हो. मुख्यमंत्री मायावती का कहना है कि कुछ पार्टियों ने साज़िश के तहत अराजक तत्वों को हथियार देकर भट्टा पारसौल में क़ानून व्यवस्था की स्थिति ख़राब कराई. राहुल गांधी के भट्टा आने से एक दिन पहले गांव की कुछ महिलाओं ने कहा कि वे चाहती हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए, क्योंकि कांग्रेस के शासन में किसानों पर ज़ुल्म नहीं होते, जबकि मायावती सरकार उनकी ज़मीनें छीन रही है और विरोध करने पर गोलियां चलाती है. जब उन्हें यह बताया जाता है कि क़ानून के तहत ही भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता.

पुलिस की गोली का शिकार हुए राजपाल की पत्नी ओमवती बताती हैं कि राजपाल धरने में पानी पिलाते थे. जब वह शाम को अपने खेत से लौट रहे थे, तब पुलिस ने उन पर गोली चलाई, जो पैर में लगी और वह गिर गए. इसके बाद पुलिस ने पीछे से उनके सिर और पेट में गोलियां मारीं. पुलिस वाले लाश भी उठाकर ले गए. बीस वर्षीय चीनू के घर भी पुलिस ने धावा बोला और उसके पिता कैलाश, छोटे भाइयों अमित और अंकित के साथ पहले मारपीट की और फिर उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले गई. जब उसने अपने भाइयों को बचाने की कोशिश की तो पुलिस ने उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया और उसे लाठी से पीटा.

इलाज के अभाव में वह तड़पती रही. उसकी मां बबीता का कहना है कि गांव में डॉक्टरों की टीम आई थी, लेकिन पुलिस ने उसे भगा दिया. जुबैदा के 16 वर्षीय अनाथ भतीजे इकराम को भी पुलिस उठाकर ले गई. 10 वर्षीय पूजा ने बताया कि पुलिस ने उसे भी डंडा मारा और उसके पिता शिवकुमार, मां कांति शर्मा और बहन नेहा को बुरी तरह पीटा. सभी परिवारीजन अस्पताल में दाख़िल हैं. बुज़ुर्ग बिरला का कहना है कि पुलिस ने उनके घर में घुसकर गाली-गलौच की और उन्हें पीटा. इतना ही नहीं, पुलिस ने उनके अपाहिज बेटे कपिल को भी कमरे से बाहर निकलने को कहा. जब वह बाहर नहीं आया तो उसे भी डंडे मारे गए. बुज़ुर्ग रिछपाल बताते हैं कि गांव में गिनती के कुछ वृद्धजन ही बचे हैं. बाक़ी कहां हैं, कोई नहीं जानता. दया, लज्जा, शोभा, जसपाल, महेंद्री, दुर्गा, मुन्नी, रिंकी, पिंकी आदि महिलाएं सवाल करती हैं कि उनके परिवारीजन कब वापस आएंगे, क्या वे ज़िंदा हैं या पुलिस ने उन्हें भी मार डाला.

गांववासी रतन सिंह कहते हैं कि उनकी 16 बीघा ज़मीन अधिग्रहीत की गई है, जिसकी क़ीमत सात लाख 42 हज़ार रुपये लगाई गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने मुआवज़ा नहीं लिया है. उन्होंने ख़ुद को धरने से अलग रखा और वह मुआवज़े की रक़म से संतुष्ट हैं. उनका कहना है कि पुलिस ने उन लोगों को भी पीटा, जो धरने में शामिल नहीं थे. उनके भाई सुरेश के हाथ-पैर तोड़ दिए गए. गांव के मास्टर धर्मवीर को भी बुरी तरह पीटा गया. दोनों अस्पताल में दाख़िल हैं. इसी गांव की 28 वर्षीय बाला देवी अपने पिता अतर सिंह और माता सोराजो के साथ धरने में गई थीं, जो अभी तक नहीं लौटीं. कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनकी हत्या कर दी. बाला देवी महिलाओं को इकट्ठा करके धरने में ले जाती थीं. किसानों की मांग है कि उनकी कुल भूमि में से सिर्फ़ आधी का ही अधिग्रहण किया जाए और बाक़ी विकास के बाद उन्हें वापस कर दी जाए. वे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे की हाउसिंग स्कीमों में 25 फ़ीसदी आरक्षण भी चाहते हैं. इसके अलावा वे भूमिहीन किसानों के लिए 120 वर्ग मीटर का प्लॉट और मुआवज़े के तौर पर पांच लाख रुपये मांग रहे हैं. उनकी यह भी मांग है कि भूमि का अधिग्रहण तब तक न किया जाए, जब तक भूमि अधिग्रहण से संबंधित मौजूदा अधिनियम की जगह नया क़ानून नहीं आ जाता. किसानों ने अधिग्रहण से पहले रोज़गार की गारंटी देने की मांग करते हुए कहा कि एक बार ज़मीन अधिग्रहीत हो जाने के बाद नई पीढ़ी बेरोज़गार हो जाएगी. इसलिए यह सुनिश्चित करना सरकार का काम है कि जिस किसान की ज़मीन चली जाए, उसके बच्चों को रोज़गार मिले. किसानों ने आबादी का अधिग्रहण पूरी तरह से बंद करने की मांग करते हुए कहा कि किसानों के खाते के बजाय परिवार के हिसाब से 3000 वर्ग मीटर ज़मीन छोड़ी जानी चाहिए. साथ ही इस ज़मीन पर किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए.

समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी का कहना है कि किसानों को सिर्फ़ 550 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है, जबकि बिचौलिए सात हज़ार रुपये प्रति वर्ग मीटर की रिश्वत लेकर इसे बिल्डरों को दे रहे हैं और बिल्डर इसी ज़मीन को 20 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बेचकर चांदी कूट रहे हैं. भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ देश में कई बार ख़ूनख़राबा हो चुका है. पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम कांड को लोग अभी तक भूले नहीं हैं. मौजूदा भूमि अधिग्रहण क़ानून 1894 अंग्रेज़ी शासनकाल में लागू किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से यही अभी तक चल रहा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी इसे अप्रासंगिक क़रार दे चुका है. इसके बावजूद केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण से संबंधित संशोधित विधेयक अभी तक संसद में पेश नहीं कर पाई है. मालूम हो कि 165 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेस-वे के ज़रिए नोएडा से आगरा तक की दूरी महज़ डेढ़ घंटे में तय कर ली जाएगी. 2500 करोड़ की इस योजना के तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा के क़रीब 334 गांवों की ज़मीन अधिग्रहीत की जानी है. इसके अलावा इस हाईवे के समीपवर्ती पांच स्थानों पर टाउनशिप और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाने हैं. यह अधिग्रहण जेपी ग्रुप, मोंटी चड्ढा और अन्य बिल्डरों के लिए किया जा रहा है. 1966 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता ने दिल्ली से सटे इस इलाक़े में फिल्म नगरी बसाने का ख्वाब संजोया. उन्होंने इसके लिए एक योजना भी बना डाली और इसे सूर्यनगर नाम दिया गया. जाने-माने अभिनेता स्वर्गीय सुनील दत्त से इसका उद्घाटन कराया गया, लेकिन यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई. इसके बाद नारायण दत्त तिवारी ने इसे नोएडा नाम देकर औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित किया. अब यह इलाक़ा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बराबरी कर रहा है.

चौथी दुनिया की राहुल गांधी से मांग है कि वह यूपीए सरकार के शासनकाल में अधिग्रहीत की गई कुल ज़मीन उनके मालिकों को वापस कराएं. साथ ही किसानों को आर्थिक सहायता भी दिलाएं, ताकि वे बेहतर तरीक़े से खेतीबाड़ी कर सकें. इसके साथ ही राहुल गांधी को उन इलाक़ों का दौरा करना चाहिए, जहां के बाशिंदे यूपीए सरकार की योजनाओं के कारण बेघर होने के कगार पर हैं.

firdaus@chauthiduniya.com

संपत्ति का अधिकार संवैधानिक है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भी गौतमबुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए किसानों की 205 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को रद्द करते हुए कहा है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सरकार मनमाने तरीक़ेसे किसी व्यक्ति को उसकी ज़मीन से वंचित नहीं कर सकती. न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की खंडपीठ ने कहा कि अदालतों को ज़रूरत के नाम पर निजी संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण को संदेह की नज़र से देखना चाहिए. अदालतों को सतही नज़रिया नहीं अपनाना चाहिए, जैसा कि मौजूदा मामले में हुआ. उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय केसंवैधानिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए. हालांकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह अब भी महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 300-ए के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. ज़मीन के मालिकों राधेश्याम और अन्य ने अदालत में एक याचिका दायर करके मार्च 2008 में किए गए भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी थी. उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में क़रीब 157 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण को निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति सुनी अंबावनी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडे की खंडपीठ ने ग्रेटर नोएडा के साहबेरी गांव के निवासियों की याचिकाओं को मंज़ूर करते हुए भूमि उनके मालिकों को लौटाने का आदेश दिया. खंडपीठ ने इस बारे में राज्य सरकार द्वारा 10 जून और 9 नवंबर, 2009 को जारी अधिसूचनाओं को भी रद्द कर दिया.

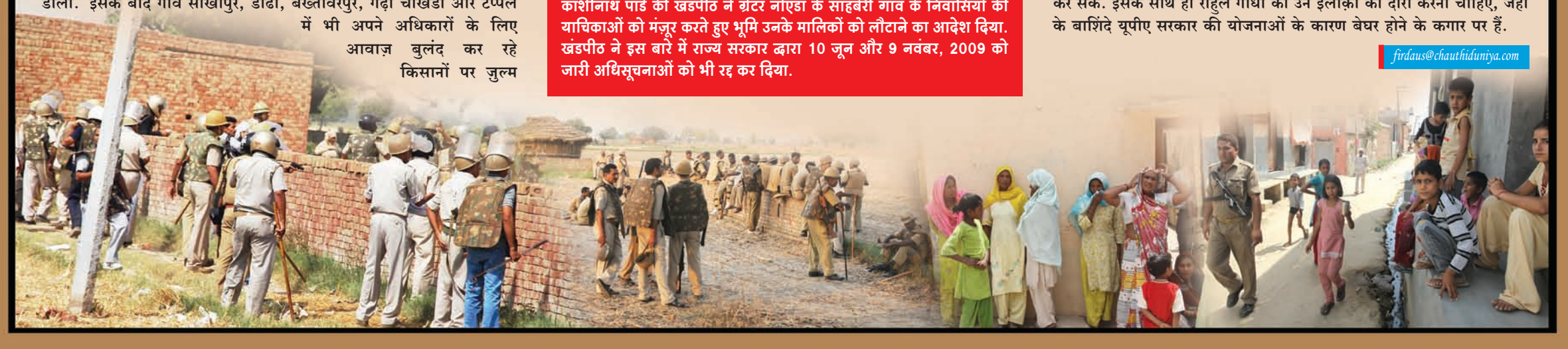

जिस तरह अमेरिकियों ने ओसामा को मार गिराया, वह सही था? बहुत से ऐसे लोग हैं, जो कि अलक़ायदा को नहीं, बल्कि अमेरिका को दोषी मानते हैं.

हमारी न्यायपालिका अधिक काम के बोझ तले दबी हुई है और तब, जबकि उसके पास कर्मचारियों और लोगों की भारी कमी है.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

समाजवाद की पृष्ठभूमि

भारत को आज़ाद हुए एक युग बीत गया है. सरकार की आर्थिक नीति समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है. कांग्रेस, सोशलिस्ट, प्रजा-समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, यहां तक कि नवनिर्मित स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ तक भी समाजवादी अर्थव्यवस्था की हिमायत करते हैं. हर पार्टी के नेता यह दावा करते हैं कि उनकी ही कल्पित समाजवादी व्यवस्था सही है, दूसरी पार्टियों की नहीं. भारत की लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी की सरकार है. अतः कांग्रेस द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था किस तरह की समाजवादी है, जनता को कुछ अनुभव हो गया है या हो रहा है. कुछ भी हो, एक बात निश्चित रूप से सिद्ध है कि जनता प्राय: सर्वसम्मत है कि समाजवादी व्यवस्था ही उपादेय है, कल्याणप्रद है.

समाजवाद पर विश्व में सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. हिंदी में भी कई पुस्तकें प्राप्य हैं. पर मेरी राय में आपको कोई भी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. किसी दूसरे की राय से प्रभावित होकर अपनी राय क़ायम करने की प्रणाली प्राचीन भारत में नहीं थी. कुछ शताब्दियों से यह दोष हम लोगों में आ गया है, जिससे दूसरों की राय से हम शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं. यदि कोई लेखक या वक्ता अच्छी भाषा में दलीलें ज़ोरदार तरीक़े से पेश करता है तो उन्हें हम सत्य मान लेते हैं. आप स्वयं अपनी राय स्वतंत्र रूप से क़ायम कीजिए कि समाजवाद क्या चीज़ है? समाजवादी व्यवस्था की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, किस तरह का समाजवाद हमको एवं सारे राष्ट्र को लाभ पहुंचा सकता है?

समाजवाद क्या है? इस बारे में विभिन्न लोगों के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं. उन लोगों की राय आपकी राय से अच्छी या सही हो, यह ज़रूरी नहीं. आपके पास कितना धन होना चाहिए? आपके पड़ोसी के पास और आपके मित्र के पास कितना-कितना धन होना चाहिए? आपकी राय क्या है? यह यक्ष प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है. बचपन से ही आपको, हमको, सबको यही सिखाया गया है. संस्कार इसी तरह के पड़े हैं कि धनवान या ग़रीब होना भाग्य की बात है. ईश्वर-इच्छा पर निर्भर है. भगवान किसी को धनवान बनाता है, किसी को निर्धन. यह मान्यता बिल्कुल ग़लत है. धनवान या ग़रीब होने का क्रम परिवर्तनशील है. निर्धन को धनवान और धनवान को निर्धन, मानव अपनी इच्छा के अनुसार ताक़त या चालाकी के बल पर बना देता है. किसी भी धनवान का धन सुरक्षित नहीं रहता, अगर शासन के पुलिस-अधिकारियों का या जेलख़ाने जाने का भय नहीं होता. विश्व में हर जगह धनवान और निर्धन व्यक्ति हैं. ऐसा देख समझ कर आपने, हमने, सबने यह मान लिया है कि धनवान होना या निर्धन होना तो भाग्य की, तक़दीर की बात है. पर असल में यह बात नहीं है. नित्य नए-नए क़ायदे क़ानून बनते हैं, बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा धन बदले जाते हैं. के धनिक, राजा-महाराजा आज अपेक्षाकृत निर्धन कहे जा सकते हैं और कल के साधारण व्यक्ति, निर्धन पुरुष आज के धनी या समाज के गणमान्य व्यक्ति माने जाते हैं. संसद में रोज़-रोज़ नए क़ानून बनाए जाते हैं. नित्य पुराने क़ानूनों में संशोधन होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको, हमको प्रचलित व्यवस्था से संतोष नहीं है. उसको सुधारने में हम प्रयत्नशील हैं. संशोधित क़ानूनों से भी संतोष नहीं, इसलिए फिर संशोधन करते हैं. फिर भी पर्याप्त संतोष न हुआ तो फिर नए सुधार करते हैं. इसी तरह परंपरा चलती रहती है और क़ानून नित्य बदलते रहते हैं. हर संशोधन के फलस्वरूप कई व्यक्तियों की जेबों से या कोषों से धन का कुछ भाग निकलता है और कई व्यक्तियों के कोष या जेबों में वृद्धि होती है. इन संशोधनों या परिवर्तनों से संतोष न होने पर दूसरे परिवर्तन किए जाते हैं. उनके फलस्वरूप समाज के दूसरे व्यक्तियों की जेबों या कोषों पर असर पड़ता है. क़ानून फिर से बदले जाते हैं, काट-छांट की जाती है. आज से 100-50 वर्ष पूर्व जिन क़ानूनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वे आज भारत का आज बाध्य होकर माने पड़ते हैं.

उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, आपके दादा-परदादा के युग में कौन सोच सकता था कि साधारण किसान, मज़दूर या हरिजन राजा-महाराजा या सेठ-साहूकारों के समकक्ष अधिकार प्राप्त कर लेंगे? कौन कल्पना कर सकता था कि कारख़ानों में मज़दूरों को अमुक मज़दूरी देनी ही पड़ेगी और काम आपके पास न होने पर भी उस मज़दूर को आप निकाल नहीं सकेंगे. इसी तरह शताब्दियों से चले आ रहे पुराने क़ानून निरस्त किए जा रहे हैं, जिनके फलस्वरूप जो-जो चीज़ें आपके दादा-परदादा के युग में स्वप्न में भी सोची नहीं जा सकती थीं, आज कर सकते हैं. उदाहरण स्वरूप, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, सहभोज इत्यादि. क़ानून बदलते रहते हैं और ये वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में बराबर फिट बैठ जाएं, इसके लिए संशोधन करते रहना पड़ता है. न्यायालय उन क़ानूनों का निर्वचन करते हैं. इस निर्वचन पर समाज की व्यवस्था में फिर से संशोधन होते रहते हैं. क़ानून में इस प्रकार अनवरत संशोधन होते रहने के कारण एक सीमा ऐसी आ जाती है कि प्रारंभ में जो क़ानून था, वहां उनकी छाया तक शेष नहीं रहती.

यह परिवर्तन अवश्यंभावी है. चुनाव के समय हर एक पार्टी समाज के लिए लंबे-लंबे वादे करती है कि वे अमुक तरह का परिवर्तन ला देंगे. पर सोचना आपको है कि किस तरह का परिवर्तन आपके या समाज के या राष्ट्र के लिए ज़्यादा हितकर होगा? पार्टियों के विज्ञापनों से या लंबी-लंबी दलीलों से प्रभावित न होकर आप अपनी स्वतंत्र राय क़ायम कीजिए और देखिए कि हमारी समाज व्यवस्था में किस तरह का परिवर्तन श्रेयस्कर है, ख़ासकर आज की आर्थिक व्यवस्था में. यह कभी मत मानिए कि जो कुछ भगवान ने लिखा है, वही होगा. आपको क़ानून द्वारा, संसद द्वारा परिवर्तन करवाने के अधिकार प्राप्त हैं. आप अपना जो निर्णय करेंगे, वही उत्तर होगा. यों तो भारत में पहले भी कई बार विचार हो चुके हैं, जिन्होंने अपने-अपने ढंग की अर्थव्यवस्था प्रतिपादित की थी. शायद उस समय के लिए वे व्यवस्थाएं सही थीं, उपादेय थीं, पर वे कभी शाश्वत नहीं बन सकीं और न ही बननी चाहिए थीं. महर्षि चाणक्य का अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य की अर्थव्यवस्था, मनु की समाज व्यवस्था, बुद्ध की शून्यवाद की अर्थ परंपरा, सम्राट अकबर का दीन-ए-इलाही, महात्मा गांधी की सर्वोदय अर्थ मीमांसा, ये सब ही तो अपने-अपने ढंग की, सामयिक समाज की, अर्थव्यवस्था की मीमांसा हैं. इनमें किसी से भी प्रभावित होकर आप अपने विचारों को बहने मत दीजिए. सब कुछ सोच समझ कर आप स्वयं अपनी एक राय क़ायम कीजिए. किसके पास कितना धन या कितनी संपत्ति होनी चाहिए, यह प्रश्न अभी तक अनिर्णीत है, निर्णीत नहीं है. शायद कभी भी सर्वथा निर्णीत नहीं हो सकेगा, हमेशा ही परिवर्तित होता रहेगा.

राम मनोहर लोहिया

जय प्रकाश

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझुनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

क्या सचमुच न्याय हुआ?

क्या रावण के साथ न्याय हुआ था? उसने तो राम से अपनी बहन सूर्पनखा की नाक काटने का बदला लेना चाहा था और इसलिए सीता को अगवा किया. क्या यह कारण इतना बड़ा था कि लंका नगरी को ही तबाह कर दिया जाए और उसके साथ-साथ सैकड़ों लोगों को भी मार डाला जाए और मार डाला जाए रावण के सारे बेटों को और फिर उसे भी? क्या राम रावण से आत्मसमर्पण नहीं करा सकते थे? और वैसे भी कौन सा राम ने युद्ध के तुरंत बाद सीता को स्वीकार ही कर लिया था. वैसे यह निरर्थक प्रश्न है. रावण सारी बुराइयों का प्रतीक था. हर साल हम दशहरे के पर्व पर उसके वध का जश्न मनाते हैं और उसका पुतला फूंकते हैं. आज तक किसी भी कोर्ट ने और यहां तक कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी उसका केस नहीं खोला है. हमारे न्याय की परिभाषा में संलिप्त है न्यायसंगत दंड. दंड हमेशा अपराध के अनुपात में ही होना चाहिए. बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट और क़ुरान में भी एक आंख के बदले एक आंख का प्रावधान है. बदले की भावना प्रचलित और लोकप्रिय न्याय की धारणा में निहित है. ईसा मसीह ने अपने दुश्मनों को भी माफ़ करने की बात कही. गांधी यदि जीवित होते तो गोडसे को भी माफ़ कर देते, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था, जिससे गोडसे फांसी से बच जाता. और कुछ ऐसा ही हुआ लादेन के साथ भी. जहां तक अमेरिकियों की बात है, लादेन भी समस्त बुराइयों का पुतला था. उसने 9/11 की ही घटना को अंजाम नहीं दिया, बल्कि यूएसएस कोल, केन्या दूतावास, बाली नरसंहार और लंदन 7/7 की घटनाओं को भी अंजाम दिया. 9/11 की घटना के बाद भारत में भी बहुत से आतंकी संगठनों ने अलक़ायदा से प्रेरणा ली और ऐसे ही एक संगठन लश्कर-ए-तैय्यबा ने 26/11 की घटना को मुंबई में अंजाम दिया.

तो क्या जिस तरह अमेरिकियों ने ओसामा को मार गिराया, वह सही था? बहुत से ऐसे लोग हैं, जो कि अलक़ायदा को नहीं, बल्कि अमेरिका को दोषी मानते हैं. कई कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष लोग तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने बिन लादेन को ऐसा हीरो बताया, जिसके साथ अन्याय हुआ था, लेकिन यह तो बस उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर मुसलमानों का वोट लेने के लिए किया गया. ये लोग सोचते हैं कि हर मुसलमान ओसामा के साथ हमदर्दी रखता है, न कि उन हज़ारों मुसलमानों के साथ, जो इराक, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, भारत, केन्या और इंग्लैंड आदि देशों में अलक़ायदा से लड़ाई में मारे गए. अमेरिकी यह मानते हैं कि यह सब उस जंग का हिस्सा था, जिसमें अमेरिका अलक़ायदा को मिटाने की कोशिश कर रहा था. उनका मानना है कि युद्ध में दुश्मन के सरदार को मार गिराना सही है. लेकिन जिस तरह मार गिराया गया, क्या वह सही था? आज इस मुद्दे पर बहुत सारे अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक यह मसला उलझा हुआ है. और क्यों न हो, आख़िरकार जॉन एफ कैनेडी को 1963 में दिनदहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था और आज तक हमें ठीक-ठीक नहीं मालूम कि यह काम किसने और कैसे किया था. खुले समाज में हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसा होता रहेगा कि नए-नए सच सामने आते रहेंगे. ओसामा की मौत लगभग आंखों के सामने मीडिया द्वारा दिखाई गई. पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें पता था और फिर धीरे-धीरे यह कहानी उलझती चली गई.

क्या सैनिक ओसामा को गिरफ्तार कर सकते थे और बाद में उस पर अभियोग चलाया जा सकता था? अमेरिकी पाकिस्तानी रडारों को चकमा देकर घुस आए थे. जब तक अमेरिकियों का एक हेलिकॉप्टर ध्वस्त होता, तब तक पाकिस्तानी यह तो सोचते रहे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन भारत को लेकर (एकतरफा दिमाग़ चलना इसे ही कहते हैं). इसलिए अमेरिकी सैनिकों ने जल्दी से अपना काम निपटाया, ओसामा को गोली मारी और चल दिए.

क्या सैनिक ओसामा को गिरफ़्तार कर सकते थे और बाद में उस पर अभियोग चलाया जा सकता था? अमेरिकी पाकिस्तानी रडारों को चकमा देकर घुस आए थे. जब तक अमेरिकियों का एक हेलिकॉप्टर ध्वस्त होता, तब तक पाकिस्तानी यह तो सोचते रहे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन भारत को लेकर (एकतरफा दिमाग़ चलना इसे ही कहते हैं). इसलिए अमेरिकी सैनिकों ने जल्दी से अपना काम निपटाया, ओसामा को गोली मारी और चल दिए. न्याय दंड की तार्किकता, अनुपात और पद्धति पर टिका होता है. न्याय संगत पद्धति का पालन नहीं किया गया. क्या ओसामा पर अभियोग चलाया जा सकता था? किस न्यायालय में, अमेरिकी या अंतरराष्ट्रीय? स्लोबोदान मिलोसेविच, राडोवन कार्डिच, चार्ल्स टेलर और ऐसे कई कैदियों के मामले चल रहे हैं, लेकिन बिना किसी जल्द निपटारे की संभावना के. इसी तर्ज़ पर यदि ओसामा पर मुक़दमा चलाया जाता तो उसके निपटारे के लिए शायद अजमल कसाब के मामले से भी कई साल अधिक लगते.

ओसामा बिन लादेन ने हमारे जीवन को बद से बदतर बना दिया. आज हम सिक्योरिटी चेक और आतंकी हमलों के डर के साये में जी रहे हैं, चाहे हम जहां भी जाएं. उसका कहना था कि यह तो पश्चिम द्वारा बीसवीं शताब्दी में, यदि धर्मयुद्धों के समय से नहीं, अरब देशों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला था. ओसामा का इतिहास बोध बहुत ही अशोधित था, बस अंतर्विरोध से ओतप्रोत था, हम बनाम उनके (इसमें भारत भी शामिल था). अमेरिकियों का भी इतिहास बोध और अलक़ायदा विरोध इससे अलग नहीं था. इसी कारण गुअंटानामो बे जेल में उन्होंने अपने ही बनाए क़ानून तोड़े, शारीरिक यंत्रणा का रास्ता अपनाया और युद्ध में चले गए. शीत युद्ध में विचारधारा का कुछ आवरण तो था, लेकिन आज के आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में यह पर्दा भी नहीं रह गया है. जहां युद्ध होता है, वहां न्याय नहीं हो सकता, लेकिन फिर कोई अंतिम निष्कर्ष भी नहीं होता है.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

जनता की ताक़त

आलेख-पीछे हट गए रामदेव पढ़कर बहुतों को झटका लगा होगा. सत्ता की ताक़त से सब वाक़िफ़ हैं, लेकिन जिस जनता ने सत्ता सौंपी है, उसकी ताक़त को भी सरकार न भूले तो बेहतर है. लोकमत को तख्ता पलटते देर नहीं लगती. किसी भी गलत काम पर अंकुश लगाना तो सरकार का कर्तव्य हो सकता है, लेकिन तानाशाही रुख़ प्रजातंत्र में नहीं चल सकता.

-अमित कुमार शर्मा, गुड़गांव, हरियाणा.

संपादकीय अच्छा लगा

चौथी दुनिया का ताज़ा अंक पाकर ख़ुशी हुई. जब तोप मुक़ाबिल हो कॉलम में देश हित पार्टी हित से बड़ा है, शीर्षक अंतर्गत संतोष भारतीय ने लोकतंत्र पर मंडरा रहे जिस ख़तरे का उल्लेख किया है, वह कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं है. हर तरफ़ अंधेरगर्दी फैली हुई है और हर कोई लूटने में अपना दिमाग़ खपा रहा है. अफ़सोस कि जो लोग देश को बचाना चाहते हैं, इस दलदल से निकलना चाहते हैं, उन्हें नोटिस भिजवाए जा रहे हैं, हद हो गई!

-सैयद शादाब अनवर, *हमजापुर, शेरघाटी, बिहार.*

सरकार और किसान

आलेख-अब प्यासे मरेंगे अमरावती के किसान महाराष्ट्र सरकार की कमियां उजागर करता है. हमेशा किसान ही ख़ामियाज़ा क्यों भुगते, कमी तो हमारी सरकार में है, जो इन कंपनियों को मनमानी करने का अवसर दे रही है.

-रमेश कुमार, *ईमेल से.*

■ केवल अमरावती नहीं, सरकार तो देश के सभी किसानों को मारने पर आमादा है. कहीं भूखा रखकर तो कहीं प्यासा रखकर.

-डेनियल, *ईमेल से.*

संस्कृत-उर्दू सभ्यता

आलेख-भारत की संस्कृत-उर्दू सभ्यता पढ़ा. सारे लोग बाहर से आए, यह मान भी लें, पर इस देश के प्रति कर्तव्य भाव से जीने वाले, जिनके लिए यह पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि या पितृभूमि है, वे कौन हैं? ऐसे लोग कोई भी हों, भारत उन्हीं का है. यही राष्ट्रीयता की व्याख्या भी है.

-मधुसूदन एच झावेरी, *ईमेल से.*

सर्वश्रेष्ठ पत्र

उजाला हुआ, मगर देर से

चौथी दुनिया ने अपनी तीसरी आंख से देखकर जो पता लगाया, वह लाजवाब है. नकली नोट, रिजर्व बैंक और सरकार, यह किस्सा अगर सच है तो सरकार, सीबीआई और रिजर्व बैंक यानी तीनों के लिए शर्म की बात है. अगर देश में 1,69,000 करोड़ जाली नोट बाजार में हैं और जनता अंधेरे में है, तो सचमुच हम लोग गंभीर स्थिति से गुज़र रहे हैं. एक बात बड़ी अजीब है, मीडिया वाले अब तक कहां थे. कंधार हाईजैक की घटना बहुत पुरानी है. इतने दिनों तक सब कुछ छुपा रहा, किसी ने कभी चर्चा तक नहीं की. ऐसी सरकारी व्यवस्था तो देश को डुबो सकती है. चौथी दुनिया ने उजाला कर दिया, मगर देर से.

-अदिति भारद्वाज, *हिंद मोटर, हुग्ली, पश्चिम बंगाल.*

शर्म आती है

आलेख-26 लाख करोड़ का महा घोटाला पढ़ा. मनमोहन सिंह जी, सोनिया तो इटालियन हैं, लेकिन आप तो भारतीय हैं. आपको क्या हो गया है? हमें शर्म आती है ऐसी सरकार पर, जिसके हाथों हमने देश को सौंप दिया.

-रवि तिवारी, *ईमेल से.*

अन्ना की आंधी

न लोक जीता, न तंत्र हारा
दे रहे दोनों एक-दूजे को सहारा
अन्ना की आंधी ने कर दिया उजागर
हज़ारे की गागर बन गई सागर
अनशन को लोगों ने मन से संवारा
दृढ़ता पर उनकी जगा जो जुनून
जनहित में बने हैं पहले भी क़ानून
लालन नहीं कोई, जो कोई बने पालनहारा
जनता का पैसा रहे सब लूट
जितना भी बंधन, जाएंगे छूट
भ्रमित जनमानस देख क़ानूनी पवारा
मरते हैं भूखे, जो करते मशक्क़त
जितना भी ले लें, कोई नहीं दिक्क़त
गरीबों को अपनी ग़रीबी गवारा
अन्ना का सैलाब देख आया न्योता
विधेयक बनाने पर हो गया समझौता
आश्वासन का फैला देश में नज़ारा

-शिव कुमार शुक्ल, *फ़ैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश.*

राजकमल प्रकाशन समूह

राजकमल प्रकाशन राधाकृष्ण लोकभारती प्रकाशन

1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002 फोन 011-23274463, 23288769, फैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com

राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से लेखन विधा को सम्मान

'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जानेवाली 700 रुपये की किताबें

राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें
हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपये की पुस्तकें दी जाएंगी
हेल्पलाइन : 09311196029

पाठक पूरे नाम, पते व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इस पते पर भेजें : संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

आंख बंद करने से समस्या हल नहीं होती

जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी उस तरह दबाव नहीं डाल पाई, जैसे उसने वी पी सिंह पर डाला था. साफ़ कह दिया था जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, शरद यादव एवं ममता बनर्जी ने कि अगर आपने एक बार भी नाम लिया राम जन्मभूमि विवाद और मंदिर बनाने का तो हम आपकी सरकार छोड़ देंगे. यह था तीसरे मोर्चे या समाजवादी विचारधारा का प्रभाव. यह कांग्रेस की बदकिस्मती थी कि वह ख़ुद को समाजवादी कहती है, लेकिन उन दलों को अपने साथ नहीं मिला पाई, जिनका समाजवाद में विश्वास था. दरअसल, समाजवादी कांग्रेस को छद्म समाजवादी कहते रहे हैं. वैचारिक विरोध भी बहुत रहा है. उस वैचारिक विरोध के पीछे डॉ. लोहिया का बहुत बड़ा विचार आज भी खड़ा है. पर कांग्रेस अगर चाहती तो भारतीय जनता पार्टी के मुक़ाबले वह ज़्यादा स्वीकार्य पार्टी थी, लेकिन वह नहीं कर पाई. अब जबकि न भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और न कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, तीसरे मोर्चे की अवधारणा या तीसरे मोर्चे की धारा में विश्वास करने वाले लोग अगर एक साथ मिलते हैं और मिलकर कार्यक्रम तय करते हैं तो वे देश के लिए एक नई संभावना दिखा सकते हैं. कौन उनके साथ जाएगा कौन नहीं जाएगा, लोगों का समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक संभावना पैदा होगी, क्योंकि आज संभावनाएं ही ज़्यादा ख़त्म हो रही हैं.

आज भी नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू यादव, राम विलास पासवान एवं अजीत सिंह जैसे नेता हैं और ये अगर मिल जाएं, इनकी पार्टियां मिल जाएं, इनके कार्यकर्ता मिल जाएं तो कम से कम उत्तर भारत में ये मज़बूत राजनीतिक ताक़त के रूप में अपना असर डाल सकते हैं और जनता के सामने एक स्वस्थ विकल्प पेश कर सकते हैं. मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वह सोचती हैं कि यह कोशिश बेकार की कोशिश है और वह स्वयं सारे देश में अकेले विकल्प बनना चाहती हैं. अभी तक उत्तर प्रदेश से बाहर मायावती जी को कहीं पर भी समर्थन नहीं मिला है. पिछले विधानसभा चुनावों में उनके लोग जहां जीते थे, वहां वे जीती हुई पार्टियों में शामिल हो गए. राजस्थान में वे कांग्रेस में चले गए. ऐसे उदाहरण हर प्रदेश के हैं. अभी जो पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उनमें मायावती जी को कोई सीट नहीं मिली. तीसरे मोर्चे की अवधारणा में मायावती का साथ नहीं है. तीसरे मोर्चे में वे दल हैं, जिनका समाजवाद में, किसानों में, मज़दूरों में थोड़ा-बहुत भरोसा आज भी है. अब उनका समर्थन मॉर्क्सवादी पार्टियां करें या न करें, भारतीय जनता पार्टी करे या न करे, ये भविष्य के सवाल हैं. पर अगर ये आपस में मिलते हैं तो जहां एक तरफ देश के लोगों को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नज़र आएगा, वहीं उस राजनीति या उस भाषा को दोबारा सुनने की आशा पैदा होगी, जिसमें ग़रीब केंद्र में रहता था, वंचित केंद्र में रहता था. लेकिन यह सब होना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब-जब ये तीसरे मोर्चे के लोग आपस में मिले हैं, तब-तब इन्होंने अपने साथी की गर्दन पर तलवार चलाई है. जितने नाम मैंने लिए हैं, उनमें नीतीश जी और शरद जी को छोड़कर सब अलग-थलग खड़े हैं. आज ये सारे लोग अलग-अलग पार्टियों में हैं. कभी ये सब एक ही पार्टी में हुआ करते थे. आज ये सभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और तीसरे मोर्चे के बनने में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो वह है प्रधानमंत्री का पद. इनकी विडंबना यह है कि जब ये दूसरे दलों के साथ रहते हैं, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे राम विलास जी हों, चाहे शरद जी हों या नीतीश जी हों, तब इनकी आकांक्षा दबी रहती है, पर जैसे ही ये आपस में मिलते हैं, इन्हें लगता है कि यही अकेले सबसे बड़े नेता हैं और बाकी सब छोटे हैं. ऐसी सोच इस देश की जनता और दबे-कुचले लोगों के साथ न्याय नहीं है, बल्कि यह इन लोगों और इनकी पार्टियों का अन्याय है.

आज भी नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू यादव, राम विलास पासवान एवं अजीत सिंह जैसे नेता हैं और ये अगर मिल जाएं, इनकी पार्टियां मिल जाएं, इनके कार्यकर्ता मिल जाएं तो कम से कम उत्तर भारत में ये मज़बूत राजनीतिक ताक़त के रूप में अपना असर डाल सकते हैं और जनता के सामने एक स्वस्थ विकल्प पेश कर सकते हैं. मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वह सोचती हैं कि यह कोशिश बेकार की कोशिश है और वह स्वयं सारे देश में अकेले विकल्प बनना चाहती हैं.

इसलिए यह ज़रूरी है कि जिस तरह इन्होंने पिछले सालों में एक-दूसरे को नुक़सान पहुंचाया, एक-दूसरे से दूर रहे, एक-दूसरे के लोगों को तोड़ने की कोशिश की, उससे अगर कोई सीख ये लोग लेते हैं तो इस देश के लोकतंत्र को मज़बूत करने, उसे और ज़्यादा व्यापक बनाने में इनका रोल होगा. अन्यथा आने वाला लोकसभा चुनाव यह ज़रूर तय कर देगा कि भविष्य में तीसरा मोर्चा या समाजवादी विचारधारा या ग़रीबों, पिछड़ों एवं दलितों का नाम लेने वाले लोगों की राजनीति में प्रासंगिकता रहेगी या नहीं. अगर यह प्रासंगिकता समाप्त होती है और आपस में ये इसी तरह एक-दूसरे की टांग खींचते रहते हैं या एक-दूसरे की पीठ में छुरा घोपते रहते हैं तो यह देश के लोकतंत्र के लिए उसी तरह ख़तरनाक है, जैसे आज के समय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विपक्ष का रोल न निभाना ख़तरनाक है. इस समय देश में कोई विपक्ष नहीं है. देश में विपक्ष के नाम पर एक ऐसी पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी की बी टीम है. एक सशक्त विपक्ष के लिए ज़रूरी है कि वह ग़रीबों की बात सुने. चुनौती कांग्रेस के सामने भी है. अगर वह ग़रीबों की बात नहीं सुनती, उनकी बात नहीं करती तो इन राज्यों के चुनाव के संकेत उसके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं. मनमोहन सिंह इस बात को नहीं समझना चाहते कि वह जब सत्ता में आए थे तो उस समय 60 ज़िले नक्सलवाद से प्रभावित थे. आज जब हम बात कर रहे हैं तो लगभग 270 ज़िलों में नक्सलवादी प्रभावी हैं. ये आंकड़े अगर मनमोहन सिंह जी को नहीं डराते और सत्तारूढ़ एवं विपक्षी पार्टी को विचलित नहीं करते तो मैं सिर्फ़ इतना ही कह सकता हूं कि आपने ख़ुद को उस रूप में ढाल लिया है, जिसे तुलसीदास जी ने कहा था कि मूंदहू आंख कतहूं कछु नाहीं. तुलसीदास जी के कहने का मतलब यह था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो आंख बंद कर लेते हैं और सोचते हैं कि दुनिया में अब न कोई परेशानी है, न समस्या है, न दिक्कत है. आशा करनी चाहिए कि भारतीय राजनीति इस भंवर से निकलेगी और देश को नए विकल्प देने में सक्षम होगी.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

हर समस्या का निस्तारण न्यायालय में संभव नहीं

पी चिदंबरम

भारत में जैसे ही कोई मुद्दा उठता है, लोग उसे ज्वलंत की संज्ञा प्रदान कर देते हैं. भारतीय न्याय व्यवस्था क्या है, इस बात पर आराम से बैठकर धैर्यपूर्वक चर्चा होनी चाहिए. मैं लोगों और ख़ासकर न्यायाधीशों से कहना चाहता हूं कि भारतीय न्यायपालिका किसी भी ऐसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, जिसे लाइलाज कहा जा सकता है. किसी भी अन्य तंत्र या व्यवस्था की तरह हमारी न्यायपालिका भी आज बहुत पुरानी और परिपक्व हो गई है, इसलिए यह दबाव में आ गई है. किसी भी अन्य व्यवस्था की तरह अगर इसमें भी ढांचागत और संस्थागत बदलाव किए जाएं तो यह दबाव अपने आप कम हो जाएगा. मैं कुछ ऐसे बिंदुओं की तरफ़ ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिनकी वजह से हमारी न्यायपालिका समुचित ढंग से काम नहीं कर पा रही है. सबसे पहली बात यह है कि हमारी न्यायपालिका अधिक काम के बोझ तले दबी हुई है और तब, जबकि उसके पास कर्मचारियों और लोगों की भारी कमी है. यह अतिशय कार्यभार अपने आप में ख़ुशी और दु:ख दोनों का ही परिचायक है. यह ख़ुशी की बात इसलिए है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आज भारत में अधिकतर लोग क़ानून और न्याय व्यवस्था में अपना विश्वास रखते हैं और यह समझते हैं कि अधिकतर झगड़ों और विवादों का निपटारा कानून के दायरे में किया जा सकता है और करना चाहिए. लेकिन यह दु:खद इसलिए है, क्योंकि अतिशय मामलों की वजह से यह व्यवस्था बहुत बड़े भार के नीचे आ गई है और बेकार के मामलों के निस्तारण से त्रस्त है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही या करना नहीं चाहती. यह जान लेना ज़रूरी है कि हर विवाद का निपटारा न्यायालय के माध्यम से नहीं हो सकता. यह भी समझने की ज़रूरत है कि हर विवाद को न्यायालय के स्तर पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा ही हुआ, जब उच्चतम न्यायालय ने मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई अपने यहां बंद कर दी. इस वजह से न्यायालय का बहुत से छोटे-छोटे और निरर्थक मामलों के निस्तारण से पीछा छूटा. मेरा मानना है कि उच्चतम न्यायालय को बहुत सारे मामलों की सुनवाई अपने यहां बंद कर देनी चाहिए और ऐसे मामलों का निस्तारण उच्च न्यायालयों के ही स्तर पर हो जाना चाहिए.

समस्या का दूसरा पहलू है जजों की कमी, संख्या में भी और उत्कृष्टता में भी. यह समस्या नियुक्ति और प्रशिक्षण की पुरानी पद्धति को बदल कर ख़त्म की जा सकती है. इसके बदले नई और तकनीकी रूप से अधिक विकसित पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए. ऊपर से हमारे उच्च और उच्चतम न्यायाधीश बहुत महत्वाकांक्षी हैं. मतलब यह कि उन्हें लगता है कि हर बात का न्यायिक निस्तारण किया जा सकता है, लेकिन मैं इस सोच से इत्तेफाक नहीं रखता. मेरा विचार है कि उसी विषय का न्यायिक निस्तारण हो सकता है, जिस विषय को और उसमें निहित समस्या को क़ानूनी या विधिक भाषा के तहत रखा जा सकता हो. जहां ऐसा हो कि अदालत को न्यायिक या विधिक तथ्यों से बाहर जाकर किसी मामले को इस तरह निस्तारित करना हो, जिसमें प्रशासनिक निर्देश देने पड़ें, ऐसे मामले को न्यायालय को नहीं लेना चाहिए. मुझे याद आता है कि सत्तर के दशक में ऐसा ही हुआ था, जब कानपुर की कुछ मृतप्राय: कंपनियों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशन में चलाने का प्रयास किया गया. जैसा कि अटकलें लगाई गई थीं, यह प्रयास विफल हो गया.

एक और विषय जो ध्यान में आता है, उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि सारी सार्वजनिक बसें सीएनजी पर चलेंगी. न्यायालय ने तेल कंपनियों की वह बात ही नहीं सुनी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि नई तकनीक से बनाए गए डीज़ल से इसके बराबर या इससे भी कम कार्बन प्रदूषण से बसें चलाई जा सकती हैं. अदालत का यह फ़ैसला सही है, लेकिन तभी तक, जब तक उचित मात्रा में गैस उपलब्ध होती रहे. फ़र्ज़ कीजिए कि गैस की उपलब्धि में कमी आ जाए तो? कीमतें बढ़ जाएं और आम आदमी के लिए यह ख़र्च वहन करना दुश्वार हो जाए? होना तो यह चाहिए था कि अदालत कार्बन उत्सर्जन का एक पैमाना तय कर देती और उसके बाद ईंधन बनाने वाली कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा के तहत नए-नए ईंधन तैयार करतीं और इसे लागू करने का काम सरकार करती. चिंता का एक और विषय है न्यायपालिका की सक्रियता यानी ज्यूडिशियल एक्टिविज्म. वैसे न्यायपालिका और ख़ासकर, उच्चतम न्यायालय ने अपनी सक्रियता से संविधान में निहित मूल अधिकारों का दायरा बढ़ाने का अच्छा काम किया है. जनहित याचिकाओं की वजह से ऐसे वर्गों, जो हाशिए पर थे, का बहुत भला हुआ है, जैसे कामकाजी महिलाएं, बंधुआ मजदूर और बाल श्रमिक.

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जब न्यायाधीश संविधान का सहारा लेते हैं तो वे क़ानून नहीं बनाते, बल्कि सिर्फ़ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन जनहित याचिकाओं से संबंधित दो पक्ष हैं, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक. इन दोनों के बीच का फर्क धागे जैसा महीन है. यह फ़र्क़ कहां करना चाहिए, यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा फ़र्क़ है ज़रूर, यह मेरी अंतर्चेतना कहती है.

बहुत से ऐसे तंत्र और संस्थाएं, जो टूट चुके थे, उन्हें मानवाधिकार धर्मशास्त्र से जोड़ा गया है, उनका उत्थान हुआ है. इस संदर्भ में देश के मुख्य न्यायाधीश के कथन को दोहराना चाहूंगा. उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जब न्यायाधीश संविधान का सहारा लेते हैं तो वे कानून नहीं बनाते, बल्कि सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन जनहित याचिकाओं से संबंधित दो पक्ष हैं, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक. इन दोनों के बीच का फर्क धागे जैसा महीन है. यह फर्क कहां करना चाहिए, यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा फर्क है ज़रूर, यह मेरी अंतर्चेतना कहती है. मेरी समझ से जब तक जनहित याचिकाएं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हों, तब तक न्यायपालिका अपनी सक्रियता में सही है. यहां एक बार फिर मैं मुख्य न्यायाधीश के कथन को उद्धृत करना चाहूंगा कि जनहित याचिकाएं नकारात्मक तब हो जाती हैं, जब वे संविधान के शब्दों और कानून के दायरे के परे चली जाती हैं. बहुत सारे तंत्र और व्यवस्थाएं टूट गए हैं, लेकिन मेरे विचार में इन सबका न्यायिक निस्तारण न्यायालयों की सक्रियता से नहीं किया जा सकता. जैसे अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाएं टूट चुकी हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी वहां के उच्चतम न्यायालय को इस बारे में कुछ कहते नहीं सुना. ब्रिटेन में भी जन स्वास्थ्य सेवाएं टूट चुकी हैं, लेकिन मैंने आज तक यह नहीं सुना कि वहां के कोर्ट ऑफ अपील या हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे ठीक करने के लिए कुछ कहा हो या कोई प्रयत्न किया हो.

भारत जैसे विशाल देश में जहां एक बड़ी आबादी बढ़ रही है और साथ ही अर्थव्यवस्था का भी विकास हो रहा हो, वहां तेज़ी से विकास करने और उस विकास को और भी समग्र बनाने के बीच मतभेद होने स्वाभाविक हैं. पुरानी व्यवस्था टूटेगी और नई व्यवस्था बनानी होगी, लेकिन जैसे कि पीडीएस (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) को ठीक करना हो या हथियारबंद विद्रोह है नक्सलियों का, इन सबका न्यायिक निस्तारण किसी अदालत के माध्यम से नहीं किया जा सकता. न्यायपालिका की सबसे बड़ी समस्या है जजों की भर्ती, उनकी नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण, ख़ासकर उच्च न्यायपालिका के जजों के संदर्भ में. मेरे विचार से न्यायपालिका की अधिकतर समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, यदि उसमें योग्य जज नियुक्त हों और उन्हें अधिकाधिक मेहनताना मिले.

feedback@chauthiduniya.com

ललित कला संकाय के चौथे वर्ष के छात्रों ने गत वर्ष 13 दिसंबर को इस पेंटिंग की शुरुआत की और यह 20 दिसंबर को पूर्ण हुई.

न्यायालय की अवमानना और आरटीआई

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(बी) में ऐसी सूचनाएं, जिनके प्रकाशन पर किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिबंध लगाया गया हो या जिनके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो, उनके सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगाई गई है. अगर कोई मामला किसी कोर्ट में निर्णय के लिए विचारधीन है तो उसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि उससे संबंधित कोई सूचना नहीं मांगी जा सकती. विचाराधीन मामलों के संबंध में कोई सूचना सार्वजनिक किए जाने से कोर्ट की अवमानना हो, यह ज़रूरी नहीं है. हां, कोई विशेष सूचना जो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगा दी हो, अगर उसे सार्वजनिक किए जाने की बात होगी तो कोर्ट की अवमानना ज़रूर होगी. गोधरा जांच के दौरान उच्च न्यायालय ने अपने एक फ़ैसले में रेल मंत्रालय को विशेष तौर पर निर्देश दिए थे कि वह गोधरा नरसंहार की जांच रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत न करे. न्यायालय ने रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगा दी. इस सूचना के दिए जाने से कोर्ट की अवमानना भी हो सकती थी और धारा 8 (1)(बी) का उल्लंघन भी. ऐसे मुद्दों पर निर्णय देते वक़्त अधिकारियों को केवल वही सूचनाएं देने से मना करना चाहिए, जिन्हें न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक किए जाने को निषिद्ध कर रखा हो. कुछ मामलों में देखने में आया है कि सरकारी अधिकारी इस धारा का इस्तेमाल सूचना न देने के बहाने के रूप में धड़ल्ले से कर रहे हैं. अफरोज ने एम्स और दिल्ली पुलिस से बाटला हाउस एन्काउंटर के दौरान मारे गए तथाकथित आतंकियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर की प्रति और दिल्ली में हुए सीरियल धमाकों की तफ्तीश के दौरान हुई गिरफ़्तारी आदि की जानकारी मांगी थी. जवाब में बताया गया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सूचना नहीं दी जा सकती. जबकि कोर्ट द्वारा सूचना सार्वजनिक न किए जाने के संबंध में दिया गया ऐसा कोई भी आदेश प्रकाश में नहीं आया.

क्या कहता है क़ानून

सूचना के अधिकार क़ानून में कोर्ट की अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है. इसे समझने के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 का सहारा लिया जा सकता है. अधिनियम की धारा 2 (ए)(बी) और (सी) में बताया गया है कि–

ए– दीवानी या फौजदारी, दोनों तरह से कोर्ट की अवमानना हो सकती है.

बी– यदि किसी कोर्ट के निर्णय, डिक्री, आदेश, निर्देश, याचिका या कोर्ट की किसी प्रक्रिया का जानबूझ कर उल्लंघन किया जाए या कोर्ट द्वारा दिए गए किसी वचन को जानबूझ कर भंग किया जाए तो यह कोर्ट की दीवानी अवमानना होगी.

सी– किसी प्रकाशन, चाहे वह मौखिक, लिखित, सांकेतिक या किसी अभिवेदन या अन्य किसी माध्यम या कृत्य द्वारा–

1– बदनाम या बदनाम करने की कोशिश या अभिकरण या कोर्ट को नीचा दिखाने की कोशिश.

2– किसी न्यायिक प्रक्रिया में पक्षपात या हस्तक्षेप.

3– न्याय व्यवस्था को किसी प्रकार से हस्तक्षेप या बाधित करना या बाधित करने की कोशिश न्यायालय की अवमानना हो सकती है.

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश, पिन -201301,
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सरकारी स्कूल की इमारत से संबंधित आवेदन

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय का नाम.....
पता.....

दिनांक.....

विषय: सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन

कृपया इस स्कूल (नाम और पता) से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. वर्ष.....से वर्ष.....के बीच उक्त स्कूल को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई? यह सूचना निम्न विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं:
(क) राशि आवंटन का वर्ष
(ख) कितनी राशि आवंटित हुई
(ग) किस उद्देश्य/कार्य के लिए राशि आवंटित की गई
(घ) वास्तविक राशि, जो उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए खर्च की गई
(च) किस उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए उक्त राशि खर्च की गई

1. वर्ष.....से वर्ष.....के बीच उक्त स्कूल को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई? यह सूचना निम्न विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं:

2. पिछले दो सालों में उक्त स्कूल पर खर्च की गई रकम का ब्योरा निम्न विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं:
(क) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए कितनी राशि खर्च की गई
(ख) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य का पूर्ण विवरण
(ग) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए स्वीकृत राशि
(घ) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को स्वीकृति देने की तिथि
(च) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य की वर्तमान स्थिति, कार्य पूरा हो गया या अधूरा है या अभी चल रहा है
(छ) उस एजेंसी का नाम, जो प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है
(ज) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य शुरू होने की तारीख
(झ) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य पूरा होने की तारीख
(ट) एजेंसी को किस दर पर प्रत्येक कार्य पूरा करने के लिए दिया गया
(ठ) एजेंसी को कितनी राशि दी जा चुकी है
(ड) कार्य के स्केच की एक सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराएं
(ढ) कब और किस आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कार्य पूर्ण हो चुका है, उस निर्णय की एक कॉपी उपलब्ध कराएं
(त) उस सहायक अभियंता और अधीक्षण अभियंता का नाम बताएं, जिसने कार्य का निरीक्षण किया और एजेंसी को भुगतान करने के लिए अपनी सहमति दी, कार्य के कौन से हिस्से का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया

3. पिछले एक साल में उक्त स्कूल पर खर्च की गई रकम का ब्योरा निम्न विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं:
(क) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए कितनी राशि खर्च की गई
(ख) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य का पूर्ण विवरण
(ग) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए स्वीकृत राशि
(घ) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को स्वीकृति देने की तिथि
(च) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य की वर्तमान स्थिति, कार्य पूरा हो गया या अधूरा है या अभी चल रहा है
(छ) उस एजेंसी का नाम, जो प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है
(ज) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य शुरू होने की तारीख
(झ) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य पूरा होने की तारीख
(ट) एजेंसी को किस दर पर प्रत्येक कार्य पूरा करने के लिए दिया गया
(ठ) एजेंसी को कितनी राशि दी जा चुकी है
(ड) कार्य के स्केच की एक सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराएं
(ढ) कब और किस आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कार्य पूर्ण हो चुका है, उस निर्णय की एक कॉपी उपलब्ध कराएं
(त) उस सहायक अभियंता और अधीक्षण अभियंता का नाम बताएं, जिसने कार्य का निरीक्षण किया और एजेंसी को भुगतान करने के लिए अपनी सहमति दी, कार्य के कौन से हिस्से का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया

मैं.....रुपये बतौर आवेदन शुल्क जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय
नाम.....
हस्ताक्षर.....
पता.....

190 घंटे की पेंटिंग

कहते हैं कि अगर मन में इरादा कर लो तो कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता. इलाहाबाद के कुछ छात्रों ने ऐसा कर दिखाया है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चार छात्रों ने लगातार 190 घंटे तक काम करके लकड़ी को काटकर 20 फुट लंबी एक ऐसी ग्राफिक पेंटिंग बनाई है, जो जीवन के सभी पक्षों को दर्शाती है. उम्मीद जताई जा रही है कि छात्रों के इस काम को किसी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में शामिल किया जा सकता है. इस पेंटिंग का शीर्षक है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. इसके ज़रिए हिंदू मिथ के अनुसार जीवन के चार पक्षों को दर्शाया गया है. धर्म (समाज और परिवार के प्रति दायित्व), अर्थ (धन और सामाजिक हैसियत की खोज), काम (आनंद की खोज) और मोक्ष (जीवन एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त होना).

ललित कला संकाय के चौथे वर्ष के छात्रों ने गत वर्ष 13 दिसंबर को इस पेंटिंग की शुरुआत की और यह 20 दिसंबर को पूर्ण हुई. पेंटिंग में कई चित्रों के माध्यम से गर्भ, गर्भाशय एवं मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं, उसकी इच्छाओं और अनुभवों को दर्शाया गया है. विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के वरिष्ठ सदस्य भी इस पेंटिंग को देखकर आश्चर्यचकित हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पेटिंग को किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में शामिल किया जा सकता है. दृश्य कला संकाय के विभागाध्यक्ष अजय जेटली ने कहा, पेंटिंग अपने आप में अनूठी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में जगह दी जाएगी. उन्होंने कहा कि 100 फीट की पेंटिंग तो हैं, लेकिन हमने अभी तक 20 फुट लंबी वुड प्रिंट पेंटिंग के बारे में नहीं सुना. छात्र कुंवर अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कल्याणी झा, निधि केसरवानी और शिल्पा सिंह ने इस पेंटिंग को बनाया. इन्होंने पालियों में काम करके इस पेंटिंग को लगातार 190 घंटे में पूरा किया. कुंवर अमरेंद्र सिंह ने कहा, पहले हमने अपना लक्ष्य लगातार सात दिनों (168 घंटे) तक पेंटिंग करने का रखा था. हम पालियों में काम करते थे और सामान्यतय: दो छात्र एक साथ काम करते थे, जिससे लक्ष्य को पूरा किया जा सके.

सिगरेट और सैलरी

सुनने में अजीब है, मगर सच है. धूम्रपान छोड़िए और पाइए 10 प्रतिशत ज़्यादा वेतन. कर्मचारियों की धूम्रपान की आदत छुड़ाने के लिए बंगलुरू की एक कंपनी ने यह नया तरीक़ा निकाला है. कंपनी ने कहा है, जो कर्मचारी धूम्रपान करते हैं, यदि वे इस आदत को छोड़ देते हैं तो उनकी बेसिक सैलरी में 10 प्रतिशत वृद्धि कर दी जाएगी. बंगलुरू मिरर में प्रकाशित ख़बर के मुताबिक़, यह तरीक़ा बंगलुरू की कंपनी फोकस इंजीनियरिंग सर्विसेस ने निकाला है. ख़बर में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी रमेश के हवाले से कहा गया है कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए यह नियम लागू किया है.

ख़ास बात यह है कि कंपनी के सीईओ रमेश ख़ुद भी पिछले 25 सालों से धूम्रपान करते रहे थे. उन्होंने जब यह आदत छोड़ी तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके साथी कर्मचारी भी स्वस्थ जीवन जिएं. इसी सोच के साथ उन्होंने कंपनी में यह फरमान जारी कर दिया. उनके मुताबिक़ , उनकी कंपनी में क़रीब 50 प्रतिशत कर्मचारी धूम्रपान करते हैं. उन्हें उम्मीद है कि उनके सैलरी बढ़ाने के इस नए तरीक़े से अधिकांश कर्मचारी धूम्रपान की आदत छोड़ देंगे. उन्होंने कहा कि मूल वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि को देखते हुए कई लोग धूम्रपान छोड़ने के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल

आपके स्वाभाविक उत्साह और पराक्रम में वृद्धि हो रही है. आपको अपने प्रयासों में लगातार सफलता मिल रही है. सामाजिक और राजनीतिक मंच पर भी आपका नाम सम्मान और आदर से लिया जाएगा. यदि किसी संस्था या संगठन के प्रतिनिधि हैं तो आपको कोई ज़िम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई

किसी सार्वजनिक घटना या घोषणा से आपके सुख–शांति में व्यवधान पड़ सकता है. अचानक विपरीत परिस्थितियां पैदा होने से आत्मविश्वास विचलित हो सकता है. इन्हीं कारणों से आप अपने कार्यक्रम भी स्थगित कर सकते हैं.

मिथुन 21 मई से 20 जून

काफी समय से चल रहा कोई विवाद या मामला इस सप्ताह अचानक समाप्त होने से मन को शांति मिलेगी. किसी आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में आपकी भागीदारी एक नया विकल्प बन सकती है. घर में किसी मूल्यवान वस्तु का आगमन हो रहा है.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई

किसी मोटे लाभ के लिए इस सप्ताह आपके मन में काफी चिंता और उत्सुकता रहेगी. हो सकता है, किसी विघ्न बाधा के चलते अभी इस काम को पूरा करने में कुछ समय लग जाए. यदि आप अपने इरादों के बल पर कोई नई रणनीति ज़ाहिर करेंगे तो आपका कार्य अचानक संपन्न हो सकता है.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त

इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सुधार की ओर अग्रसर हो रहा है. हो सकता है कि इसी वजह से आपको अपने कामकाज में उत्साह बनाए रखने में मदद मिले. यदि आप अपने समय का सही उपयोग करेंगे तो लक्ष्य के नज़दीक पहुंचने में देर नहीं लगेगी.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर

किसी प्रेमी या जीवनसाथी के व्यवहार से उदासी और अशांति महसूस होगी. बार–बार किसी न किसी कारण आपको परिवारीजनों एवं मित्रों से उपेक्षा और विरोध का सामना करना पड़ता है. आप न चाहते हुए भी किसी ग़लत धारणा से ग्रस्त हैं.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर

यह सप्ताह आपके लिए कुछ विपरीत और खिन्नता भरा रहेगा. किसी काम में लगातार असफलता मिलने से मन में उदासी रहेगी. वरिष्ठ अधिकारी या परिवारीजन आपकी खिलाफत कर सकते हैं.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर

फ़िलहाल आपके आगे–पीछे विरोधियों और आलोचकों का दबदबा चल रहा है. इस सप्ताह आप अपने कामों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे. यदि आप दृढ़ निश्चय से मुक़ाबला करेंगे तो आपकी विजय निश्चित है.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर

यह सप्ताह आपके लिए मनोकामना पूर्ति में सहायक होगा. सप्ताह के आरंभ से ही अच्छी ख़बरों और संदेशों की प्राप्ति होगी. यदि आप इसी तरह अपने कामकाज में तल्लीन रहेंगे तो आगे का समय धन–समृद्धि से भरपूर हो जाएगा.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी

कुछ अद्भुत घटनाएं इस सप्ताह के आरंभ में आपके साथ हो रही हैं. यह सब अशुभ गोचर का प्रभाव है. आपको यह नहीं समझना चाहिए कि हमेशा ऐसी स्थिति रहेगी. आपके जीवन में उतार–चढ़ाव बहुत जल्दी–जल्दी आते हैं.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी

इस सप्ताह आपको अपनी शारीरिक–मानसिक इच्छापूर्ति का सुख और हर्ष मिलेगा. किसी नए व्यक्ति द्वारा सम्मान और दावत दिए जाने की ख़ुशी होगी. कोई उपहार भी आपको सप्ताह के अंत में मिल सकता है.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च

लफ्फस सप्ताह कोई ऐसी ख़बर आ सकती है, जो आपके लिए आगे चलकर लंबी दौड़ का घोड़ा साबित हो. दीर्घकालीन योजनाओं और परियोजनाओं में आपकी भागीदारी न केवल आपका यश और ख्याति बढ़ाएगी, बल्कि धन लाभ भी कराएगी.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

अगर पाकिस्तान जेहादियों की बंदूक़ के निशाने पर आ जाता है तो अमेरिका को अपनी अफ़ग़ान योजना में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

दस साल पहले हुआ था ओसामा का सौदा

जिस तरह ओसामा को मारा गया, उसे ओबामा की शक्ति और संकल्प का उदाहरण बताया जाने लगा. ओबामा को ऐसे दृढ़ निश्चयी नेता के रूप में पेश किया गया, जो निडर ही नहीं, बल्कि देश की अस्मिता को बचाने के लिए दुस्साहस की भी सीमा तक जा सकने में सक्षम हैं और वह असामान्य फ़ैसले लेने से भी पीछे नहीं हटते.

रीतिका सोनाली

ओसामा के मारे जाने के बाद अटकलों का बाज़ार काफी गर्म हो गया है. लगभग रोज़ ही कोई न कोई नई कहानी पता चलती है. इसी क्रम में हाल में जनता को बताया गया कि ओसामा का सौदा आज से दस साल पहले ही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुश और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के बीच हो चुका था. इस सौदे में अमेरिका ने यह साफ़-साफ़ कह दिया था कि जब भी ओसामा का पता चलेगा, भले ही वह पाकिस्तान में ही क्यों न हो, तो भी उसे यह अधिकार होगा कि वह पाकिस्तानी धरती पर बिना वहां के सैन्य संगठनों को शामिल किए अपने आप ही ओसामा को मार गिराएगा. अब यह मान लेना कि सिर्फ़ इतनी ही बात हुई थी, बहुत सारे सवालों को जन्म देता है. आख़िर इस सौदे में पाकिस्तान को क्या मिला? अमेरिका ने यह तो कह दिया कि वह ओसामा को पाकिस्तानी धरती पर भी अकेले ही मारेगा, लेकिन यह नहीं बताया कि बदले में पाकिस्तान को किस तरह की मदद मिलेगी. यह प्रश्न इसलिए भी और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यह बात सर्वमान्य है कि पाकिस्तान को मिलने वाली ज़्यादातर मदद को वह भारत विरोधी कामों में ही लगाता है. वैसे ओसामा की मौत से पाकिस्तान पर लगे सवालिया निशानों के मद्देनज़र अगर यह बात देखी जाए तो भी कई ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, जो पाकिस्तान और अमेरिकी साठगांठ के काले सच के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं. इस कारण इस बात पर विश्वास करने में कठिनाई होती है.

इस संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस बात को अक्षरशः मान लिया जाए तो बराक ओबामा की छवि को गहरा धक्का लगता है. जिस तरह ओसामा को मारा गया, उसे ओबामा की शक्ति और संकल्प का उदाहरण बताया जाने लगा. ओबामा को ऐसे दृढ़ निश्चयी नेता के रूप में पेश किया गया, जो निडर ही नहीं, बल्कि देश की अस्मिता को बचाने के लिए दुस्साहस की भी सीमा तक जा सकने में सक्षम हैं और वह असामान्य फ़ैसले लेने से भी पीछे नहीं हटते. इसके पीछे की सोच यह थी कि जनता को बताया जाए कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर, मतलब कि एक स्वतंत्र देश की प्रभुसत्ता का उल्लंघन करके भी ओसामा को मार गिराने का बड़ा फ़ैसला लेने से भी ओबामा पीछे नहीं हटे. जबकि दूसरी ओर अगर ओसामा वहां नहीं मिलता तो ओबामा की किरकिरी की कोई सीमा नहीं रहती. इस ख़तरे को उठाते हुए ओबामा ने यह ऐतिहासिक फ़ैसला लिया. अगर ओसामा अमेरिका के हमले में न मिलता या भाग जाता तो ओबामा को आगामी चुनाव में हार से कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि वैसे भी पिछले कुछ सालों में ओबामा की छवि बहुत धूमिल हो गई थी और इसी कारण जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बहुत घट गई थी. बावजूद इसके ओबामा ने ऐसा ख़तरनाक, लेकिन निर्णायक फ़ैसला लिया. ओबामा की लोकप्रियता इस कारण भी बहुत बढ़ गई, क्योंकि पिछले दिनों अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकियों पर हुए हमलों की जानकारी भी सीआईए को नहीं मिल पाई थी. सीआईए पिछले दस सालों से ओसामा का पता-ठिकाना खोजने में विफल रही थी. अब ऐसी चिंताजनक स्थिति में भी ओबामा ने यह फ़ैसला लेने का क़दम उठाया तो यह बड़ी बात थी. ऐसा भी हो सकता था कि इस बार भी सीआईए की सूचना ग़लत होती और फिर वही होता, जो ऊपर कहा गया है. तो जब ओबामा की छवि इस बात से धूमिल होती है कि यह फ़ैसला उनका न होकर बुश की दूरदर्शिता का परिणाम है तो फिर ऐसा कहा ही क्यों गया? इसके पीछे बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय कारण हैं और अमेरिका की दूरदृष्टि भी है. अमेरिका अपने भविष्य के लक्ष्यों पर ध्यान देते हुए ही कोई काम करता है. तो फिर प्रश्न यह है कि इस कथन का अमेरिका के दूरगामी लक्ष्यों से क्या लेना-देना है?

यह बयान असल में पाकिस्तान की वर्तमान सरकार और सैन्य तंत्र को ओसामा के पाकिस्तान में मिलने की घटना से बचाने के लिए दिया गया हो सकता है. इसका मतलब यह है कि अमेरिका पाकिस्तान में अपने पिट्ठुओं को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को अफ़ग़ानिस्तान में चल रहे अपने युद्ध में इन लोगों की ज़रूरत है. लेकिन क्यों? वजह यह है कि ऐसा करने से पाकिस्तान के जेहादी वहां के वर्तमान तंत्र को ओसामा की मौत की ज़िम्मेदारी से मुक्त कर देंगे और पाकिस्तान अपनी ही धरती पर अपने ही बनाए दानव का कोपभाजन बनने से बच जाएगा. इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि ऐसा बयान जारी करने से मुशर्रफ़ पर ओसामा के ख़ून का इल्ज़ाम डाला जा सकता है, ताकि उनके पाकिस्तान वापस आने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, जो कि इसलिए ज़रूरी बन गया है, क्योंकि वह पाकिस्तान वापस ही नहीं लौटना चाहते, बल्कि आगामी चुनाव भी लड़ना चाहते हैं. अब उनके चुनाव लड़ने से पाकिस्तान की वर्तमान व्यवस्था में भूचाल आ सकता है, क्योंकि मुशर्रफ़ बहुत से ऐसे राज़ जानते हैं, जो अगर खुल जाएं तो पाकिस्तान के शासकों को दिक्कत हो सकती है. वैसे तो पाकिस्तान के राजनेताओं एवं सैन्य प्रमुखों में हमेशा ही लड़ाई चलती रहती है, लेकिन इस बात पर शायद दोनों ही एकमत हैं. ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि पाकिस्तान का प्रजातंत्र वर्तमान में हाशिए पर ही है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना हमेशा लोकतंत्र पर हावी रही है और हमेशा ही प्रजातंत्र ने सेना के सामने घुटने टेके हैं. मुशर्रफ़ ख़ुद भी सेना प्रमुख थे और फिर तानाशाह बन बैठे. उनके पहले भी पाकिस्तान में आज तक के इतिहास में अधिकतर समय सेना का ही शासन रहा है. दूसरी वजह, हाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा देखा गया है कि अमेरिका और यहां तक की भारत ने भी पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में पाकिस्तानी नेताओं और सेना को अलग-अलग संपर्क साधना शुरू कर दिया है. ऐसा इसलिए, क्योंकि पाकिस्तान में सेना हावी है.

अगर पाकिस्तान जेहादियों की बंदूक़ के निशाने पर आ जाता है तो अमेरिका को अपनी अफ़ग़ान योजना में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए एक अस्थिर पाकिस्तान अमेरिका के लिए उपयुक्त नहीं है. वैसे भी यह बयान और पाकिस्तान के लिए उसके निहितार्थ एवं आशय एक बात की ओर साफ़-साफ़ इशारा करते हैं कि ओसामा को पाकिस्तान के सैन्य शासकों ने अमेरिकी हाथों बेच दिया, ताकि पाकिस्तान को अफ़ग़ानिस्तान में अधिक से अधिक फ़ायदेमंद भूमिका मिले, क्योंकि अमेरिका ने अपनी सेनाओं को अफ़ग़ानिस्तान से हटाने का फ़ैसला कर लिया है. इस परिदृश्य में पाकिस्तान के लिए अफ़ग़ानिस्तान पर अपनी पकड़ मज़बूत करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तभी वह भारत को अस्थिर रख सकता है, अपनी प्रासंगिकता बरक़रार रख सकता है और अफ़ग़ानिस्तान के तालिबान को पोषित कर सकता है. साथ ही वह पुराने दिनों की तरह अफ़ग़ानिस्तान में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती कर सकता है और उस पैसे से अपना आतंकी नेटवर्क चला सकता है. वैसे पाकिस्तान ने ओसामा के अपने यहां पाए जाने की बात पर उमड़े जनाक्रोश को मोड़ने के प्रयास में बहुत सी दलीलें दी हैं. सबसे बड़ी तो यह कि अमेरिका ने उसकी संप्रभुता और आधिपत्य को भंग किया है. लेकिन यथार्थवाद यह कहता है कि वैसे भी तो पाकिस्तान कोई अपनी आर्थिक वजह से ज़िंदा है नहीं. पाकिस्तान बस अपनी भौगोलिक स्थिति के सामरिक और कूटनीतिक महत्व की वजह से अलग-अलग देशों से पैसा खा रहा है और इसी कारण जिंदा है. यदि अंतरराष्ट्रीय जनमत यह मान भी ले कि पाकिस्तान ने ही ओसामा को बचा रखा था तो उस स्थिति में भी पाकिस्तान को कौन सा नुक़सान होने वाला है. पूरा विश्व तो पहले से ही जानता है कि पाकिस्तानी धरती ही आतंकवाद की सबसे बड़ी जननी है, जहां से अलग-अलग आतंकी संगठन अपनी गतिविधियां चलाते हैं. ऐसे में ओसामा के वहां मिलने से पाकिस्तान पर कौन सी आफत आ सकती है? पाकिस्तान अभी भी अमेरिका और चीन के लिए प्रासंगिक है और उसे वहां से पैसा मिलता रहेगा. यह कोई पहली बार तो है नहीं कि अमेरिका को पाकिस्तान की दोमुंही राजनीति का पता चला है.

भारत में भी बहुत से लोग इसे पाकिस्तान के मुंह पर कालिख पुतने जैसी घटना मानते हैं, लेकिन यह तभी भारत के लिए लाभदायी है, जब वह इसे अमेरिका एवं बाक़ी विश्व के सामने भुना पाए और ओसामा का घर होने के नाते पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समाज में अलग-थलग कर पाए तथा पाकिस्तान पर दबाव बनाकर ज़ाकिर रहमान लखवी सरीखे आतंकियों को सज़ा दिलवाए. लेकिन ऐसा करने के लिए एक सोची-समझी, दूरदर्शी और साथ ही एक आक्रामक विदेश नीति होनी आवश्यक है, जो भारत के पास नहीं है. भारत के नेताओं के पास ऐसा दृढ़ निश्चय भी नहीं है. जबसे ओसामा प्रकरण हुआ है, हम सिर्फ अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि वह पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाए. हम यह क्यों नहीं समझते या समझना नहीं चाहते कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी ज़रूरी है. अफ़ग़ान मसला तो पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के लिए प्रासंगिक इसलिए भी है, ताकि वह भारत को परेशान कर सके, जिससे भारत को अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती क़ायम रखनी पड़े. अमेरिका को इस दोस्ती से भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के दोहन का मौक़ा मिलता है. चीन भी पाकिस्तान को चाहता है, ताकि भारत अस्थिर रहे और विकास की सीढ़ियों को उससे तेज़ न चढ़ पाए, जिससे चीन की एशिया में प्रभुसत्ता कायम रहे. समय की मांग यह है कि भारत अपनी शक्ति को समझे और पाकिस्तान में अमेरिका जैसी कार्रवाई करने की बयानबाज़ी में न फंसकर अमेरिका और विश्व समुदाय को इस बात के लिए मजबूर करे कि पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद ख़त्म हो, क्योंकि पाकिस्तान अलक़ायदा और तालिबान का पितामह है.

ritika@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

बाबा ने अपने हाथ का मिश्री प्रसाद हेमाडपंत को देते हुए कहा कि यदि तुम इस कहानी को सदैव याद रखोगे तो तुम्हारी स्थिति मिश्री जैसी मधुर हो जाएगी, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा.

स्वयं की दिव्यता पहचानें

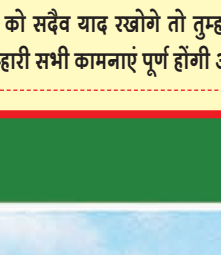

कनुप्रिया

मैं पतित तुम स्वामी, मैं मूर्ख–खलकामी, मैं दास–तुम मालिक. किस–किस तरह से स्वयं को हमने अपनी पहचान कराई! रोज आरती में क्यों कहते हैं कि मैं मूर्ख हूं, दास हूं, खलकामी हूं? इसलिए कि हम परमात्मा के सामने स्वयं को बहुत कमज़ोर, बहुत छोटा मानते हैं, पर क्या परमात्मा हमें यानी अपने बच्चों को इतना कमज़ोर, मूर्ख या पापी मानता है या वह हमारी असली पहचान कराता है? यह सच है कि जन्म से लेकर आज तक हम उतरती कला में हैं, क्योंकि किसी न किसी विकार वश हम ग़लत या पाप कर्म करते आए हैं और धीरे–धीरे लगता है कि गर्त में जाते ही जा रहे हैं. अब तो लगता है कि शायद धर्म और जीवन के रसातल में पहुंच चुके हैं. यहां तक कि अब तो सही और ग़लत की पहचान भी भूलते जा रहे हैं. लेकिन हम हर प्रार्थना, हर आरती में स्वयं को पतित मानते हैं और उससे कहते हैं कि हमें पावन बनाओ, हमारे दु:ख हरो तथा उम्मीद करते हैं कि परमात्मा प्रकट होंगे और छूमंतर से हमारी काया पलट जाएगी. होता भी कुछ ऐसा ही है. परमात्मा आकर हम बच्चों की हमसे और ख़ुद से पहचान कराता है. हमारे अपने गुणों का साक्षात्कार कराता है. वह दिव्यता, जो हमारे अंदर अनादि काल से है, उसका अनुभव कराता है, इसलिए हमें परमात्मा का साथ अच्छा लगता है. परमात्मा प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, आनंद का सागर है और हम उसके बच्चे. न उसके दास, न बंदी, बल्कि उसके प्रेम के, उसके खजाने के उत्तराधिकारी हैं. जिन दिव्य गुणों का भंडार वह है, उनकी पहचान वह हमें भी कराता है. हम, प्रेम के सागर के बच्चे, प्रेम स्वरूप हुए न! तो प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता, सत्यता और आनंद मेरे ही वे दिव्य गुण हैं, जिन्हें आज मैं भूला हुआ हूं. एक बार प्रभु का साथ लेकर उसके दिव्य गुणों को याद करके स्वयं के इन दिव्य गुणों को जागृत करें तो सिर्फ़ हम ही नहीं, हमारे आसपास का पूरा माहौल, सभी लोग उस दिव्यता को अनुभव करेंगे. अगर स्वयं को पतित, पापी ही मानना है और इंतज़ार करना है किसी चमत्कार का, तो यह इंतज़ार ही रह जाएगा. लेकिन, अगर परमात्मा को पहचान कर स्वयं को उसकी संतान मानकर उसके दिव्य गुणों का आधार लेकर ख़ुद का शृंगार करना है तो चमत्कार आज ही हो जाएगा.

ओम साईं राम.

feedback@chauthiduniya.com

बाबा और हेमाड पंत का सबक

सुबह, दोपहर और शाम, तीन समय बाबा की आरती होती थी और बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती थी. ठीक उसी समय मस्जिद में घंटी बजने लगी. बाबा के भक्त रोज़ाना दोपहर को बाबा की पूजा और आरती करते थे, यह घंटी दोपहर की पूजा–आरती की सूचक थी. शामा और हेमाडपंत तेजी से मस्जिद की ओर चल पड़े. बापू साहेब जोग पूजन शुरू कर चुके थे, सभी आरती गा रहे थे. शामा हेमाडपंत का हाथ पकड़ कर बाबा के दाईं ओर बैठ गए, जबकि हेमाडपंत सामने बैठ गए, तब बाबा ने हेमाडपंत से कहा कि शामा ने तुझे जो दक्षिणा दी है, वह मुझे दे. इस पर हेमाडपंत ने कहा कि बाबा, शामा तो यहीं पर है और दक्षिणा के लिए उसने पंद्रह नमस्कार दिए हैं. तब साई बाबा हंस पड़े और बोले, ठीक है, अब मुझे बता कि तुम दोनों के बीच क्या बातें हुईं? इस पर हेमाडपंत ने शुरू ने अंत तक हुई सारी बातें विस्तार से बता दीं. उन्होंने बताया कि वार्ता बड़ी सुखदायी रही, विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा अद्‌भुत थी. इस कथा के माध्यम से आपने मुझ पर कृपा की है. तब बाबा ने पूछा कि यह कहानी कितनी मीठी है? शामा ने कहा कि बाबा, इस कहानी को सुनकर मेरे मन की चंचलता दूर हो गई, अब मुझे रास्ता समझ में आने लगा (यानी सत्य मार्ग का पता चल गया), अब मैं एकदम शांत हूं. बाबा ने कहा, मेरी प्रणाली अनोखी है. यदि इस कहानी को स्मरण रखोगे तो बड़ी सार्थक सिद्ध होगी. फिर बाबा ख़ुशी से हंस पड़े और बोले, अब मेरा कहा मान और सुन ले, चैतन्य स्वरूप परमात्मा सब जगह मौजूद हैं, इसलिए प्रत्येक प्राणी के अंदर जो चेतना है, उसी का ध्यान करना चाहिए. उसे मेरे स्वरूप का दिन–रात ध्यान करना चाहिए. ऐसा करने से मन स्थिर होकर परमात्मा से एकरस हो जाएगा, ध्येय एवं ध्यान का भेद समाप्त हो जाएगा. गुरु और शिष्य का संबंध कछुवी मां और उसके बच्चों जैसा है. कछुवी नदी तट पर रहकर दूसरे तट पर रहने वाले अपने बच्चों का प्रेम दृष्टि से पालन–पोषण करती है. वह न तो अपने बच्चों को हृदय से लगाकर रखती है और न उन्हें अपना दूध पिलाती है. बच्चे भी अपनी मां को याद करते रहते हैं. कछुवी की प्रेम दृष्टि ही उनके लिए आहार है. इतने में ही आरती संपन्न हो गई और भक्त ऊंचे स्वरों में साई बाबा की जय–जयकार करने लगे और बापू साहेब जोग ने सबको प्रसाद में मिश्री बांटी. बाबा को भी मिश्री प्रसाद दिया गया. बाबा ने अपने हाथ का मिश्री प्रसाद हेमाडपंत को देते हुए कहा कि यदि तुम इस कहानी को सदैव याद रखोगे तो तुम्हारी स्थिति मिश्री जैसी मधुर हो जाएगी, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा. हेमाडपंत ने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और आंखों में आंसू भरकर बोले, बाबा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है, आप ही मुझे संभालिए.

लेनदेन के बिना कोई भी किसी से नहीं मिल सकता, इसलिए मनुष्य तो क्या, किसी भी जीव के प्रति नफरत का भाव मत रखो. सभी से आदर–भाव से मिलो, अभद्रता का व्यवहार मत करो. भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, वस्त्रहीन को कपड़ा और राहगीर को बैठने के लिए जगह दो. यदि तुम्हारी ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम उससे बुरा मत बोलो. यदि कोई तुम्हें बुरा बोले तो उस पर क्रोध मत करो. ऐसा करने वाले को सुख मिलता है. संसार चाहे इधर से उधर हो जाए, तुम अपने आदर्श पर स्थिर रहो. जो कुछ हो रहा है, उसे देखते रहो. तुम द्वैत भाव त्याग दो, इससे गुरु–शिष्य में पृथकत्व आ जाता है. सबका अल्लाह मालिक है, वही सबका रखवाला है, वही सबको मार्ग दिखाता है और वही सबकी इच्छाएं पूरी करता है. पूर्वजन्म का संबंध होने से ही तेरी और मेरी भेंट हुई है. आपस में प्यार बांटकर ख़ुश रहो. यहां कोई स्थिर रहने वाला नहीं है. जब तक सांसें चलती हैं, तब तक ही जीवन है और अपने जीते जी जिसने परमात्मा को पा लिया, वह ही धन्य है. इस उपदेश को सुनकर हेमाडपंत को अति आनंद हुआ और वह बाबा की चरण वंदना कर अपने घर लौट पड़े.

श्री सद्‌गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अनंत विजय

कुंठा @ प्रेम डॉट कॉम

विमल कुमार हिंदी के पाठकों के बीच एक जाना-पहचाना नाम हैं. लिक्खाड़ पत्रकार हैं, तमाम पत्र-पत्रिकाओं में साहित्य और साहित्येतर विषयों पर उनके लेख और टिप्पणियां प्रकाशित होती रहती हैं. अच्छे कवि भी हैं और कविता के लिए 1987 में ही भारत भूषण पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं. इसके अलावा हिंदी अकादमी भी उन्हें पुरस्कृत कर चुकी है, लेकिन अपने उसूलों की ख़ातिर वह पुरस्कार ठुकरा भी चुके हैं. पत्रकारिता और कविता लेखन के अलावा वह व्यंग्य और कहानियां भी लिखते हैं और कई संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं. अब उनका नया उपन्यास आया है, जिसका शीर्षक उत्तर आधुनिक है चांद @ आसमान डॉट कॉम. उपन्यास के शीर्षक से यह भ्रम होता है कि यह तकनीक की दुनिया में आ रही क्रांति और बदलाव को केंद्र में रखकर लिखी गई कृति होगी, लेकिन उपन्यास पढ़ने के बाद यह भ्रम टूट जाता है. इस उपन्यास के ब्लर्ब पर लिखा है-चांद @ आसमान डॉट कॉम का रूपक कल्पना और यथार्थ के बीच मनुष्य की आवाजाही का रूपक है, जहां मनुष्य अपने लिए कुछ हासिल कर भी कुछ हासिल कर नहीं पाता है, वह त्रिशंकु की तरह फंसा रहता है.

विमल कुमार ने अपने इस उपन्यास में प्रेम की गहरी तड़प के ज़रिए मनुष्य की इस त्रिशंकु स्थिति को अपने वक़्त के आईने में ढूंढने की कोशिश की है. यह एक प्रेमकथा ही नहीं, बल्कि अपने समय की एक त्रासद कथा भी है. मैं ब्लर्ब में सिर्फ़ यह जोड़ना चाहता हूं कि विमल कुमार का यह उपन्यास प्रेम में असफल होने की कुंठा कथा है और इसे समय की त्रासद कथा बनाने की लेखक ने जो कोशिश की है, उसमें वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है.

विमल कुमार ने अपने इस उपन्यास में प्रेम की गहरी तड़प के ज़रिए मनुष्य की इस त्रिशंकु स्थिति को अपने वक़्त के आईने में ढूंढने की कोशिश की है. यह एक प्रेमकथा ही नहीं, बल्कि अपने समय की एक त्रासद कथा भी है. मैं ब्लर्ब में सिर्फ़ यह जोड़ना चाहता हूं कि विमल कुमार का यह उपन्यास प्रेम में असफल होने की कुंठा कथा है और इसे समय की त्रासद कथा बनाने की लेखक ने जो कोशिश की है, उसमें वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है. इस उपन्यास के केंद्रीय पात्र मिहिर में साहस का घोर अभाव है. पत्नी और बच्चों के घर में होते हुए वह प्रेम की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन प्रेम को परिणति तक पहुंचाने का साहस उसमें नहीं है. उसकी पत्नी नंदिता का एक वाक्य उसके पूरे व्यक्तित्व को परिभाषित कर देता है-मिहिर, तुम्हारे साथ सबसे बड़ी बात यह है कि तुम कल्पना में जीते हो. यह क्यों नहीं देखते कि तुम्हारे पांवों के नीचे कोई ज़मीन है या नहीं. यह पूरा वाक्य इस उपन्यास पर भी लागू होता है, जहां कल्पना के आधार पर बग़ैर किसी ज़मीन के सिर्फ़ व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर कथा कहने की कोशिश की गई है. दरअसल, इस उपन्यास की कथा इसके केंद्रीय पात्र मिहिर, उसकी पत्नी नंदिता और उसकी प्रेमिका सुगंधा के इर्द-गिर्द चलती है. उपन्यास में बहुधा यह लगता रहता है कि मिहिर के बहाने लेखक अपनी बात कह रहा है, अपने जीवनानुभवों को बांट रहा है. इस उपन्यास में लेखक ने पत्र या डायरी के अंशों का इस्तेमाल करके पाठकों को एक नए तरह का कथास्वाद देने की कोशिश की है. यह माना जाता है कि पत्र और डायरी की जो प्रकृति होती है, वह लेखक की आत्मकथा की तरह ही होती है. पत्र और डायरी अपने स्वभाव से ही निजी होते हैं और वे ज़्यादातर अपने बेहद क़रीबियों को ही संबोधित किए जाते हैं. पत्रों में कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को बग़ैर किसी लाग-लपेट के अभिव्यक्त करता है, जिसके केंद्र में वह स्वयं होता है. उपन्यास में जब इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है तो लेखक की कोशिश या मंशा यह होती है कि वह ख़ुद को नेपथ्य में रखकर पत्र एवं डायरी के माध्यम से अपनी बात पाठकों के सामने रखे. पत्रों और डायरी का इस्तेमाल वह इस तरह से करता है कि पाठकों से एक कनेक्ट स्थापित हो सके. विमल कुमार ने भी अपने इस उपन्यास में अपनी बात डायरी और पत्रों के माध्यम से बख़ूबी कहने का प्रयास किया है. कुछ बेहद रूमानी पत्र इस उपन्यास में हैं.

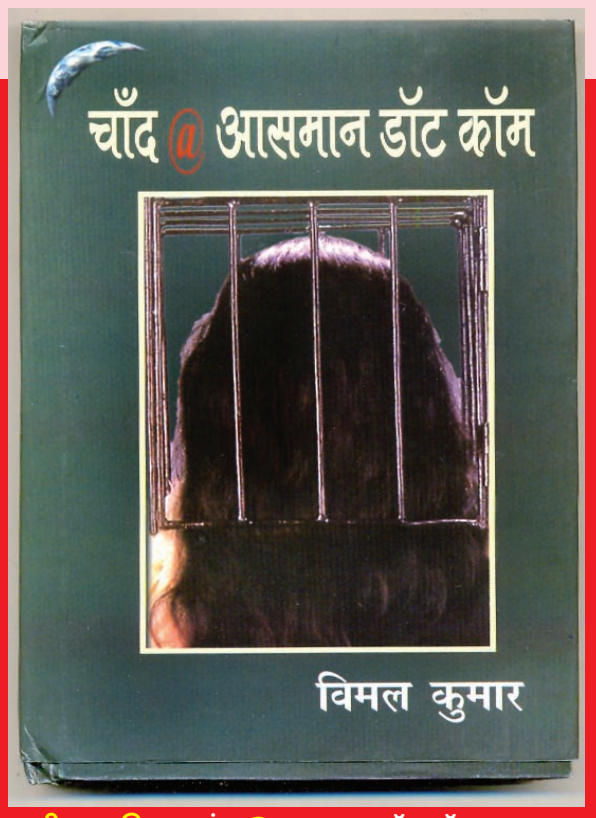

समीक्ष्य कृति : चांद @ आसमान डॉट कॉम
लेखक : विमल कुमार
प्रकाशक : वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली
मूल्य : 350 रुपये

एक दूसरी बात जो इस उपन्यास की उल्लेखनीय है, वह यह है कि विमल कुमार लिखते वक़्त बेहद अंतरंग क्षणों में भी राजनीति के प्रसंगों को ले आते हैं. उदाहरण के तौर पर जब वह अपनी प्रेमिका सुगंधा की बांहों में होते हैं और उनके दिमाग़ में राजनीति की सौदेबाज़ी या आज की भाषा में कहें तो व्यवहारिकता का एक ज़बरदस्त द्वंद्व चलता है. लेखक या यों कहें कि उपन्यास के नायक का यह द्वंद्व उन अंतरंग क्षणों भी उसे शिबू सोरेन और भाजपा की सौदेबाज़ी की ही याद दिलाता है. दूसरे, जब वह अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर होते हैं तो भी उनके दिमाग़ में रूमानियत के बजाय संसद की बहस का ही स्मरण होता है. आख़िर पच्चीस साल से पत्रकारिता कर रहे लेखक का कल्पना लोक भी उसके आसपास के वातावरण के इर्द-गिर्द ही रहेगा. कुल मिलाकर अगर हम विमल कुमार के इस उपन्यास चांद @ आसमान डॉट कॉम पर विचार करें तो लगता है कि लेखक ने एक नए तरीक़े से आत्मकथा कहने का प्रयास अवश्य किया है, जिसमें डायरी और पत्रों का प्रयत्नपूर्वक इस्तेमाल किया है. लेकिन नई शैली के बावजूद यह उपन्यास महानगरीय जीवन की एक बेहद साधारण कहानी भर बनकर रह गया है, जो एक पत्रकार की असफल प्रेम कहानी जैसी लगती है. जिस प्रेम को लेकर ख़ुद लेखक ही आश्वस्त नहीं है.

यह माना जाता है कि पत्र और डायरी की जो प्रकृति होती है, वह लेखक की आत्मकथा की तरह ही होती है. पत्र और डायरी अपने स्वभाव से ही निजी होते हैं और वे ज़्यादातर अपने बेहद क़रीबियों को ही संबोधित किए जाते हैं. पत्रों में कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को बग़ैर किसी लाग-लपेट के अभिव्यक्त करता है, जिसके केंद्र में वह स्वयं होता है.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

संकट में विज्ञान पत्रिकाएं

एल मोहन कोठियाल

आज देश में राजनीति, खेल, आर्थिक, महिला जगत, घर-परिवार, स्वास्थ्य, ऑटो मोबाइल, कंप्यूटर, पर्यावरण, सूचना प्रौद्योगिकी और फिल्म आदि विषयों पर अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, किंतु विज्ञान एक ऐसा विषय है, जिसमें सरकारी पहल के बावजूद बहुत प्रगति नहीं हुई. आज भी विज्ञान पत्रिकाओं की संख्या बेहद सीमित है. ये एक के बाद एक करके बंद होती जा रही हैं. विज्ञान एवं तकनीक का लाभ समाज को तभी मिल पाता है, जब उसे अद्यतन सूचनात्मक और समालोचनात्मक जानकारी मिलती रहे. आज समाचार चैनल मात्र बाज़ारवाद तक सीमित रह गए हैं. भूत-प्रेत, डायन, चमत्कार दिखाने वाले चैनलों के पास विज्ञान के लिए समय और स्थान नहीं है. विज्ञान से समाज में तार्किक सोच एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, लेकिन जिस स्तर पर विज्ञान एवं तकनीक की जानकारी जनता तक जानी चाहिए, वैसी नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि माहौल बनाने वाले माध्यमों का अभाव है.

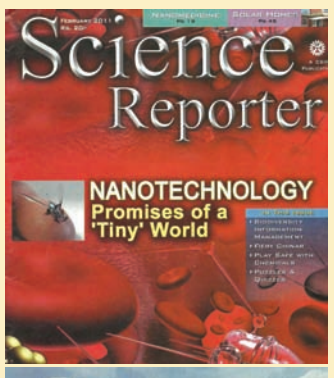

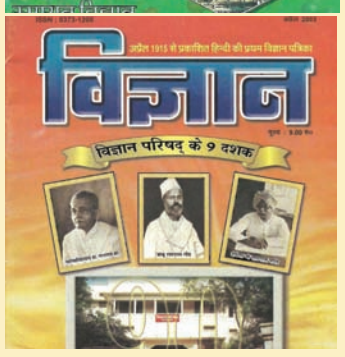

आज देश में विज्ञान के प्रति छात्रों एवं अभिभावकों की रुचि घटती जा रही है. विज्ञान के क्षेत्र में मेधावी छात्रों के न आने से अनुसंधान एवं शोध पर प्रभाव पड़ना लाज़िमी है. ऐसे में शोध के लिए अच्छे छात्रों का अभाव होता जा रहा है. विज्ञान के क्षेत्र में पिछले तीन दशकों में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही है. 20 साल पहले तक न्यूज़ स्टैंड पर तीन मुख्य मासिक विज्ञान पत्रिकाएं दिखा करती थीं. इनमें बेनेट एवं कोलमेन कंपनी की साइंस टुडे, सीएसआईआर की अंग्रेजी विज्ञान पत्रिका साइंस रिपोर्टर और हिंदी पत्रिका विज्ञान प्रगति थी. जब बेनेट कोलमेन ने अपनी पत्रिका साइंस टुडे बंद की तो कई समाचारपत्रों ने लंबे संपादकीय लिखे थे, लेकिन आज तक उसका स्थान रिक्त पड़ा है. पिछले एक साल के अंदर दो प्रमुख विज्ञान पत्रिकाएं और बंद हो गईं. इनमें सबसे पहले एनआरडीसी की पत्रिका इंवेंसन इंटेलिजेंस का नाम है, जो 1965 से अंग्रेजी में छपना शुरू हुई थी और बीते साल सितंबर से बंद है. इसके बाद संस्थान ने 40 सालों से छप रही हिंदी विज्ञान पत्रिका आविष्कार को भी बीते जनवरी माह से बंद कर दिया है. यह दोनों डाक द्वारा अपने ग्राहकों तक पहुंचा करती थीं. आविष्कार तब बंद हुई, जब संस्था के प्रबंध निदेशक किसी कारण निलंबित कर दिए गए और पत्रिका का काग़ज़ का कोटा रुक गया. ये पत्रिकाएं फिर से निकलेंगी या नहीं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता.

देश में जो भी विज्ञान पत्रिकाएं निकल रही हैं, वे सरकारी क्षेत्र से निकल रही हैं या फिर एनसीएसटीसी के सहयोग से. सीएसआईआर के अधीन राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान द्वारा प्रकाशित हो रहीं अंग्रेजी विज्ञान पत्रिका साइंस रिपोर्टर और हिंदी विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति आज देश की प्रमुख विज्ञान पत्रिकाएं हैं. सेंटर फॉर साइंस एवं एन्वायरमेंट की डाउन टू अर्थ को यद्यपि विज्ञान पत्रिका कहा जाता है, किंतु यह विज्ञान एवं तकनीक के पर्यावरणीय पहलू पर केंद्रित पत्रिका है. बेंगलुरू से निकलने वाली करंट साइंस वैज्ञानिकों तक सीमित है. इसी प्रकार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई की पत्रिका वैज्ञानिक का भी बेहद सीमित दायरा है. भोपाल से निजी क्षेत्र में आइसेक्ट एक विज्ञान पत्रिका इलेक्ट्रॉनिकी निकाल कर अच्छा काम कर रही है, किंतु वह इसका विस्तार करने में असफल रही है. इलाहाबाद से निकलने वाली भारत की सबसे पुरानी पत्रिका विज्ञान भी न्यूज़ स्टैंड पर नहीं है.

भारत में विज्ञान की चेतना जगाने हेतु 2005 के बाद से विदेशी विज्ञान पत्रिकाओं के लिए द्वार खोले जा चुके हैं. यहां कई एजेंटों के माध्यम से विदेशी विज्ञान पत्रिकाएं बेची जा रही हैं. 250 से लेकर 600 रुपये तक प्रति अंक कीमत वाली ये बेहद महंगी पत्रिकाएं संस्थागत ग्राहक सदस्यता के आधार पर चलाई जा रही हैं. इंडिया टुडे समूह ज़रूर साइंटिफिक अमेरिकन का भारतीय संस्करण निकाल कर उसे अपेक्षाकृत कम दाम पर बेच रहा है, लेकिन इसके एक अंक की कीमत 100 रुपये है. देश में विज्ञान पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए सरकार मदद देती आई है, किंतु ऐसी कई पत्रिकाएं अपना वजूद नहीं बचा सकीं. हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में निकलने वाली ऐसी विज्ञान पत्रिकाएं एक ख़ास दायरे में रहती हैं. दरअसल, विज्ञान लेखन एक हुनर है, जो हर व्यक्ति में होना संभव नहीं है. विज्ञान की गूढ़ बातों को रुचिकर बनाने की कला में दक्षता के अलावा सतत अध्ययन लेखक के लिए बेहद ज़रूरी है और मंच का होना भी. विज्ञान पर लिखने वाले अनेक लोग हैं, किंतु मंच न मिलने के कारण उनकी प्रतिभा सामने नहीं आ पाती. विज्ञान पत्रिकाओं को बंदी से बचाने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय सारथी बनने को तैयार नहीं है. जबकि नए विज्ञान लेखकों को लेकर स्वदेशी विज्ञान पत्रिकाएं निकाली जा सकती हैं. इससे देश में इस विधा को रोज़गारपरक बनाया जा सकता है और जन सामान्य की रुचि बढ़ाई जा सकती है.

निजी क्षेत्र को लगता है कि विज्ञान पत्रिकाओं के प्रकाशन से लाभ नहीं होता और लेखकों का अभाव है. आज लोगों की दिलचस्पी वैज्ञानिक खोजों से ज़्यादा तकनीक में होती है, इसलिए कंप्यूटर, चिकित्सा, सूचना तकनीक एवं इलेक्ट्रॉनिकी आदि विषयों पर पत्रिकाएं निकलती रहती हैं, किंतु विज्ञान के क्षेत्र में कोई पत्रिका नहीं दिखती. दरअसल, यह कार्य बहुत मेहनत और समर्पण वाला है. इसीलिए कई प्रकाशन समूह विज्ञान पत्रिकाओं के पचड़े में नहीं फंसना चाहते.

feedback@chauthiduniya.com

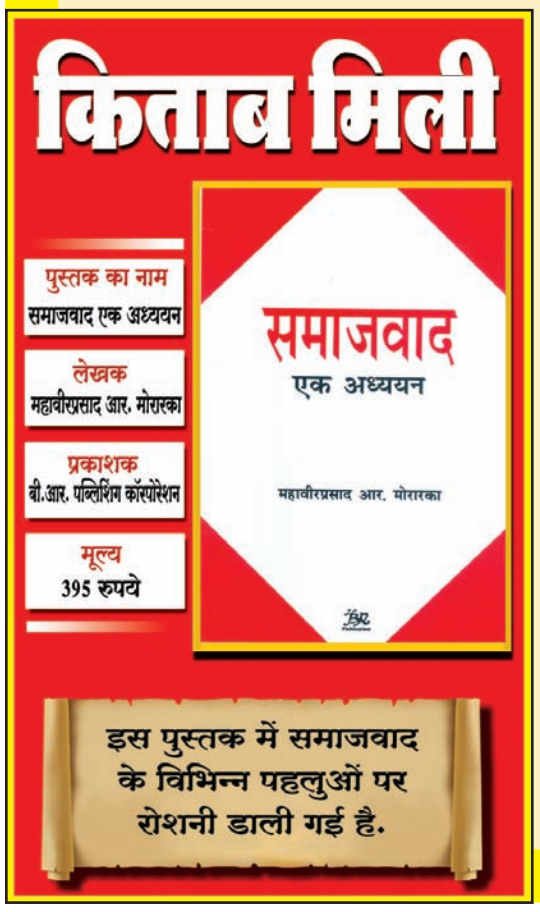

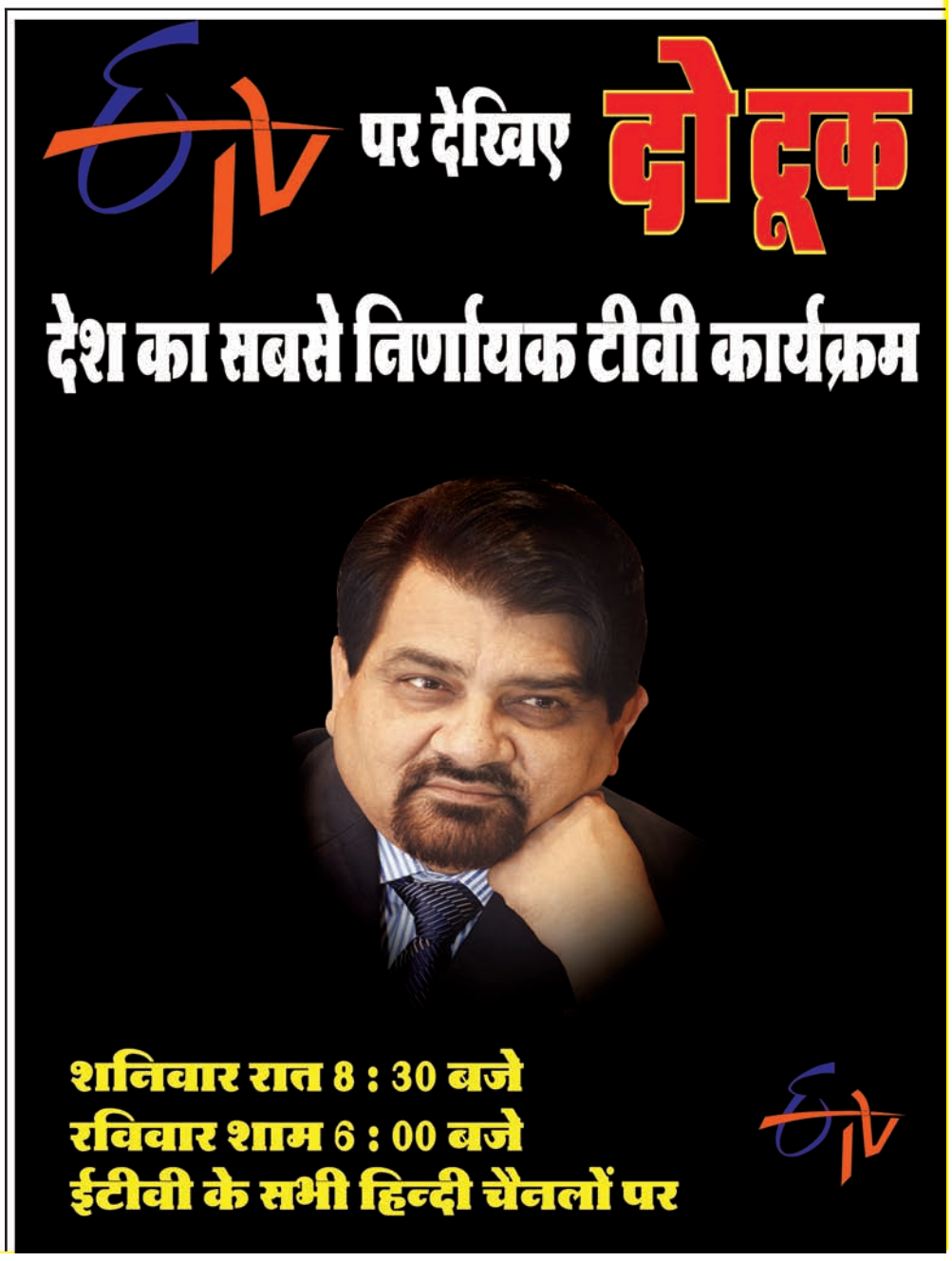

यह दूसरी बार्बी गुड़िया है, जो कैटरीना से प्रेरित होकर बनाई गई है. पिछले साल मैटेल कंपनी ने एक बार्बी गुड़िया बनाई थी, जो कैफ के लुक्स पर आधारित थी.

शानदार कार फलूडिक वरना

कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने अपनी कारों की श्रृंखला में नई नवेली कार फलूडिक वरना को जोड़ दिया है. फलूडिक वरना शानदार लुक, विलासितापूर्ण आंतरिक सजावट, अत्याधुनिक प्रोद्योगिकी जैसी विशेषताओ से युक्त है. फलूडिक वरना सिडान के लांच पर बोलते हुए एचएमआईएल के एमडी और सीईओ एच.डब्ल्यू पार्क ने कहा कि कंपनी को यह विश्वास है कि फलूडिक वरना नए मानक स्थापित करेगी और भारत में अपर मिड साइज़ कारों के स्तर को ऊपर उठाएगी. फलूडिक वरना का लांच ग्राहकों को बेहतरीन डिज़ाइन, गुणवत्ता और प्रोद्योगिकी प्रदान करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को और मज़बूती प्रदान करता है. नई फलूडिक वरना में फलूडिक स्कल्पचर डिज़ाइन फिलॉस्फी पर आधारित कई बेहतरीन डिज़ाइन तत्वों का समावेश है. कार का डिज़ाइन कूपे की तरह है जिसे आगे सुरूचिपूर्ण और सतत रेखाओं से परिष्कृत किया गया है. कार के आगे की ओर हैक्सागोनल ग्रिल, चौड़े एयर डैम के सा ईगल आई हेडलैम्प्स एल आकार के फॉग लैंप लगे हैं. फलूडिक स्कल्पचर डिज़ाइन को आगे क्रोम प्लेटेड 2 टोन रियर गार्निश और स्टाइलिश नई टेल लैंप जैसी प्रीमियम ख़ूबियों से पूरक किया गया है. 16 इंच एलॉय व्हील नई वरना को बोल्ड लुक प्रदान करते हैं, बोल्ड रियर बेपर रिफ्लेक्टर के साथ कार को स्पोर्टी लुक देते हैं. विलासितापूर्ण अहसास देने वाली अंदरूनी सफा में वुड फिनिश वाले टू-टोन बेज और ब्लैक हाई ग्लॉस इंटीरियर्स शामिल हैं. इसका अनोखा क्लस्टर आयोनाइज़र इयोन प्लाज़्मा निर्मित करते हुए जीवणुओं और अशुद्धियों को नष्ट करता है. कार के पीछे ड्यूल क्रोम टिप्ड एग्ज़ॉस्ट लगा है, साथ ही ऑडियो हैंड रिमोट की सुविधा भी दी गई है. फलूडिक डिज़ाइन की अवधारणा कार के इंटीरियर में वाई शेप्ड क्रैश पैड और आरामदायक और खुली खुली इंटीरियर सीटिंग के साथ दिखाई पड़ती है. फलूडिक वरना 8 ट्रिम विकल्पों के साथ 6 रोचक रंगों में उपलब्ध है.

एलजी का नया वाटर प्यूरिफायर

इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की जानी मानी कंपनी एलजी ने अपना नया वाटर प्यूरिफायर लांच किया है. यह काफी एडवांस्ड तकनीक से बना है जो पानी को अति शुद्ध करने में मददगार साबित होगा. यह गुणों में बेहतर तो है ही साथ ही परंपरागत वाटर प्यूरिफायर की अपेक्षा ज़्यादा ख़ूबसूरत भी है. यह भारतीय उपभोक्ताओं की आदतों को ख़ास ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह बाज़ार में बेहद ख़ूबसूरत आकर्षक लाल रंग में उपलबध है. इसकी ख़ास बात यह है कि पानी शुद्ध करने के साथ ही चिल्ड पानी एवं गरम पानी की ज़रूरत को भी यह पूरा कर सकता है. इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें फोर स्टेप आरो फिल्टरेशन सिस्टम लगा हुआ है. यह पानी के अति सूक्ष्म .001 माइक्रोंस के अशुद्ध कणों को दूर कर सकता है. एक बटन के प्रेस करते ही आपको चिल्ड पानी मिल जाएगा एवं दूसरे बटन को टच करते ही आपको 87 डिग्री तक हॉट वाटर मिल जाएगा. इसकी पूरी बॉडी एसटीएस मेटल से बनी हुई है जिससे यह लंबे समय तक चल सकेगा. इसमें फिल्टर ऑफ लाइफ इंडिकेटर भी लगा है, इस्तेमाल के बाद फिल्टर चेंज करना हो तो इसमें अपने आप ब्ल्यू या अंबर लाइट इंडिकेटर सिग्नल देने लगेगा .

इसका मॉडल नंबर है डब्ल्यूक्यू डी 74 आरजी 59
इसकी कैपिसिटी है - 6.9एल (ठंडा 2.1एल/गरम 1.8एल)
इतनी सारी ख़ूबियों के साथ यह बाज़ार में 39990 रुपये में उपलब्ध है.

स्टोरेज सोल्यूशन की नई तकनीक

हार्डड्राइव्ज़ और स्टोरेज सोल्यूशन के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी सीगेट ने दुनिया का पहला 3.5 इंच का हार्डड्राइव पेश किया है, जिसकी स्टोरेज क्षमता एक टेराबाइट प्रति डिस्क प्लैटर है. इसके ज़रिए सीगेट ने एक टेराबाइट एरियल डेनसिटी (क्षेत्रीय घनत्व) की बाधा तोड़ दी है, ताकि दुनिया भर के घरों और दफ्तरों में डिजिटल कंटेंट स्टोर करने की भारी मांग की पूर्ति की जा सके. सीगेट के गोलेक्स डेस्क उत्पाद पहले हैं, जिनमें नए हार्डड्राइव लगाए गए हैं और इनकी स्टोरेज क्षमता 3 टीबी एवं एरियल घनत्व 625 गीगाबिट्स प्रति वर्ग इंच है, जो सबसे ज़्यादा है. सीगेट अपने प्रमुख 3.5 इंच बाराकुडा डेस्कटॉप हार्डड्राइव बेचने के लिए तैयार है. तीन डिस्क प्लैटर में इसकी स्टोरेज क्षमता 3 टेराबाइट होगी यानी 120 हाई डेफिनिशन (एचडी) मूवी, 1500 वीडियो गेम, हज़ारों फोटो या अनंत समय का डिजिटल म्यूज़िक स्टोर करने की क्षमता. यह हार्डड्राइव 2011 के मध्य में वितरण चैनल को दिए जाएंगे. यह ड्राइव 2 टीबी, 1.5 टीबी और एक टीबी क्षमता में भी उपलब्ध होंगे. सीगेट के वर्ल्डवाइड सेल्स एंड मार्केटिंग के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट रॉकी पिमेनटेल ने कहा कि दुनिया भर में हर तरह के संस्थान और उपभोक्ता तेज रफ्तार से डिजिटल कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं. इससे हर तरह की डिजिटल सामग्री के भंडारण (स्टोरेज) की भारी मांग पैदा हो गई है. कंपनी अपने ग्राहकों की ज़रूरत के अनुसार स्टोरेज क्षमता, स्पीड और मैनेजेबिलिटी मुहैया कराने पर ध्यान देती है, ताकि तेजी से डिजिटल होती दुनिया फल-फूल सके. गोलेक्स डेस्क एक्सटर्नल ड्राइव विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक कंप्यूटर्स दोनों के अनुकूल है. प्रत्येक ड्राइव में मैक के लिए एक एनटीएफएस ड्राइवर होता है, जिससे यह ड्राइव फाइलों को विंडोज और मैक ओएसएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बग़ैर फॉर्मेट किए एक्सेस और स्टोर कर सकता है. गोलेक्स डेस्क एक्सटर्नल ड्राइव की स्लीक और 3.5 इंची काली डिजाइन ऐसी है, जिसे आप अपनी सुविधानुसार रख सकते हैं.

कैटरीना की बार्बी डॉल

कैटरीना कैफ ने बार्बी शैली का पिंक गाउन पहन रखा था. कैटरीना ने अपनी उत्सुकता ज़ाहिर करते हुए कहा कि यह एक बहुत ख़ास दिन है और अपने नाम पर इस तरह कोई सम्मान अर्जित करना बहुत बड़ी बात है.

कैटरीना कैफ, जो अपने बार्बी डॉल लुक्स के लिए जानी जाती हैं, ने हाल में अपनी ख़ुद की बार्बी डॉल का शुभारंभ किया. मैटेल कंपनी द्वारा चलाए जा रहे अभियान-मैं एक फिल्म स्टार हो सकता हूं, के हिस्से के रूप में बार्बी का लांच हुआ. इस अवसर पर बार्बी का पर्याय मानी जाने वाली कैटरीना कैफ ने बार्बी शैली का पिंक गाउन पहन रखा था. कैटरीना ने अपनी उत्सुकता ज़ाहिर करते हुए कहा कि यह एक बहुत ख़ास दिन है और अपने नाम पर इस तरह कोई सम्मान अर्जित करना बहुत बड़ी बात है. मुझे आशा है कि हर कोई इस गुड़िया को ज़रूर पसंद करेगा. यह दूसरी बार्बी गुड़िया है, जो कैटरीना से प्रेरित होकर बनाई गई है. पिछले साल मैटेल कंपनी ने एक बार्बी गुड़िया बनाई थी, जो कैफ के लुक्स पर आधारित थी. 2009 के लक्मे फैशन वीक में बार्बी ऑल डॉल्स अप शो में इसे प्रदर्शित किया गया था.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नोकिया के नए फोन

नोकिया ने पिछले साल भारतीय बाज़ार में अपना बेहतरीन स्मार्ट फोन नोकिया एन-8 लांच किया था और अब ख़बर है कि कंपनी जल्द ही इसका एक बेहद अनोखा मॉडल लांच करने की तैयारी में है. यह ख़ास मॉडल पिंक कलर में होगा. अब तक बाज़ार में एन-8 ब्लू, ब्लैक, सिल्वर, ग्रीन और ऑरेंज कलर में मौजूद है. यह भी बताया जा रहा है कि कंपनी एन-8 के इस पिंक कलर वाले मॉडल को अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम सिंबायन अन्ना के साथ लांच करेगी. इस फोन में फैशन, ब्यूटी टिप्स और सेलिब्रिटी न्यूज़ के लिए ख़ास एप्लीकेशंस होंगे. तैयारियों को देखकर यही लग रहा है कि कंपनी एन-8 के इस नए मॉडल को ख़ासतौर पर महिलाओं के लिए लांच करने जा रही है. दुनिया भर के मोबाइल फोन बाज़ार में अपनी पकड़ ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत करने के लिए कंपनी अब नए-नए प्रयोग कर रही है. इसी के तहत अब कंपनी ने बाज़ार में अपना एक बेहद ख़ास हैंडसेट नोकिया ओआरओ लांच करने का फ़ैसला किया है. दरअसल यह नया हैंडसेट नोकिया सी-7 का नया अवतार है. इस फोन को तैयार करने के लिए लेदर और गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि इसमें वही फीचर्स हैं, जो सी-7 के साधारण मॉडलों में होते हैं, लेकिन इसके लुक में मामूली बदलाव किया गया है. इस फोन के की-पैड और फ्रेम में सोने का इस्तेमाल किया गया है. इसका बैक कवर मज़बूत लेदर से तैयार किया गया है. अब फोन इतना ख़ास है तो ज़ाहिर सी बात है कि इसके लिए मोटी क़ीमत चुकानी पड़ेगी. इसकी क़ीमत है 1635 डॉलर यानी क़रीब 73,775 रुपये. फ़िलहाल इस फोन को रूस की एक रिटेल कंपनी बेच रही है. अन्य देशों में यह फोन कब तक उपलब्ध होगा, इस बारे में कंपनी ने अभी कुछ साफ नहीं किया है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

आईपीएल की अपार सफलता ने दूसरे खेलों के लिए भी इसी तर्ज पर लीग आयोजित कराने का रास्ता खोल दिया है.

हॉकी को आईपीएल कैसे बनाएंगे

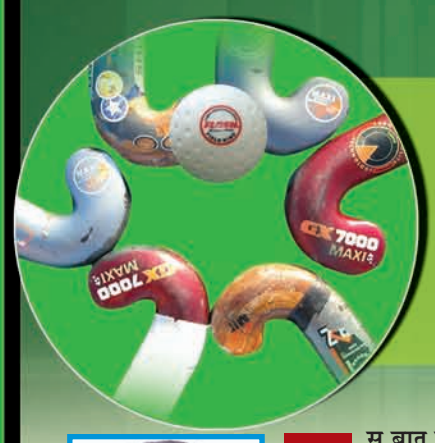

फोटो–प्रभात पाण्डेय

भारतीय हॉकी टीम किस हालत में है, इसका अंदाजा विभिन्न विवादों और स्कैंडलों के आधार पर तय किया जा सकता है. भारतीय हॉकी के दामन में एक काला दाग़ उस समय लग गया, जब एक समाचार चैनल में भारतीय हॉकी महासंघ (आईएचएफ) के महासचिव के ज्योति कुमारन एक खिलाड़ी का राष्ट्रीय टीम में चयन कराने के लिए रिश्वत लेते दिखाई दिए थे.

प्रियंका प्रियम तिवारी

इस बात से तो सभी वाक़िफ़ हैं कि भारत में हॉकी की हैसियत क्या है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि हॉकी की दशा सुधारने के लिए कई नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जाएगा. इनमें सबसे आकर्षित करने वाली योजना यह है कि अब हॉकी भी आईपीएल की तर्ज पर पेशेवर लीग के रूप में खेली जाएगी. यानी अब हॉकी के फॉर्मेट में कई ज़रूरी बदलाव होंगे और अगर यह कहा जाए कि अब पैसों की बरसात होगी तो ग़लत नहीं होगा, लेकिन यह अभी हवा में महल बनाने जैसा है. दरअसल, हॉकी और क्रिकेट में बहुत अंतर है. वर्तमान में हॉकी और क्रिकेट के हालात पर नज़र डालें तो सारा माजरा समझ में आ जाएगा कि क्यों लीग परंपरा हॉकी के लिए मुश्किल है. ख़ैर यह तो बाद की बात है, लेकिन इस घोषणा ने काफी लोगों को चौंकाया है. ग़ौरतलब है कि एफआईएच के अध्यक्ष लियांद्रो नेग्रे ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि हम वर्ष 2013 में विश्व क्लब चैंपियनशिप आयोजित करेंगे, जो एक वार्षिक प्रतियोगिता होगी. साथ ही हमारी हॉकी इंडिया के साथ भारत में एक पेशेवर लीग शुरू करने की योजना है, जिसकी विजेता टीम विश्व क्लब चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी. नेग्रे ने हालांकि साफ किया कि पेशेवर लीग अभी विचाराधीन है और एफआईएच इसके लिए विंडो निर्धारित करने के लिए सभी सदस्य देशों से बातचीत कर रहा है. उन्होंने कहा कि इसके लिए समय अहम है और यह जनवरी से फरवरी के बीच होना चाहिए. इसे लंदन ओलंपिक के बाद ही आयोजित किया जाएगा, लेकिन हमें इसके लिए विंडो बनाने की ज़रूरत है.

इसके अलावा एफआईएच अगले साल से वर्ल्ड लीग का भी आयोजन करेगा, जिसका फाइनल 2013 में भारत में होगा. नेग्रे के मुताबिक़, हमने हाल में प्रतियोगिता के ढांचे में बदलाव किया है. अगले साल से हम वर्ल्ड लीग शुरू करेंगे. एफआईएच की प्रस्तावित योजना के तहत 58 पुरुष और 50 महिला इंटरनेशनल टीमें जोनल क्वॉलिफायर खेलकर आठ टीमों के वर्ल्ड लीग फाइनल में जगह बनाएंगी. यह लीग आने वाले समय में वर्ल्ड कप और ओलंपिक के लिए क्वॉलिफाइंग टूर्नामेंट बनेगी. दूसरी तरफ़ इंडियन हॉकी फेडरेशन (आईएचएफ) ने भी भारतीय टीवी कंपनी निम्बस के साथ करोड़ों डॉलर की वर्ल्ड हॉकी सीरीज की घोषणा की है. नेग्रे ने दोहराया कि एफआईएच किसी अनाधिकृत टूर्नामेंट को मान्यता नहीं देता है और वह हॉकी इंडिया के साथ मिलकर ही काम करेगा. इस बदलाव की वजह आईपीएल की अपार सफलता के साथ–साथ उसमें बरसने वाला धन है. आईपीएल की अपार सफलता ने दूसरे खेलों के लिए भी इसी तर्ज पर लीग आयोजित कराने का रास्ता खोल दिया है. इसी के तहत अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) हॉकी इंडिया के सहयोग से भारत में फ्रेंचाइजी आधारित प्रोफेशनल लीग आयोजित करने पर विचार कर रहा है. पिछले वर्ष नई दिल्ली में आयोजित विश्वकप और राष्ट्रमंडल खेलों की सफलता को देखते हुए एफआईएच ने भी प्रोजेक्ट चक दे शुरू किया है. इसके तहत भारत में इस वर्ष से 2014 तक पांच प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट खेले जाएंगे. हालांकि अभी तक उक्त सारी योजनाएं सिर्फ़ घोषणाओं तक ही सीमित हैं, इसलिए अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है, लेकिन हॉकी की वर्तमान दशा और दिशा के आधार पर इतना तो तय किया जा सकता है कि इस योजना की सफलता किस हद तक संभावित है.

अब ज़रा हॉकी की वर्तमान हालत की बात कर लें. 20वें सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट में भारत की शर्मनाक हार तो सबके सामने है. पाकिस्तानी हॉकी टीम ने लीग मुक़ाबले में भारत को 3–1 से हराया. भारत को पहले मुक़ाबले में भी कोरिया के हाथों 2–3 से हार मिली थी, लेकिन इसके बाद उसने इंग्लैंड को 3–1 से हराया और फिर ऑस्ट्रेलिया को 1–1 से बराबरी पर रोका. चौथे मुक़ाबले में उसने मलेशिया को 5–2 से पराजित किया था. इतना ही काफी नहीं था कि न्यूज़ीलैंड ने भी भारत को 7–3 के बड़े अंतर से हराकर टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया. मलेशिया के इपोह शहर में हो रही प्रतियोगिता में अपने अंतिम लीग मैच में भारत न्यूज़ीलैंड से पहली बार इतनी बुरी तरह हारा है. इस हार के साथ ही पिछली बार का उपविजेता भारत प्रतियोगिता के फ़ाइनल में जगह पाने की दौड़ से बाहर हो गया है. सात देशों की इस सुल्तान अज़लान शाह कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत इस हार के बाद अंक तालिका में सात अंकों के साथ मलेशिया और कोरिया के बाद पांचवें नंबर पर है. दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में अपनी साख बचा रखी है.

टूर्नामेंट में तो भारतीय हॉकी की हालत साफ है, इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम किस हालत में है, इसका अंदाजा विभिन्न विवादों और स्कैंडलों के आधार पर तय किया जा सकता है. भारतीय हॉकी के दामन में एक काला दाग़ उस समय लग गया, जब एक समाचार चैनल में भारतीय हॉकी महासंघ (आईएचएफ) के महासचिव के ज्योति कुमारन एक खिलाड़ी का राष्ट्रीय टीम में चयन कराने के लिए रिश्वत लेते दिखाई दिए थे. यानी इसे आप आईपीएल के नक्शेक़दम पर चलने की शुरुआत कह सकते हैं. आपको याद होगा कि चैनल की ख़ुफ़िया टीम ने भारतीय हॉकी के पतन के कारणों की जांच के अपने अभियान में लंबे समय तक लगे रहने के बाद यह तथ्य सामने लाकर सबको हिला दिया था कि भारतीय हॉकी में चयन प्रक्रिया बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है. चैनल ने दावा किया था कि ज्योति कुमारन ने उसकी ख़ुफ़िया टीम को अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारत की वरिष्ठ हॉकी टीम में एक खिलाड़ी का चयन कराने का आश्वासन दिया और इसके बदले में पांच लाख रुपये की मांग की. इसके बाद दो लाख रुपये की रिश्वत ज्योति कुमारन को दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में 10 और 11 अप्रैल को चुकता कर दी गई और शेष 3 लाख रुपये उनके आदमी को दिल्ली में देने का वादा हुआ. धन पाने के कुछ दिनों बाद ज्योति कुमारन ने उन्हें बताया कि खिलाड़ी का नाम इस सप्ताह मंत्रालय को अजलान शाह कप टूर्नामेंट के लिए भेजी जा चुकी खिलाड़ियों की सूची में पहले ही शामिल किया जा चुका है. चैनल ने बताया कि ज्योति कुमारन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जहां तक उनका संबंध है, खिलाड़ी की टीम में जगह बुक हो चुकी है और अब यह केवल औपचारिकताएं पूरी करने की बात है. हालांकि चैनल की खुफिया टीम इस खिलाड़ी को बिल्कुल भी नहीं जानती है और उसने पूरी जांच को वास्तविक रूप देने के लिए ज्योति कुमारन को एक ऐसे खिलाड़ी का नाम बताया था, जो बेंगलुरू में हाल में हुए शिविर में शामिल था, लेकिन उसे आगामी ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया था.

इस मामले के ख़ुलासे के बाद पूरे खेल जगत में सनसनी फैल गई थी. यहां तक कि खेल राज्यमंत्री मनोहर सिंह गिल ने एक बयान में कहा कि मामले की पूरी जांच कराई जानी चाहिए और तब तक ज्योति कुमारन को अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. हालांकि उन्होंने जांच प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं कहा. धनराज पिल्ले, परगट सिंह, मोहम्मद शाहिद एवं अशोक कुमार समेत कई पूर्व दिग्गज हॉकी खिलाड़ियों ने इसे शर्मनाक घटना क़रार देते हुए ज्योति कुमारन और के पी एस गिल के इस्तीफ़े की मांग की. उधर आईएचएफ के उपाध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने भी इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग की है. उनका कहना है कि ऐसी शर्मनाक घटना की तह तक जांच होनी चाहिए. लेकिन कहते हैं न कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े–लिखे को फारसी क्या... इसी तर्ज पर अजलान शाह कप टूर्नामेंट में भारतीय हॉकी टीम के शर्मनाक प्रदर्शन ने यह तो साबित कर ही दिया कि खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता बरती गई थी.

दरअसल, यह सारा खेल देश के स्वाभिमान के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ पैसे के लिए होता है. हॉकी को भी आईपीएल की तरह लीग के रूप में बाज़ार में उतारना खेल को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि आईपीएल की तरह भ्रष्टाचार का अड्डा बनाना है. यह तो सबको पता है कि कलमाडी और ललित मोदी ने क्रिकेट के फॉर्मेट को फटाफट करके जिस तरह से पैसा, ग्लैमर और भ्रष्टाचार का कॉकटेल बनाया है, उससे इतना तो तय है कि इस खेल में सबने अपनी–अपनी जेबें गर्म की हैं. यह अलग बात है कि कोई पकड़ में आ जाता है और कोई शरद पवार की तरह बचा रहता है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि क्रिकेट को फ्रेंचाइजी के तौर पर उतारना और उससे बाज़ार में पैसा कमाना इसलिए अपेक्षाकृत आसान था, क्योंकि भारत में क्रिकेट की जो फैन फॉलोइंग है, वह हॉकी की नहीं है. इस देश में क्रिकेट गली से लेकर हर छोटे–मोटे मैदान में होते देखा जा सकता है, लेकिन हॉकी नहीं. क्रिकेट के चाहे जितने फॉर्मेट बना लीजिए, आपको खिलाड़ी उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय टीम के अलावा जूनियर और राज्य स्तर पर भी ख़ूब क्रिकेट होता है. लेकिन हॉकी में तो अंतरराष्ट्रीय टीम में ही खिलाड़ी पूरे नहीं होते, फ्रेंचाइजी के लिए खिलाड़ी कहां से उपलब्ध होंगे.

जब इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल पर क्रिकेट की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा था, तब बहुत से लोगों ने यह दलील दी थी कि इस प्रतियोगिता के कारण कई नवोदित खिलाड़ी राष्ट्रीय और फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर नाम रोशन कर रहे हैं. अगर यही बात हॉकी पर भी लागू की जाए तो यहां समस्या कुछ और है. क्रिकेट में जब यह फॉर्मेट शुरू हुआ था, तब भारत में क्रिकेट पर पैसा लगाने वाले लोगों की कमी नहीं थी. ऐसा इसलिए था, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम अपने प्रदर्शन के आधार पर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अपना सिक्का जमा चुकी थी और इससे भारत में क्रिकेट एक बड़ा बाज़ार बनकर उभरा. यही आईपीएल की सफलता का राज था, लेकिन भारतीय हॉकी का अजलान शाह कप टूर्नामेंट में जो प्रदर्शन रहा है, उस आधार पर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कितने निवेशक पैसा लगाएंगे, यह बताने की ज़रूरत नहीं है. अगर अजलान शाह टूर्नामेंट के प्रदर्शन को छोड़ दें तो भी कई विवाद हैं, जो इसे आईपीएल की तरह सफल होने से रोकते हैं. इसलिए हॉकी को फ्रेंचाइजी में बदलने के बजाय टीम का प्रदर्शन सुधार कर उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानजनक स्थान दिलाने की कोशिश की जाए तो शायद अच्छा होगा.

priyanka@chauthiduniya.com

यह सारा खेल देश के स्वाभिमान के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ पैसे के लिए होता है. हॉकी को भी आईपीएल की तरह लीग के रूप में बाज़ार में उतारना खेल को बढ़ावा देना नहीं बल्कि आईपीएल की तरह भ्रष्टाचार का अड्डा बनाना है. यह तो सबको पता है कि कलमाडी और ललित मोदी ने क्रिकेट के फॉर्मेट को फटाफट कर जिस तरह से पैसा, ग्लैमर और भ्रष्टाचार का कॉकेटेल बनाया है उससे इतना तो तय है कि इस खेल में सबसे अपनी अपनी जेबे गर्म की हैं.

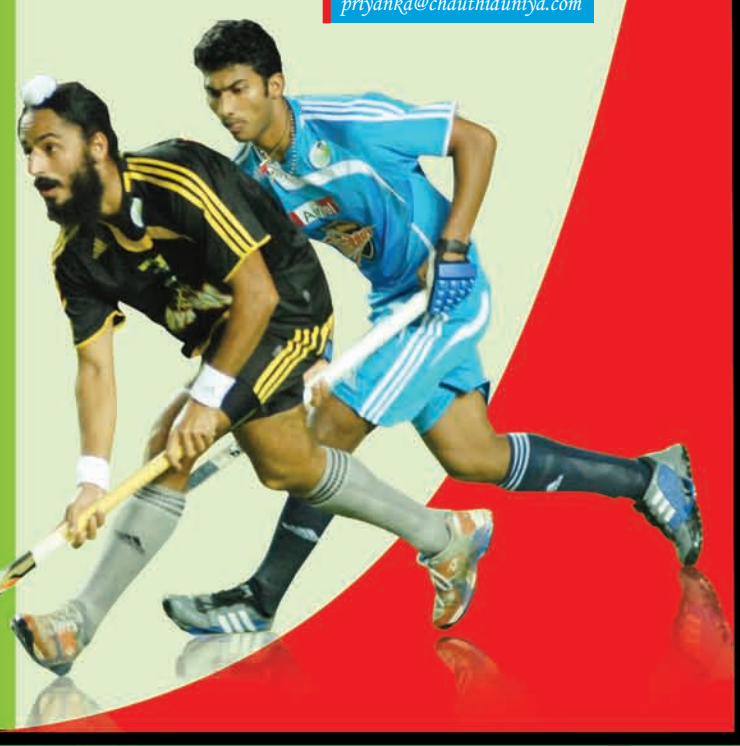

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

दिलचस्प बात यह है कि तनु वेड्स मनु के निर्माताओं के पास फ़िलहाल सीक्वल बनाने जैसी कोई योजना नहीं है.

रवीना कैसे उलझीं

रवीना टंडन इन दिनों किसी न किसी रूप में अंदर-बाहर के खेल में फंसी हुई हैं. हाल में उन्होंने कुछ विवादों के कारण कॉमेडी का महामुक़ाबला के कुछ एपिसोड से ख़ुद को बाहर कर लिया. फिर मिन्नतें करने के बाद वह वापस आईं. अब ख़बर आ रही है कि उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म डिपार्टमेंट में काम करने से इंकार कर दिया है. हाल में ख़बर आई थी कि रवीना टंडन बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं और राम गोपाल वर्मा की फिल्म डिपार्टमेंट में संजय दत्त की पत्नी की भूमिका निभाने वाली हैं. अब खबर आ रही है कि वह इस फिल्म में काम नहीं करेंगी. ख़ुद राम गोपाल वर्मा ने कहा है कि उन्होंने अपनी फिल्म डिपार्टमेंट में संजय दत्त की पत्नी की भूमिका निभाने के लिए केवल रवीना के नाम पर विचार किया था, लेकिन अब वह इस बात से कतरा रहे हैं. वह कहते हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है.

सुपरहिट शो कॉमेडी का महामुक़ाबला को रवीना टंडन ने अलविदा कह दिया है. उन्होंने इसलिए यह शो छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें अपनी स्क्रिप्ट में प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ का मज़ाक उड़ाना था. वाकई, दोस्त हो तो ऐसी! चूंकि रवीना की दोनों ही अभिनेत्रियों से अच्छी बनती है और रवीना ख़ुद भी अभिनेत्री रह चुकी हैं. इसलिए वह स्क्रिप्ट से नाख़ुश थीं और उन्होंने इसका साफ तौर पर विरोध कर दिया कि वह इस तरह की स्क्रिप्ट पर कॉमेडी नहीं करेंगी. उन्होंने स्क्रिप्ट में बदलाव करने को कहा, जिसके लिए टीम तैयार नहीं थी और रवीना शाहिद कपूर और प्रियंका के रिश्तों का मज़ाक नहीं बनाना चाहती थीं. वह यह भी जानती थीं कि उनके द्वारा दिखाया गया यह शो एक बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण बन सकता है. अब देखना यह है कि इस शो में उनकी वापसी होती है या नहीं. हालांकि ख़बर यह भी है कि उनकी टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा था, इसलिए भी उन्होंने इस शो से ख़ुद को अलग करना बेहतर समझा.

सोहा देंगी लेक्चर

अभिनेत्री सोहा अली ख़ान के लिए अपनी मां एवं प्रख्यात अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के साथ अभिनय करना आसान नहीं था. वह लाइफ गोज ऑन की शूटिंग में अपनी मां की मौजूदगी से घबराई हुई थीं. यह सोहा और शर्मिला की ऐसी पहली फिल्म है, जिसमें वे साथ नज़र आएंगी. सोहा ने कहा, मैं अपने संवाद नहीं भूली, लेकिन मैं थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि मेरी मां में बहुत अच्छा सौंदर्य बोध है. जब वह ख़ुश होती हैं तो अद्भुत होती हैं, लेकिन जब उनका मन ठीक नहीं होता तो स्थिति बहुत ख़राब होती है. वैसे वह शूटिंग के दौरान बहुत अच्छी और संयमित रहीं और साथ ही उन्होंने मुझे सलाह भी दी कि मैं निर्देशक संगीता दत्ता के निर्देशों पर ध्यान दूं. फिल्म लाइफ गोज ऑन लंदन की पृष्ठभूमि पर बनी पीढ़ियों के संघर्ष को दिखाती एक इमोशनल फिल्म है. मुझे अम्मी के साथ काम करने का मौक़ा मिला. यह एक भावनात्मक फिल्म है, जिसमें एक मां और परिवार केदु:ख को संवेदनशीलता के साथ उकेरा गया है. बैंककर्मी से अभिनेत्री बनीं सोहा ने 2004 में अनंत महादेवन की फिल्म दिल मांगे मोर से अभिनय की शुरुआत की थी और अगले साल ही वह राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म रंग दे बसंती में नज़र आई थीं. सोहा कहती हैं कि वह अपनी आने वाली फिल्मों में विविध प्रकार की भूमिकाओं में दिखाई देंगी. अभिनेता श्रेयस तलपड़े के साथ वह कैमिस्ट्री में नज़र आएंगी.

सोहा को हावर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय सिनेमा पर व्याख्यान देने के लिए विशेष आमंत्रण मिला हैं. वहां एक इंटरेक्शन सेक्शन-सिनेमा: तब और अब में सोहा हिंदी सिनेमा पर लेक्चर देंगी. इस सत्र में उनकी मां शर्मिला टैगोर भी उनके साथ होंगी. इसमें सोहा अपनी फिल्म खोया-खोया चांद, रंग दे बसंती और अंतर महल में अपने काम पर खुली चर्चा भी करेंगी. इसके साथ ही वह हिंदी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्रियों जैसे मधुबाला, मीना कुमारी, वहीदा रहमान और अपनी मां शर्मिला टैगोर के कामों पर भी प्रकाश डालेंगी. सोहा का कहना है, इस दौरे को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं और थोड़ा नर्वस भी. मैंने इससे पहले कभी सिनेमा पर लेक्चर नहीं दिया. यह काफी अच्छा अनुभव होगा. सोहा ने कहा, इसके लिए मैंने काफी रिसर्च किया है. कई पुराने अभिनेताओं एवं निर्माता-निर्देशकों से बातचीत भी की है. सोहा ने बताया कि सत्र के दौरान कमर्शियल और आर्ट, दोनों ही तरह की फिल्मों पर चर्चा होगी.

कनिष्ठा का सफ़र

पैंटालूंस फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड की विजेता कनिष्ठा धनखड़ मूल रूप से हरियाणा की हैं. उनकी मां दिल्ली में टीचर हैं. ताज जीतने का अनुभव शेयर करते हुए वह कहती हैं कि उनका सबसे बड़ा सपना सच हुआ. बकौल कनिष्ठा, मुझे इस बात की बेइंतहा ख़ुशी है कि आख़िरकार मेरा हार्डवर्क सबके सामने आया. सारे प्रतियोगी बहुत अच्छे थे. यह जर्नी और क्राउन मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं. ताज हासिल करने के लिए इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? इस सवाल पर वह कहती हैं, मैं आर्मी बैकग्राउंड वाली फैमिली से हूं. मैंने बचपन से अपनी फैमिली में सबको हार्डवर्क करते हुए देखा. दूसरी बात यह है कि हमारे परिवार में मोटिवेशनल माहौल रहा है. अगर एग्ज़ाम में मेरा स्कोर ख़राब होता था तो मेरा भाई मुझसे कहता था कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर सब ठीक हो जाएगा. वैसे भी इस तरह के कंपटीशन में आपको अपना फोकस बनाए रखना होता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी ऐसा बनाकर रखना होता है जैसे कि आप ही विनर हों.

मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के लिए आपकी क्या तैयारियां चल ही हैं? कनिष्ठा कहती हैं, अब तो कुछ ही महीने बाक़ी हैं उसके लिए. मैं मेहनत कर रही हूं. डांस की प्रैक्टिस कर रही हूं. इसके अलावा देश और दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में अपनी जानकारी बढ़ा रही हूं. कनिष्ठा की भी बॉलीवुड में एंट्री की ख्वाहिश रखती हैं. वह कहती हैं, अगर मुझे बॉलीवुड में काम करने का मौक़ा मिला तो यह वाकई मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी.

कोई तो मिल जाए

जब किसी को वह मिल गया हो, जो उसने सपने में भी न सोचा हो तो उसका झूमना लाज़िमी है. ऐसा ही कुछ इन दिनों रणवीर सिंह के साथ हो रहा है. रणवीर ने कभी नहीं सोचा था कि करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा से मिलना उनके लिए इतना आसान होगा. वह हर दूसरे-तीसरे दिन अपनी इन दो प्रिय अभिनेत्रियों से मिल पाएंगे. अब जबकि बैंड बाजा बारात की सफलता के बाद रणवीर के लिए यह सब संभव हो गया है तो उनके पैर जमीं पर नहीं पड़ रहे हैं. और तो और, अब वह कुछ ऐसे काम करने लगे हैं, जिससे उनकी दोनों प्रिय अभिनेत्रियां नाराज़ हो गई हैं. साथ ही, रणवीर की अच्छी मित्र अनुष्का शर्मा भी समझ नहीं पा रही हैं कि आख़िर रणवीर को क्या हो गया है, वह क्यों ऐसी ऊलजुलूल हरकतें कर रहे हैं, जिनसे उनकी पसंद पर सभी आश्चर्य कर रहे हैं. दरअसल, हुआ यह कि करीना कपूर की ख़ूबसूरती के मुरीद रणवीर को जब एक पार्टी में करीना से मिलने का मौक़ा मिला तो वह ख़ुशी से झूमने लगे. वह सैफ अली ख़ान की मौजूदगी में करीना की मर्जी के बिना उनसे नज़दीक होने की कोशिश करने लगे. करीना को रणवीर की यह हरकत अच्छी नहीं लगी. वह जल्द ही पार्टी से निकल गईं.

उधर दूसरी पार्टी में जब रणवीर की नज़रें प्रियंका चोपड़ा से मिलीं तो एक बार फिर उनसे नहीं रहा गया. वह प्रियंका की तरफ़ देखकर उन्हें फ्लाइंग किस देने लगे. इस पर प्रियंका झेंप गईं और उन्होंने रणवीर को भविष्य में ऐसा न करने की बात कही. जब अनुष्का के कान में यह बात पहुंची तो वह भी रणवीर से नाराज़ हो गईं. उन्होंने रणवीर को समझाया कि यदि हिंदी फिल्मों में उन्हें अपनी पहचान बनानी है तो प्रशंसकों जैसी हरकतें छोड़नी पड़ेंगी और अपनी अहमियत साबित करनी होगी. अनुष्का की बातों पर अमल करना ही रणवीर के लिए फ़ायदेमंद होगा, वरना हीरोइनों को देखकर फिसल जाने वाले एक्टर को निर्माता-निर्देशक गंभीरता से नहीं लेते...

कंगना की तरक़्क़ी

अमूमन नई फिल्मों की घोषणा निर्माता-निर्देशक करते हैं, लेकिन फिल्म तनु वेड्स मनु के सीक्वल की घोषणा पिछले दिनों कंगना रानावत ने की. अपनी इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता से कंगना इतनी उत्साहित हुईं कि उन्होंने निर्माता-निर्देशक की हरी झंडी मिलने से पहले ही सीक्वल की घोषणा कर दी. उन्होंने इस बारे में मीडिया से बातें करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, कंगना ने ख़ुद ही तनु वेड्स मनु के सीक्वल की स्क्रिप्ट की रूपरेखा भी तय कर दी. कंगना ने कहा कि इस सीक्वल में तनु और मनु के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाएगा. बिंदास तनु और सीधे-सादे मनु शर्मा की ज़िंदगी, खासकर कमरे के भीतर की ज़िंदगी को सीक्वल का मुख्य विषय बनाया जाएगा.

दिलचस्प बात यह है कि तनु वेड्स मनु के निर्माताओं के पास फ़िलहाल सीक्वल बनाने जैसी कोई योजना नहीं है. उन्होंने अभी तक सोचा ही नहीं है कि इसका सीक्वल भी बनेगा. कंगना की जल्दबाज़ी निर्माता-निर्देशक को समझ में नहीं आ रही है कि उनसे सलाह-मशविरा किए बग़ैर कैसे मीडिया में सीक्वल की घोषणा कर दी गई. कंगना के नज़दीकियों की मानें तो तनु वेड्स मनु की तनुजा त्रिवेदी के किरदार से उन्हें एक अलग पहचान मिल गई है. तनु के किरदार ने उनकी लोकप्रियता का दायरा बढ़ा दिया है. आमतौर पर आजकल सफल फिल्मों के सीक्वल की घोषणा ज़रूर होती है. कंगना ने सोचा कि कहीं निर्माता उनकी जगह किसी और अभिनेत्री को लेकर सीक्वल बनाने की बात न सोचने लगे, इसीलिए उन्होंने ख़ुद ही तनु वेड्स मनु के सीक्वल की बात करनी शुरू कर दी. फ़िलहाल कंगना की हड़बड़ी उनकी जगहंसाई का कारण बन गई है. अब वह चुप्पी साधे अपनी नई फिल्मों की शूटिंग में मशरूफ हैं. अब वह तनु वेड्स मनु के सीक्वल की बात करने से भी हिचकिचाती हैं. उम्मीद है कि कंगना अपनी इस हड़बड़ी के नतीजे से सबक लेंगी और भविष्य में जल्दबाज़ी में कोई घोषणा नहीं करेंगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

कुछ लव जैसा

सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी फिल्म कुछ लव जैसा से काफी समय बाद वापसी कर रहे हैं राहुल बोस. एक अलग तरह के कलाकार के रूप में पहचाने जाने वाले राहुल से जितनी उम्मीद दर्शकों को है, उतनी ही उम्मीद राहुल को अपनी इस फिल्म से है. इस फिल्म में उनके साथ हैं शैफाली शाह, जिन्होंने अपनी ख़ास अदाकारी से अलग तरह के किरदारों में जान डाली है. इस फिल्म के निर्माता हैं विपुल शाह और इसे निर्देशित किया है बरनाली रे शुक्ला ने. यह ऐसे दो लोगों की कहानी है, जो अपनी ज़िंदगी से ऊब चुके हैं. मधु यानी शैफाली हाउस वाइफ है और सबका ख्याल रखते-रखते अपने आपको खो चुकी है. अपनी बोरिंग लाइफ से वह दूर भागना चाहती है, ज़िंदगी में रोमांच चाहती है. दूसरी ओर राघव यानी राहु बोस एक अपराधी है और पुलिस से भागते-भागते थक गया है. अब वह ज़िंदगी में ठहराव चाहता है. इन दोनों की मुलाक़ात होती है और फिल्म की कहानी में कई ट्विस्ट आते हैं. फिल्म में ओमपुरी और नीतू चंद्रा ने अतिथि भूमिका निभाई है. इनके अलावा सुमित राघवन, मनमीत सिंह, कुणाल कुमार, अमीन हाजी सहायक भूमिकाओं में हैं. पटकथा लिखी है निर्देशक बरनाली रे शुक्ला ने और सिनेमेटोग्राफी की कमान संभाली बॉबी सिंह ने. फिल्म का संगीत प्रीतम चक्रवर्ती ने दिया और गीत लिखे इरशाद कामिल ने. फिल्म को स्टानली और रीमो डिसूजा ने कोरियोग्राफ किया है. ड्रामा जॉनर की यह फिल्म आगामी 27 मई को रिलीज हो रही है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 23 मई-29 मई 2011

www.chauthiduniya.com

कुशवाहा को चाहिए राज और ताज

बिहार में क़रीब 40 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां कुशवाहा की आबादी 25 हज़ार से ज़्यादा है तथा 12 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां 25 हज़ार से ज़्यादा आबादी तो है किन्तु वह क्षेत्र सुरक्षित हो गया है. क़रीब 80 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसे यह समाज प्रत्यक्ष रूप से तथा 30 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसे यह समाज अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है. ऐसे में अब कुशवाहा समाज के नेताओं ने सत्ता में उचित भागेदारी के लिए नया संघर्ष शुरू कर दिया है.

उपेंद्र कुशवाहा

प्रेमकुमार मणि

सरोज सिंह

चुनावी राजनीति का एक फार्मूला है, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी. लेकिन बिहार की सत्ता में शीर्ष पर बैठे नेताओं ने इस फॉर्मूले को अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से लागू किया और सत्ता की मलाई का दोनों हाथों से स्वाद चखा. यही वजह है कि बिहार का कुशवाहा समाज इस बात को लेकर दुखी है कि हद से आगे बढ़कर भागीदारी निभाने के बावजूद सत्ता की हिस्सेदारी में वह हमेशा पीछे छूटा जा रहा है. सत्ता की मलाई कोई और खा रहा है और इस समाज को बस झुनझुना पकड़ा दिया जा रहा है. कुशवाहा समाज अब अपनी इस पीड़ा के प्रतिकार का मन बनाने लगा है. सोच है कि छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से दूर हो चुके इस समाज को पूरी तरह एकजुट कर एक ऐसी संगठित शक्ति के तौर पर उभारा जाए कि सूबे के राजनीतिक पटल पर कोई भी इसकी अनदेखी करने का साहस न कर पाए. कई स्तरों पर काम शुरू भी हो गया है और जल्द ही इस समाज का एक बड़ा गोलबंद चेहरा दिखलाई देने वाला है. अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग को गहरा झटका लग सकता है.

कुशवाहा बिहार में आबादी के दृष्टिकोण से यादव के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति है. यूं तो कुशवाहा समाज भगवान राम के पुत्र कुश को अपना सबसे पहला पूर्वज मानता है और कुछ लोग समाज के पूर्वजों में महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सम्राट अशोक को भी शामिल करते हैं. कुशवाहा स्वाभाव से विनम्र और मेहनती होते हैं पर अन्याय के खिलाफ इनमें विद्रोह करने की क्षमता भी है. राज्य में 9 प्रतिशत आबादी होने के बाद भी 1952 से लेकर 1980 तक इनके विधायकों की संख्या राज्य में दर्जन से ज़्यादा नहीं हो सकी. 1985 में इनकी संख्या विधानसभा में 14 हुई तो इस समाज की ओर लोगों का ध्यान गया. मंडल कमीशन की लड़ाई में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के कारण 90 में इसके विधायकों की संख्या 22 हुई. इसके बाद 95 के चुनाव में कुशवाहा-कुर्मी का समीकरण बनाकर शकुनी चौधरी और नीतीश कुमार ने समता पार्टी का निर्माण किया और चुनाव में कुशवाहा जाति का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा. विधानसभा के 95 के चुनाव में इस समाज के 28 विधायक चुनकर आए. इस चुनाव के बाद कई पार्टियों ने अपनी कमान कुशवाहा नेताओं के हाथों में सौंपी. समता पार्टी में विधायक दल के नेता शकुनी चौधरी, बसपा के महाबली सिंह, कुशवाहा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में रामदेव वर्मा, सीपीआई में सूरज प्रसाद, भाकपा माले में राजाराम प्रसाद नेता बनाए गए. नागमणि का भी क़द बढ़ा. उस समय ऐसा लगने लगा था कि अब आने वाला समय कुशवाहा समाज का है. लेकिन उस दौरान इस समाज के बड़े नेताओं ने छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से इतनी दूरी बना ली कि समाज का प्रतिनिधित्व फिर विधानसभा में घटने लगा. 2000 में 26, 2005 में 23 और 2010 में कुशवाहा समाज के विधायकों की संख्या 19 होकर रह गई. प्राचीन काल में भले ही यह समाज अपने को कुश, बुद्ध एवं सम्राट अशोक से जोड़ता हो किन्तु बिहार में इस समाज के सबसे बड़े संगठक सीपी सिन्हा के मुताबिक आधुनिक भारत में उत्तर प्रदेश के बनारस के पास रॉबर्टसगंज में सब्जी बेचने वाली महिलाओं पर होने वाले शोषण के ख़िलाफ़ हरि प्रसाद वैष्णव के निर्देशन में 1911 में कोइरी हितकारिणी पंचायत समिति का गठन किया गया. तब से अब तक कई उठापठक के बावजूद यह समाज पूरी तरह संगठित नहीं हो सका है. 1912 में अरवल ज़िले के बेलखाड़ा में भी इस समाज का पहला बड़ा सम्मेलन हुआ. 1930 में बनारस के विद्वान जे.पी चौधरी ने अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का निर्माण किया जिसमें बिहार, उ.प्र. के कोइरी, दांगी, म.प्र. के काछी, शक्य मौर्य, हरियाणा पंजाब और दिल्ली के सैनी महाराष्ट्र के माली मुताव तथा दक्षिण भारत के अग्निकुला, बन्नी कुला, शंभूकुला, बनियार संगम आदि सब्जी उत्पादक जातियों को शामिल करके इस समाज को राष्ट्रीय फलक देने की शुरुआत हुई.

बिहार में बाद के दिनों में यादव, कुशवाहा और कुर्मी जातियों ने मिलकर त्रिवेणी संघ का निर्माण किया और सामाजिक न्याय आंदोलन की शुरुआत की. त्रिवेणी संघ से यादवों ने काफ़ी लाभ लिया. 1 जून 1968 को धार्मिक कुरीतियों के ख़िलाफ़ कुशवाहा समाज के लोगों ने अर्जक संघ का निर्माण किया. जगदेव प्रसाद ने इस आंदोलन को काफ़ी मज़बूत बनाया. इससे इनकी काफी लोकप्रियता हो गयी और वह बिहारी लेनिन के नाम से जाने लगे. उन्होंने सौ में नब्बे शोषित हैं, नब्बे भाग हमारा है का ज़ोरदार नारा दिया और शोषित समाज दल की स्थापना की. दुर्भाग्य से 1974 में 5 सितम्बर में कुर्था में प्रदर्शन के क्रम में उनकी हत्या कर दी गयी है. बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में इस समाज के सतीश प्रसाद सिंह ने 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक कार्यभार संभाला. आज़ादी के बाद इस समाज के चर्चित मंत्रियों में सहदेव महतो, वासदेव मेहता, सुमित्रा देवी, हरिहर महतो, जय नारायण मेहता, सुखदेव प्रसाद वर्मा, वैद्यनाथ मेहता, जगदेव प्रसाद, रामदेव महतो, शकुनी चौधरी, नागमणि, अशोक कुमार, वसावन भगत, सीता सिन्हा, शिवचरण मेहता, सुचित्रा सिन्हा, वैद्यनाथ महतो, भगवान सिंह, दिनेश प्रसाद, व्यासदेव प्रसाद आदि का नाम शामिल है. वर्तमान राज्य सरकार में रेणु देवी और अवधेश कुशवाहा मंत्री हैं. नए परिसीमन के बाद बिहार में क़रीब 40 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां कुशवाहा की आबादी 25 हज़ार से ज्यादा है तथा 12 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां 25 हज़ार से ज्यादा आबादी तो है किन्तु वह क्षेत्र सुरक्षित हो गया है. करीब 80 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसे यह समाज प्रत्यक्ष रूप से तथा 30 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसे यह समाज अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है. 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू, राजद और भाकपा माले ने 15-15 टिकट इस समाज को दिए थे. बसपा ने 12, कांग्रेस ने 9, भाजपा ने 5 तथा लोजपा ने 3 कुशवाहा प्रत्याशी को चुनावी समर में उतारा था. चुनाव में जदयू के 12 और भाजपा के सभी 5 तथा राजद के दो प्रत्याशी को सफलता मिली थी. पिछले चुनाव में जदयू के लिए सी.पी. सिन्हा ने काफी मेहनत कर सर्वाधिक सीटें जितवाईं, वहीं भाजपा में बालेश्वर भारती एवं सत्येंद्र कुशवाहा, राजद में शकुनी चौधरी और आलोक मेहता, कांग्रेस में नागमणि, बसपा में बबन कुशवाहा तथा लोजपा में राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई थी.

कुशवाहा राजनीति फिर से गर्म होने लगी है. गत चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा एवं प्रेमकुमार मणि ने जदयू में रहकर भी पार्टी के पक्ष में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो उन्हें बाद में निलंबित कर दिया गया. उपेंद्र कुशवाहा व प्रेम कुमार मणि नयी राजनीतिक गोलबंदी करने में लगे हैं . इन दोनों नेताओं की कुशवाहा समाज में बेहद इज्जत है और ये दोनों अपने समाज की पीड़ा को भी बेहतर तरीके से समझ रहे हैं. सत्ता की नब्ज को समझने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह जोड़ी पूरे फॉर्म में आ गई और दूसरे समाज के बड़े नेताओं का भरोसा जीतने में सफल रही तो फिर बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदलनी तय है. उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि गंभीर मंथन जारी है, अमृत ज़रूर निकलेगा. इस समाज के एक बुद्धिजीवी नेता डॉ. राधाकृष्ण सिंह का मानना है कि कुशवाहा समाज को केंद्र में रखकर एक नई पार्टी या गठबंधन बनाकर अगला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए. उधर राजद ने पराजय का मुंह देखने के बाद सम्राट चौधरी को मुख्य विरोधी दल का मुख्य सचेतक तथा लोजपा ने राघवेंद्र सिंह कुशवाहा को प्रधान महासचिव का पद देकर इस जाति का समर्थन अपनी ओर खींचने की कवायद की है. सम्राट चौधरी परबत्ता के विधायक हैं तथा राघवेंद्र सिंह सीतामढ़ी से इस बार के चुनाव 47,000 से ज़्यादा वोट लाकर थोड़े मतों से पराजित हो गए. अर्जुन मंडल जैसे मज़बूत नेता को हाशिये पर डाल देने से भी इस समाज को काफ़ी नुक़सान हो रहा है. मंडल को राज्यभर के कुशवाहा काफ़ी आदर की नज़र से देखते हैं. अपनी ईमानदार छवि के कारण अर्जुन मंडल का युवाओं में काफ़ी प्रभाव है. भगवान सिंह कुशवाहा भी नए तरीके से चार्ज होकर अपने समाज के हित की लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं. कुशवाहा राजनीति का भविष्य तो सुन्दर है किन्तु कुशल और स्थायी नेतृत्व का अभाव इस समाज को सत्ता में उचित हिस्सेदारी नहीं दिला पा रही है. कुशवाहा समाज के नेताओं में आपसी स्वाभिमान में टकराहट का फ़ायदा कई लोगों ने ख़ूब उठाया है. लेकिन अब एक नए अहसास और पूरी तेज़ी के साथ यह समाज गोलबंद हो रहा है. 2012 में होने वाले विधान परिषद और राज्य सभा के चुनाव पर अभी से ही इस समाज के कई नेताओं की पैनी नज़र जमी हुई है. आगामी 5 सितम्बर को शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर कुशवाहा समाज की बहुत बड़ी गोलबंदी होनेवाली है. इसके बाद ही इस समाज की राजनीतिक दिशा स्पष्ट हो सकेगी.

feedback@chauthiduniya.com

कुशवाहा राजनीति फिर से गर्म होने लगी है. गत चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा एवं प्रेमकुमार मणि ने जदयू में रहकर भी पार्टी के पक्ष में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो उन्हें बाद में निलंबित कर दिया गया. उपेंद्र कुशवाहा व प्रेम कुमार मणि नयी राजनीतिक गोलबंदी करने में लगे हैं. इन दोनों नेताओं की कुशवाहा समाज में बेहद इज्जत है और ये दोनों अपने समाज की पीड़ा को भी बेहतर तरीक़े से समझ रहे हैं.

वर्तमान में बिहार के किसी अन्य ज़िलों की तुलना में सबसे अधिक आदिवासी पूर्णिया ज़िले में ही हैं. विशेषकर ग्रामीण इलाकों में अदिवासियों की बहुलता है.

पवन जी के साथ हुआ यह हादसा ऐसी घटना है जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हैं जिसकी सूचना पुलिस को नहीं मिलती.

एक नज़र

विद्या और विनय के प्रतिमान हैं डॉ. शिववंश पाडे

साहित्य साधक और प्रसिद्ध समीक्षक डॉ. शिववंश पाडे, विद्या और विनय के प्रतिमान हैं, उनके जैसा विमल, तरल और सार व्यक्ति इन दिनों दुर्लभ है. उन्होंने एक समीक्षक के रूप अनेकों पुस्तकों पर अपनी विद्वतापूर्ण समालोचना प्रस्तुत कर साहित्य-जगत में न केवल प्रसिद्धि प्राप्त की है बल्कि अपने मूल्यवान विचारों और लेखन से हिन्दी साहित्य की समृद्धि में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है. यह विचार आज यहां बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन में डॉ. पाडे की 75 पूर्ति के अवसर पर प्रकाशित पुस्तक के लोकार्पण के पश्चात अपने उदगार में साहित्कार और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. अनिल सुलभ ने व्यक्त किए. डॉ. सुलभ ने कहा कि लोकार्पित पुस्तक, जिसमें अनके विद्वानों के विचार शामिल हैं, से स्पष्ट होता है कि साहित्य जगत में इनके अवदान को और उनके कृतित्व और व्यक्तिव को किस रूप में रेखांकित किया जाता है. डॉ. सुलभ ने उनके दीर्घायु होने की कामना की. इसके पूर्व समारोह का उदघाटन आचार्य आद्याचरण झा ने तथा पुस्तक का लोकार्पण बिहार विधान परिषद के पूर्वसभापति प्रो. अरुण कुमार ने किया. सभा की अध्यक्षता सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ. जगदीश पाडे ने की. इस अवसर पर जियालाल आर्य, राम उपदेश सिंह विदेह, डॉ. एस.एन.पी. सिन्हा, डॉ. रजन सुरिदेव, एन.एन.गुप्त, डॉ. अमर नाथ सिन्हा, डॉ. ब्रह्मचारी सुरेंद्र कुमार तथा प्रो. रामदेव प्रसाद समेत बड़ी संख्या में विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए तथा डॉ. पाडे को शुभकामनाएं दीं.

डॉ. शिवनारायण बने म.वि.वि. के पीआरओ

अरविंद महिला कॉलेज, पटना के हिन्दी विभाग के प्राध्यापक डॉ. शिवनारायण को मगध विश्वविद्यालय का जनसम्पर्क पदाधिकारी बनाया गया है. हिन्दी के चर्चित युवा साहित्यकार डॉ. शिवनारायण की कहानी, कविता, आलोचना, पत्रकारिता, आदि विषयों पर 29 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. इनकी कार्य क्षमता एवं कार्यप्रणाली को देखते हुए मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरविन्द कुमार ने उन्हें मगध विश्वविद्यालय का पीआरओ बनाया है. इनका मुख्यालय पटना स्थित मगध विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय में रहेगा.

कार्रवाई से महनार में खुशी

मुजफ्फरपुर के आईजी गुप्तेश्वर पांडेय के द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस निरीक्षक बालेश्वर प्रसाद के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने से पूरे वैशाली जिले में खुशी की लहर छायी है एवं स्थानीय लोगों ने वैशाली में भी ऐसे अधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है. विदित हो कि मुजफ्फरपुर के.सी.सी. फर्जीवाड़े में अभियुक्त को बचाने डीएसपी को धमकी देने, आईजी व डीएसपी पर झूठा केस दायर करा वादी का अपहरण कर लेने, मालखाना में गड़बड़ी करने आईजी की हत्या के लिए 25 लाख रुपए सुपारी देने इत्यादि मामले उक्त पुलिस इंसपेक्टर पर दर्ज है. फिलहाल वह जेल में बंद है. लोगों ने पाण्डेय को डीजीपी बनाने की मांग की है.

खगड़िया की सूरत बदलने में लगे मनोहर

खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है. वैसे तो नगर परिषद अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद से ही नगर सभापति मनोहर कुमार यादव ने इलाके का विकास शुरू कर दिया था. लेकिन पेयजल संकट की मार झेल रहे शहरवासियों को इस संकट से छुटकारा दिलाने की उन्होंने ठान ली है. यादव ने सभी वॉर्ड पार्षदों के साथ एक बैठक आयोजित कर यह निर्णय लिया कि अब शहर में कूड़ा कर्कट का ढेर तो नहीं दिखना चाहिए, साथ ही शहर के लोगों को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए नायाब नीति तय की गई है. *-चौथी दुनिया ब्यूरो*

अपराधियों के ख़िलाफ़ सख्त हुआ प्रशासन

खगड़िया ज़िले में बढ़ते अपराध पर क़ाबू पाने के बाबत पुलिस प्रशासन ने सख्त तेवर अपनाने शुरू कर दिए हैं. पहले बैठकें तब होती थी जब अपराध परवान पर होता था लेकिन खगड़िया के नवपदस्थापित जिलाधिकारी पालका सहनी तथा एसपी मिट्ठू प्रसाद ने अपने-अपने मातहतों के साथ मिलकर अपराधियों के मंसूबे फेल करने की ठान ली है. इसके बाबत सभी पदाधिकारियों ने एक बैठक कर यह निर्णय लिया कि सबसे पहले अपराधियों को चिन्हित किया जाय फिर उनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जाए कि अपराध करने के पहले अपराधियों की रूह कांप जाए. *- सूर्यनारायण भारती*

नकली सामानों से महनारवासी परेशान

दो वर्ष पूर्व महनार पुलिस ने वैशाली ज़िला के सहदेई ओ.पी. के सलहा में छापा मार कर एक अवैध फैक्ट्री से नामी-गिरामी कंपनियों के नकली पान-मसाले व अन्य उत्पाद जब्त किए थे. जिसकी क़ीमत एक करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी. तत्पश्चात हाजीपुर की कई दुकानों से भी ये नकली उत्पाद पकड़े गए थे. वर्तमान में पुलिस की सुस्ती के कारण पुन: सलहा में हॉर्लिक्स, विभिन्न कंपनियों के सुगंधित तेल, साबुन, अगरबत्ती खाद्य पदार्थ इत्यादि तैयार किए जा रहे हैं. इसे ब्रांडेड कम्पनी के रैपर में पैक कर बाज़ारों में सप्लाई किया जा रहा है. इसी तरह हाजीपुर में भी नकली शीतल पेय पदार्थों का निर्माण, पैकिंग व मार्केट सप्लाई धड़ल्ले से जारी है. इसकी अधिकतर खपत [illegible] में हो रही है. *-अनुराग परवेज*

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT

- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, which is Govt. of India registered, Regd. No. 03-09284 of 2000-2001.
- ISO 9001:2000 certified, Regd. No. CCPL/QMS/C1487
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where Practicals are conducted.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where one full paper of 100 marks on petroleum is taught.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where students of Industrial Safety Management Course of Patna University & Magadh University get Practical Training.

FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday

Excellent Placement with Handsome Salary

Website: www.psfsm.com

410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001

Ph: 0612-6455019, Mob.: 9334107607, 9835042835, 9234729075

अब कबड्डी में किरकिरी

स्मिता की गुहार पर एमएलसी नीरज कुमार ने विभागीय मंत्री सुखदा पांडेय से पुरस्कार राशि शीघ्र दिलवाने तथा स्मिता से सीधा संपर्क रखने की अपील की. मंत्री की पहल पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्मिता को ग्यारह लाख का चेक दिया. राज्य कबड्डी संघ के सचिव कुमार विजय द्वारा दस लाख मांगे जाने की बात मीडिया में काफ़ी बाद में आई.

दिव्या कुमारी

खेल संघ के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों के बीच विवादों का नाता चोली-दामन का रहा है. पदाधिकारियों पर अक्सर खिलाड़ियों के शोषण का आरोप लगता रहा है, लेकिन बिहार राज्य कबड्डी संघ में जो हालिया विवाद उभरे हैं वो अफसोसजनक होने के साथ-साथ शर्मनाक भी हैं. शर्मनाक इसलिए क्योंकि विवाद ऐसे समय में उभरा है जब बिहार की कबड्डी क्वीन स्मिता कुमारी गोल्डन गर्ल के रूप में चर्चित हुई है और एशियाई कबड्डी स्वर्ण विजेता टीम में बिहार की भी सहभागिता है. चीन के ग्वांगझू में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण विजेता टीम की सदस्य स्मिता कुमारी ने जब राज्य कबड्डी संघ के सचिव कुमार विजय पर दस लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया तो एकबारगी सभी सन्न रह गए. सवालों के घेरे में आए कुमार विजय बचाव की मुद्रा में सामने आए और सिर्फ इतना ही कहा कि स्मिता को राज्य कबड्डी टीम की कप्तानी से हटा दिया गया है इसलिए वह अपने कोच मुकेश कुमार के बहकावे में आकर ऐसा आरोप लगा रही है. [illegible] पांडेय ने मुझ से इतना कहा कि स्मिता ने कभी उनसे ऐसा नहीं कहा. परन्तु [illegible] की तहक़ीक़ात में अब तक जो बातें सामने आई हैं, उससे कुमार विजय पूरी तरह से पाक-साफ़ नहीं हैं. इसमें कोई शक नहीं कि कुमार विजय ने स्मिता को स्थापित करने में लंबी लड़ाई लड़ी है और स्मिता को आगे बढ़ाने में भी कुमार विजय ने महती भूमिका निभाई है. दस लाख के विवाद की पृष्ठभूमि एशियाड खेलों के बाद ही तैयार हो गई थी. गोल्डन गर्ल स्मिता पर इनामी राशि की बौछार हुई थी. महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने दस लाख रुपए और रेल मंत्री ममता बनर्जी ने पंद्रह लाख रुपए दिए थे. [illegible] रेलवे बोर्ड के [illegible] कुमार विजय [illegible] स्मिता ने रुपए देने से इंकार किया [illegible] रेल एकेडमी [illegible] बाद कुमार विजय [illegible] शुरू किया. [illegible] कुमार विजय का फोन [illegible] सरकार ने स्मिता [illegible]

विश्व कप के दौरान भारत-पाकिस्तान मैच के दिन कुमार विजय ने स्मिता को मोइनुलहक स्टेडियम बुलाया [illegible] हुए कहा कि [illegible] महज तीन [illegible] उनके प्रयासों के [illegible] रही है लिहाजा [illegible] हिस्सेदारी है. इसी [illegible] नीरज कुमार को [illegible] एमएलसी ने कुमार विजय को हड़काना चाहा परंतु कोच मुकेश कुमार ने स्मिता के भविष्य का हवाला देकर बीच-बचाव की बात कही. विधान पार्षद नीरज कुमार ने तत्काल विभागीय मंत्री सुखदा पांडेय प्रदेश जदयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और एमएलसी संजय सिंह को सारी बातों से अवगत कराया. इससे पूर्व कुमार विजय ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर एशियाई खेलों का प्रमाण-पत्र भी स्मिता को नहीं दिया था और राज्य सरकार द्वारा घोषित सम्मान समारोह भी टलवा दिया था. स्मिता की गुहार पर एमएलसी नीरज कुमार ने विभागीय मंत्री सुखदा पांडेय से पुरस्कार राशि शीघ्र दिलवाने तथा स्मिता से सीधा संपर्क रखने की अपील की. मंत्री की पहल पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्मिता को ग्यारह लाख का चेक दिया. राज्य कबड्डी संघ के सचिव कुमार विजय द्वारा दस लाख मांगे जाने की बात मीडिया में काफ़ी बाद में आई. इससे पूर्व ही पूरे प्रकरण की जानकारी भारतीय कबड्डी संघ के अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत और सचिव जगदीश्वर यादव को दे दी गई थी. एमएलसी नीरज कुमार ने भी मंत्री, प्रदेश जदयू अध्यक्ष और एमएलसी संजय सिंह को कुमार विजय द्वारा पैसे मांगे जाने की बात कही थी. उस वक़्त तक स्मिता को कप्तानी से नहीं हटाया गया था और ज्योंही कुमार विजय को लगा कि माहौल स्मिता के पक्ष में जा सकता है, उन्होंने तत्काल स्मिता को कप्तानी से हटा दिया था. पूरे प्रकरण पर कुमार विजय का कहना है कि विवाह के पश्चात स्मिता खेल पर ध्यान नहीं दे रही थी जिस कारण उसका प्रदर्षन ठीक नहीं था. इसी आधार पर उसकी कप्तानी छीनी गई. कुमार विजय के अनुसार कप्तानी से वंचित किए जाने पर स्मिता ने ऐसा आरोप लगाया है. ख़राब प्रदर्शन पर कोच मुकेश कुमार कहते हैं कि रांची में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के बाद 7 मार्च को स्मिता की शादी हुई और 17 मार्च को वह जदयू खेल प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित वीर कुंवर सिंह प्रतियोगिता का ट्रायल देने गईं. इस बीच कोई प्रतियोगिता भी नहीं हुई तो फिर प्रदर्शन ख़राब कैसे हो गया. कबड्डी संघ के तटस्थ सूत्रों ने बताया कि वीर कुंवर सिंह प्रतियोगिता में स्मिता को ज़बरन ट्रायल देने को कहा गया. चयनकर्ताओं ने स्मिता का ट्रायल लेने से इंकार कर दिया और टीम में उसको शामिल कर लिया. इस बीच कप्तानी छीन कर मीनू को कमान सौंप दी गई. राज्य महिला कबड्डी टीम के कोच मुकेश कुमार ने सवाल उठाया तो कुमार विजय ने यह सवाल दाग़ कर मुकेश को चुप करा दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम में महेंद्र सिंह धोनी महान हैं या सचिन तेंदुलकर. कुमार विजय ने यह भी कहा कि स्मिता काफी आगे बढ़ चुकी है और अब दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा. कोच मुकेश कुमार कहते हैं कि रांची राष्ट्रीय खेलों में बारह खिलाड़ियों की सूची में कबड्डी खिलाड़ी राजीव कुमार की पत्नी स्मिता और कुमार विजय की बेटी अनुराधा का भी नाम शामिल कराकर मेडल और प्रमाण पत्र दिला दिया गया था ताकि बिहार सरकार की नौकरी दिलाई जा सके. ऐसा इसलिए कि खेल-खिलाड़ियों की प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य सरकार ने मेडल लाओ-नौकरी पाओ की घोषणा कर रखी है. कोच मुकेश कुमार कहते हैं कि जब राजीव की पत्नी का नाम बारह खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया तब वह कथित तौर पर तीन माह की गर्भवती थी वहीं कुमार विजय की बेटी अनुराधा का क़द काफ़ी छोटा है.

स्मिता और राज्य संघ सचिव कुमार विजय के बीच पैदा हुए इस विवाद पर खेलकर्मी हतप्रभ हैं. खेल संघों की राजनीति पर नज़र रखने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते हैं कि कुमार विजय ने बेशक़ दस लाख की निश्चित रकम भले ही न मांगी हो परन्तु उन्होंने यह अवश्य कहा होगा कि ईनामी पुरस्कार राशियों में उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए. स्मिता के दावों की हक़ीक़त पर भले ही आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता परन्तु कुमार विजय पर लगे आरोपों की विस्तृत जांच होनी ही चाहिए ताकि सच से पर्दा उठ सके.

स्मिता के कोच मुकेश कुमार का आरोप

कबड्डी टीम में गर्भवती खिलाड़ी भी शामिल थी

कुमार विजय | मुकेश कुमार | नीरज कुमार

feedback@chauthiduniya.com

समस्तीपुर को चाहिए विकास का रंग

विकास कुमार

सरकारी एवं प्रशासनिक उपेक्षा के कारण नीतीश कुमार के शासनकाल में भी उत्तर बिहार की प्रमुख राजनीतिक स्थली समस्तीपुर को व्यवस्थित ढंग से सजाया संवारा नहीं गया है. पूर्ववर्ती सरकार की तरह नीतीश राज में भी प्रखंड, अनुमंडल, नगर परिशद् एवं नगर निगम बनाने की मुहिम चली लेकिन समस्तीपुर नगर परिशद् आज भी नगर निगम बनने को लालायित है. ज़िला मुख्यालय के अंतर्गत नगर परिशद् समस्तीपुर के अधीन 29 वार्ड हैं, जिसमें वॉर्ड पार्षद का एक पद रिक्त है. बाकी बचे 29 पार्षदों में महिला एवं पुरुष पार्षदों की संख्या 14-14 है. नगर परिषद के स्वरूप में पूर्व मुख्य पार्षद अनीता राम का बदलाव कर पार्षदों ने बिन्दु देवी को नगर की समस्याओं का प्रभार सौंपा लेकिन अनेकानेक विचारणीय बिन्दुओं में से एक भी बिन्दु पर काम न होते देख वॉर्ड पार्षद हतोत्साहित हैं क्योंकि अगले नौ माह के बाद पार्षदों को जनता की अदालत में जाना है.

ज़िला गठन 14 नवम्बर 1972 से लेकर अब तक 38 वर्षों के अंतराल में नगर परिशद् के वॉर्ड पार्षदों का कायाकल्प होता रहा लेकिन समस्तीपुर ज़िला मुख्यालय का शहरी क्षेत्र कई मायनों में पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया. शहर की सड़कें पगडंडी में तब्दील होती जा रही हैं. जन साधारण की बात तो दूर रही अब ज़िला प्रशासन के वाहन भी अतिक्रमणकारियों के रहमोकरम पर चल रहे हैं. नगर परिशद् के नियम क़ानून को ताक पर रखकर शहर में युद्धस्तर पर मार्केट कॉम्पलेक्स एवं कमर्शियल पैलेस का निर्माण हो रहा है. नगर परिषद् से पारित नक्शे पर शहर में शायद ही कोई भवन बना हो या बन रहा हो. वॉर्ड पार्षद एवं नपकर्मी मुट्ठी भर लोगों की कठपुतली बनकर रह गये हैं. अब जबकि ज़िला प्रफ्रसन नगर परिशद् क्षेत्र का कायाकल्प करने को मुश्तैद हुई है तो लोगों को भी इसके लिए इच्छाशक्ति जगानी होगी. ज़िला मुख्यालय का कायाकल्प करने की दिशा में ज़िले के प्रथम जिलाधिकारी सरदार महेंद्र सिंह से लेकर वर्तमान युवा ज़िलाधिकारी कुंदन कुमार की ओर लोग टकटकी लगाए हुए हैं. समस्तीपुर के विधायक अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा विधानसभा में कई बार शहर की जनसमस्याओं पर आवाज़ उठाने के बाद विगत 4 मई को ज़िलाधिकारी कुंदन कुमार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना सेतु योजना, शहरी विकास योजना एवं सड़क निर्माण की समीक्षा बैठक में नगर परिशद् क्षेत्र की सर्वाधिक विकट जल जमाव की समस्या से निपटने का ऐलान किया है. उन्होंने जल निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम की बात कही है. जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन, बस स्टैण्ड एवं विभिन्न बाज़ारों आदि का जीर्णोद्धार किया जाएगा. ज़िलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को नगर का कायाकल्प करने में जी-जान से जुटने को कहा है. उन्होंने सड़कों, गलियों, नालियों आदि को सूचीबद्ध करते हुए इसके कायाकल्प हेतु चालू वित्तीय वर्ष में योजनाबद्ध रूप से काम करने हेतु तत्पर रहने को कहा है. नगर के कायाकल्प की रूपरेखा बनने की घोषणा के बाद नगर के लोगों, वॉर्ड पार्षदों एवं व्यवसायी वर्ग में सरगर्मी देखी जा रही है. अबतक नगर को व्यवस्थित करने में बाधक रही सड़कें , गलियों के साथ साथ सफेदपोश एवं दबंग लोगों की सूची भी बन रही है. नगर परिषद् द्वारा निर्मित मार्केट कॉम्पलेक्सों, सार्वजनिक स्थलों की भी सुधि ली जा रही है. गर्मी में पेयजल संकट बढ़ रहा है. ऐसे में समाधान जल्द ही तलाशने होंगे.

अनीता राम (पूर्व मुख्य पार्षद)

बिन्दु देवी (मुख्य पार्षद)

अख्तरूल इस्लाम शाहीन (विधायक समस्तीपुर)

feedback@chauthiduniya.com

आदिवासी कैसे भरेंगे नगर निगम का टैक्स?

नीरज सिंह

अंग्रेजी हुकूमत में पूर्णिया ज़िला दार्जिलिंग से लेकर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर तक फैला था और पूर्णत: वनों से ढका था, इसी कारण इस क्षेत्र का नाम पूर्ण+आरण्य शब्दों से मिलकर पूर्णिया पड़ा. यहां की अधिकतर जनसंख्या और संस्कृति आदिवासियों की थी. आदिवासियों का मुख्य पेशा आखेट और कृषि कार्य था एवं इस क्षेत्र में कालाजार व मलेरिया जैसी बीमारी का गंभीर प्रकोप था. इसीलिए इस क्षेत्र को कालापानी का क्षेत्र कहा जाता था. तत्कालीन सरकारी महकमे द्वारा इस क्षेत्र में सज़ा के तौर पर किसी व्यक्ति को पदास्थापित किया जता था. लेकिन बदलते परिवेश में यहां की संस्कृति क्षेत्र में बदलाव आया और मूल पूर्णिया ज़िले का कई बार विखण्डन हुआ. जहां सत्तर के दशक में बंगाल को पूर्णिया का उत्तरी पूर्वी भाग दे दिया गया वहीं कटिहार, किशनगंज, अररिया का निर्माण हुआ. इस तरह से वर्तमान पूर्णिया का क्षेत्रफल मात्र 3202.31 वर्ग किमी. बचा. वर्तमान में बिहार के किसी अन्य ज़िलों की तुलना में सबसे अधिक आदिवासी पूर्णिया ज़िले में ही हैं. विशेषकर ग्रामीण इलाकों में अदिवासियों की बहुलता है. आज भी यहां के आदिवासियों के जीवन स्तर में कोई खास बदलाव नहीं आया है. मजदूरी, कृषि, घोंघे सितुवे चुनकर खाना इनका मुख्य पेशा है. आज भी इनका जीवनस्तर काफी निम्न है. ऐसे में बिहार सरकार द्वारा इन अशिक्षित आदिवासियों को नगर निगम में समेट लेना नाइंसाफी होगी क्योंकि जो लोग अपने दो जून की रोटी नहीं जुटा पाते हो भला वे नगर निगम का टैक्स शब्द का अर्थ ही क्या समझेगें और पेट की क्षुदा बुझाने के बजाए निगम टैक्स कहां से भरेंगे. मालूम हो कि सुशासन की सरकार ने 26 मई 2009 को पूर्णिया को नगर निगम बनाने की घोषणा कि थी जिसमें शहर के बगल की पांच पंचायतों में हंसदा, अब्दुल्लानगर, बेलौरी, मरंगा पूर्व, मरंगा पश्चिम को शामिल किया गया. 14 फरवरी 2010 को नगर निगम का चुनाव कराया गया, जिसमें ये पंचायतें भी शामिल थी. पुन: पंचायत के जन प्रतिनिधियों के द्वारा पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की गई, जिसमें नवनीत प्रसाद सिंह की एकल पीठ ने अपील पर सुनवाई करते हुए नगर निगम की अधिसूचना को रद्द करते हुए निगम के लिए कराये गये चुनाव परिणाम पर रोक लगा दी. उधर नगर निगम को लेकर पूर्व नगर अध्यक्ष साहिद राजा ने पुन: अपील दायर की. परिणामस्वरूप मामला हाइकोर्ट पहुंचा. मामले की सुनवाई के उपरांत डबल बेंच ने पंचायत चुनाव के ऐन मौके पर पूर्णिया को नगर निगम बनाने के पक्ष में निर्णय दिया.

इस निर्णय से पूर्णिया समेत पांचों पंचायत के लोगों के बीच तरह-तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. क्या पांचों पंचायत की ग़रीब जनता नगर निगम के टैक्स भरने में सक्षम है क्योंकि वर्तमान में इनमें से हंसदा जैसी पंचायतों की 70 प्रतिशत जनता घास-फूस, बांस से बनी झोपड़ियों में रह रही है और मजदूरी घोंघे, सितुअे खाकर अपना जीवन यापन कर रही है. वहीं नगर निगम बनने से दु:खी पंचायत चुनाव में भाग्य आज़मा रहे उम्मीदवारों के सामने भी दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है. इनका कहना है कि कोर्ट में मामला लम्बित रहने के कारण किसी भी प्रकार के चुनाव को कोर्ट के निर्णय आने तक स्थगित रखा जाना चाहिए था और इन लोगों ने भी न्यायालय की शरण में जाने का मन बना लिया है. जिला परिषद् क्षेत्र सं. 24 एवं 25 के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो गये है, क्योंकि क्षेत्र सं. 24 का निर्माण 7 पंचायतों को मिलाकर किया गया है जिसमें मरंगा पूर्व एवं मरंगा पश्चिम शामिल हैं, वहीं क्षेत्र सं. 25 में 6 पंचायत शामिल हैं जिसके अन्तर्गत हंसदा, बेलौरी एवं अब्दुल्लानगर को नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव है. इन हालातों में आदिवासियों की ओर से लड़ने वाला कोई नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

वर्षों से लटकी है ददौल घाट बैराज योजना

वर्ष 1987 के बाढ़ में तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली के समीप मुरौल गांव में बुढी गंडक तटबंध टूटने से मुजफ्फरपुर ज़िले का सकरा तथा वैशाली ज़िले के पातेपुर प्रखंड में जानमाल की जो हानि हुई, उससे कहीं अधिक विध्वंस समस्तीपुर ज़िले में हुआ. सात लाख से ज़्यादा की आबादी प्रभावित हुई तथा करोड़ो रुपयों की फ़सल बर्बाद हो गई, हज़ारों मकान ध्वस्त हो गए. जानकारों का कहना है कि यदि ददौल घाट बैराज योजना को पूरा कर नून नदी तटबंध के साथ ही सुल्तानपुर नून नदी लिंक चैनल योजना पूरी हो जाती, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया.

अफजल ईमाम मुन्ना

बूढ़ी गंडक की विभीषिका से उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों को बचाने के लिए ददौल घाट पर बैराज बनाने की महत्वाकांक्षी योजना वर्षों से खटाई में पड़ी है. इस संबंध में सिंचाई विभाग के समस्तीपुर स्थित मास्टर प्लांनिग अंचल ने एक विस्तृत योजना तैयार कर वर्ष 1983 में बिहार सरकार को सौंपी थी. लेकिन 28 वर्षों में भी यह कार्य पूरा नहीं हो सका है. फलस्वरूप लोगों में काफ़ी रोष है. राजद नेता फैजुर रहमान फैज ने ददौल घाट बैराज योजना को जल्द पूरा करने की मांग वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की है. उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरा होने से इस क्षेत्र के लोगों को सिंचाई के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था होगी.

ज्ञात हो कि वर्ष 1987 के बाढ़ में तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली के समीप मुरौल गांव में बूढ़ी गंडक तटबंध टूटने से मुजफ्फरपुर ज़िले का सकरा तथा वैशाली ज़िले के पातेपुर प्रखंड में जानमाल की जो हानि हुई, उससे कहीं अधिक विध्वंस समस्तीपुर ज़िले में हुआ. सात लाख से ज़्यादा की आबादी प्रभावित हुई तथा करोड़ो रुपयों की फ़सल बर्बाद हो गई. हज़ारों मकान ध्वस्त हो गए. 39 लोगों की मृत्यु बाढ़ के पानी में डूबने से हो गई थी. जानकारों का कहना है कि समस्तीपुर ज़िले की इस बर्बादी को बचाया जा सकता था यदि ददौल घाट बैराज योजना को पूरा कर नून नदी तटबंध के साथ ही सुल्तानपुर नून नदी लिंक चैनल योजना पूरी हो जाती. लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. वैसे नून नदी परियोजना पर वर्तमान में कार्य जारी है लेकिन ददौल घाट बैराज योजना अब भी खटाई में पड़ी हुई है. ग़ौरतलब है कि बूढ़ी गंडक नदी हर वर्ष बरसात में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय सहित खगड़िया ज़िलों में प्रलंयकारी बन जाती है. करोड़ों की संपत्ति के साथ-साथ सैकड़ों जानें हर वर्ष इस नदी में समा जाती है. बाढ़ सहायता एवं बचाव कार्य के नाम पर भी हर वर्ष सरकारी राजस्व की भारी बर्बादी होती है.

इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण के उद्देश्य से सरकार ने अनुसंधान एवं योजना कार्य के लिए समस्तीपुर में एक अधीक्षण अभिज्ञयंता को पदस्थापित किया. इस अंचल के अधीन समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया आदि का क्षेत्र है. इसी अंचल ने समस्तीपुर से 23 मील पश्चिम बूढ़ी गंडक के ददौल घट पर 39.35 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले बैराज योजना का प्रारंभिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को 28 वर्ष पूर्व 1983 ईसवी में सौंपा था. इस योजना के कार्यान्वयन से 3.85 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि के सिंचित होने का अनुमान लगाया गया था. साथ ही मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय तथा खगड़िया ज़िलों की बाढ़ से योजनाबद्ध ढंग से सुरक्षा होती. इतना ही नहीं, इस योजना से पनबिजली उत्पादन की भी संभावना थी. 28 वर्ष पूर्व बनी इस योजना की फाइल अब तक दफ्तरों में उपेक्षित पड़ी है, लेकिन सिंचाई विभाग के समस्तीपुर स्थित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं.

इस क्षेत्र की जनता को सुशासन की सरकार के नाम पर दूसरी पारी खेलने वाले बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल वर्तमान जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी पर भरोसा है कि वह इस योजना को जल्द शुरू कराने की दिशा में पहल करेंगे. अब देखना है कि समस्तीपुर ज़िले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक एवं राज्य के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ददौल घाट बराज योजना की शुरुआत कब तक कराते हैं या वह भी पूर्व जल संसाधन मंत्रियों की तरह उक्त योजना को नज़र अंदाज़ कर देंगे. यह तो आनेवाला वक़्त ही बतायेगा.

विजय कुमार चौधरी

feedback@chauthiduniya.com

पटना- सहरसा ट्रैक

रेल यात्रा में लफंगों का उत्पात

पवन जी पटना जंक्शन से सहरसा आनेवाली कोसी एक्सप्रेस में बैठते हैं कि एक असामाजिक तत्व उनकी पत्नी पर फब्ती कसने लगता है. मना करने पर वह उससे उलझ जाता है, धमकी देता है. मोबाइल निकालता है और अपने सहयोगी से बात करता है. रेल खुशरूपुर पहुंचती है. वहां उसका सहयोगी आ धमकता है और शुरू होती है पवन जी की पिटाई. ये लोग उनकी पत्नी की गर्दन से सोने की चेन भी छीनते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं.

मनोज ठाकुर

पवन जी सहरसा के विद्यापति मोहल्ले के रहने वाले हैं. 30 अप्रैल को वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ दीदी यानी ममता बनर्जी की रेल में पटना जंक्शन पर सवार हुए और सुशासन बाबू के बाढ़-बख्तियारपुर के क्षेत्र खुशरूपुर आते आते पीट डाले गए. पवन जी कोई गंवार जाहिल व्यक्ति नहीं है. वह बैंगलोर में इंजिनियर हैं और एक-दो महीने में विदेश जाने वाले हैं. वह पटना जंक्शन से सहरसा आनेवाली कोसी एक्सप्रेस में बैठते हैं कि एक असामाजिक तत्व उनकी पत्नी पर फब्ती कसने लगता है. मना करने पर वह उससे उलझ जाता है, धमकी देता है. मोबाइल निकालता है और अपने सहयोगी से बात करता है. रेल खुशरूपुर पहुंचती है. वहां उसका सहयोगी आ धमकता है और शुरू होती है पवन जी की पिटाई. ये लोग उनकी पत्नी की गर्दन से सोने की चेन भी छीनते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं. इसी बीच आते हैं टीटी बाबू सुरेश महतो उलटे पवन जी को समझाते हैं कि इन लोगों से न लगिए ये गुंडे, बदमाश हैं. वह फोर्स को नहीं बुलाते. असंतुष्ट रहने पर पवन जी सहरसा स्टेशन आने के बाद राजकीय रेल थाने के थाना अध्यक्ष को अपनी आपबीती का एक लिखित आवेदन सौपतें हैं जिसे वहां के मुंशी राजीवन रंजन सिंह प्राप्त करते हैं और पवन जी को इसका प्राप्ति रशीद भी देते हैं.

कई दिन बीत चुके लेकिन कोई कार्रवाई किसी भी स्तर से नहीं हुई. इस संबंध में सहरसा जीआरपी थाने के थाना अध्यक्ष हरि राम कहते हैं कि आवेदन पटना एसआरपी को अग्रसारित किया गया है, साथ ही एक प्राथमिकी संख्या 00/11 दर्ज की गई है. यानी कम से कम प्राथमिकी दर्ज हो गई है. पवन जी के साथ चलने वाले किसी यात्री ने इस अभियुक्त का चेहरा भी कैद कर लिया है तो भी कारवाई नहीं हो पाई है.

ये तो ऐसी घटना है जिसकी सूचना पूलिस को दी गई है लेकिन कई ऐसी घटनाएं हैं जिसकी सूचना पुलिस को नहीं मिलती. इस घटना के संबंध में जब एसआरपी कटिहार शुकन पासवान से सम्पर्क साधा गया तो उन्होंने कहा कि इसे एसआरपी पटना को अग्रसारित कर दिया गया है अब कारवाई एसआरपी पटना के स्तर पर की जाएगी. यानी अग्रसारण का खेल चल रहा है, लेकिन कारवाई नहीं हो रही है.

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार बढ़ेगा
देश बढ़ेगा

विकास के पथ पर अग्रसर बिहार

भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने हेतु
कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री
श्री नीतीश कुमार एवं
माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी
और गठबंधन के तमाम मंत्री, विधायक, कार्यकर्तागण
को
हार्दिक बधाई

अपना बिहार
बढ़ता बिहार

सहदेव साह
वरिष्ठ नेता, जनता दल यूनाईटेड
महनार विधान सभा क्षेत्र

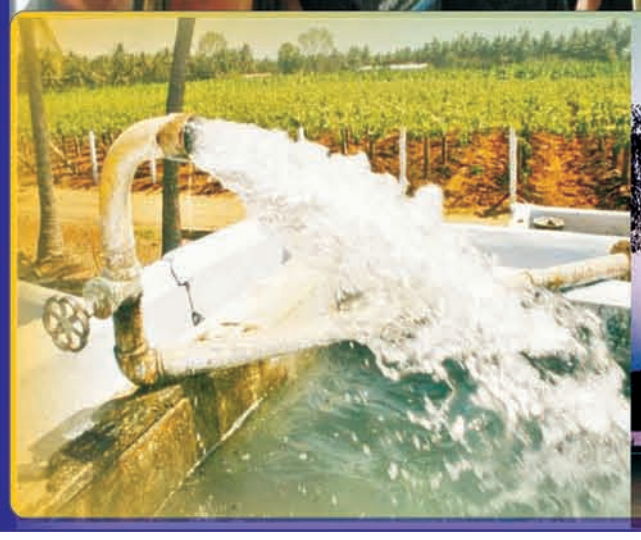

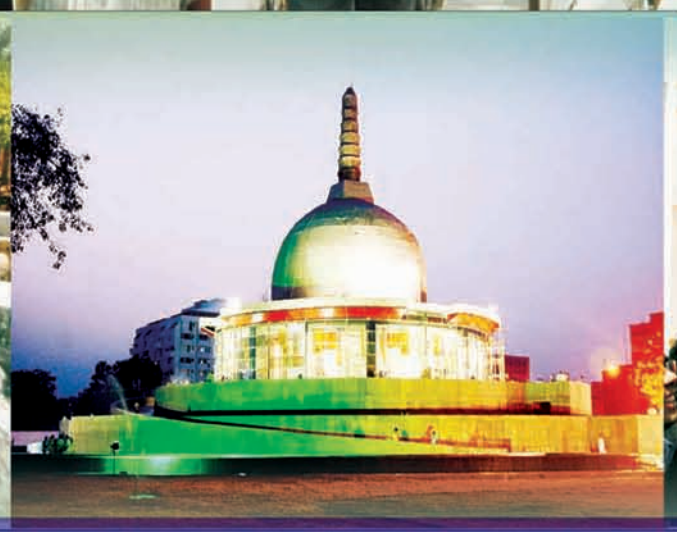

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 23 मई–29 मई 2011

www.chauthiduniya.com

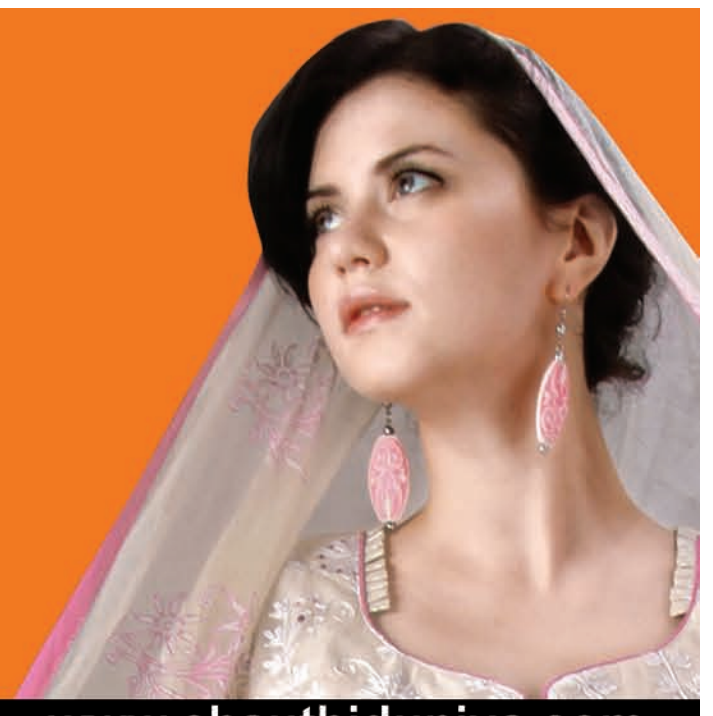

ज़मीन के लिए ख़ूनी खेल

जनसंख्या के दबाव के तहत सरकार एक्सप्रेस–वे और टाउनशिपों का बनना ज़रूरी समझती है तो क्या वह यह ज़रूरी नहीं समझती कि जो खेत ख़त्म हो रहे हैं उनकी पूर्ति के लिए नए खेत भी बनें. यह सवाल केवल उत्तर प्रदेश सरकार से ही नहीं, पूरे देश और प्रदेशों के राजनीतिक आक़ाओं से भी है.

राजेंद्र सारथी

ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़ और आगरा के बाद राज्य के अन्य स्थानों पर भी किसान आंदोलन की आग भड़क सकती है, क्योंकि लखनऊ, फ़ैज़ाबाद और आज़मगढ़ में भी ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. किसानों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के सामने दस जून को महापंचायत बुला रखी है. आज़मगढ़ का मामला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दरबार तक जा पहुंचा है. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्रबंधनगर योजना–1 के लिए 451.218 हेक्टेयर और प्रबंधनगर योजना–2 के लिए 324.633 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की है. सरकार इस भूमि का मुआवज़ा 4.50 से 7.50 लाख रुपये प्रति बीघा दे रही है, जबकि किसानों की मांग 40 लाख रुपये प्रति बीघे की है.

उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार 1187 गांवों की 2.37 लाख हेक्टेयर भूमि में फैली हुई यमुना एक्सप्रेस–वे की महत्वाकांक्षी योजना को अगले विधानसभा चुनाव से पूर्व पूरा कराने में जी–जान से लगी हुई थी. इसके लिए उन्होंने अपने सिपहसालारों को विशेष निर्देश दिए हुए थे. विधानसाभा चुनाव 2012 में होने हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा जनपदों में उग्र किसान आंदोलन देश की राजनीति में फिर से किसान राजनीति को गरमा देगा. प्रदेश सरकार का कहना है कि उसने किसानों को 33 वर्ष के लिए प्रति एकड़ 20 हज़ार रुपये की वार्षिकी और कुल ज़मीन का 7 प्रतिशत भाग रिहायशी प्लॉट देकर उनके हितों का ध्यान रखा है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इस मुआवज़े से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राज्य सरकार और यमुना एक्सप्रेस–वे से जुड़ी रीयल एस्टेट कंपनी के बेतहाशा मुनाफ़ों के मुक़ाबले उनके मुआवज़े कुछ भी मायने नहीं रखते. 2002 में ग्रेटर नोएडा के 124 गांवों के किसानों से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेस–वे बनाने के लिए 50 रुपये से 300 रुपये वर्गमीटर की दरों से ज़मीन अधिग्रहित की थी. आज इसी इलाक़े में स्पोर्ट्स सिटी में रिहायशी ज़मीन 15000 रुपये वर्गमीटर बेची जा रही है यानी जिस किसान ने इस समय अपनी ज़मीन एक्सप्रेस–वे के लिए दी थी. यदि वह किसान अपनी रक़म में इतने वर्षों का ब्याज़ जोड़कर उससे ग्रेटर नोएडा में अपनी ज़मीन का 1/10 हिस्सा भी नहीं ख़रीद सकता. ग्रेटर नोएडा में रिहायशी ज़मीन की आधिकारिक दरें वर्तमान में 15, 840 रुपये से 42, 560 रुपये वर्गमीटर हैं. वाणिज्यिक उपयोग के लिए ही दरें 60, 500 रुपये से 1.37 लाख वर्गमीटर हैं. समस्या यह है कि आज खेती संकट के दौर से गुज़र रही है. अनाज को रखने के लिए अभी तक गोदाम नहीं बन सके हैं. फल–सब्ज़ियों को बचाने के लिए वातानुकूलित स्टोरेज की व्यवस्था तक नहीं है. किसानों के साथ विकास के नाम पर मजाक हो रहा है. गांवों में आप स्कूल, सड़क, पेयजल और बिजली की हालत देख लीजिए. किसानों के बच्चों और महानगर के बच्चों के शिक्षा के स्तर में ज़मीन–आसमान का अंतर है. विकास के नाम पर किसानों की ज़मीन मनमानी शर्तों पर ली जा रही है. आख़िर क्यों? किसान अपनी ज़मीन बेचे या न बेचे यह निर्णय उसे ख़ुद क्यों नहीं लेने दिया जाता? विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रलोभनों के झांसे देकर किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है और उसकी ज़मीन ली जा रही है.

जनसंख्या के दबाव के तहत सरकार एक्सप्रेस–वे और टाउनशिपों का बनना ज़रूरी समझती है तो क्या वह यह ज़रूरी नहीं समझती कि जो खेत ख़त्म हो रहे हैं उनकी पूर्ति के लिए नए खेत भी बनें. यह सवाल केवल उत्तर प्रदेश सरकार से ही नहीं, पूरे देश और प्रदेशों के राजनीतिक आक़ाओं से भी है. जिस अनुपात में आज कंक्रीट के जंगल खड़े करने के लिए भूमि अधिग्रहित कराई जा रही है. क्या उसी अनुपात में सरकारें बीहड़, ऊसर, सेम से प्रभावित भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने की कार्रवाई भी कर रही हैं? समस्या के मूल में यही कारण है. इसी भयावह कल्पना से किसान अपनी भूमि बेचकर उजड़ना नहीं चाहता. उन्हें मालूम है कि ज़मीन उनके पास है तो परिवार का पेट पालने का साधन उनके पास है. वह अपनी भूमि को रुपये में बदल लेगा तो रुपया जिस तेज़ी से आएगा उसी तेज़ी से वह ख़र्च भी हो जाएगा. भूमि बेचकर भूमि वह ख़रीद नहीं सकता, चूंकि भूमि है ही नहीं. यदि सरकार ने ध्यान देकर बीहड़, ऊसर और सेम प्रभावित भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने का अभियान चलाया होता तो वह किसानों को भूमि के बदले भूमि और विस्थापन मुआवज़ा देकर आसानी से समस्या को सुलझाया जा सकता था.

केंद्र और राज्य की सरकारों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि किसी भी प्रदेश में किसान की भूमि का तभी अधिग्रहण किया जाए जब उसे भूमि के बदले भूमि और विस्थापन मुआवज़ा दिया जाए. दूसरी बात यह कि यदि कोई किसान भूमि नहीं बेचना चाहता तो यह उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार होना चाहिए. यह नहीं कि वहां तानाशाही चलाई जाए. राज्य का क़ानून वहां तो तानाशाही दिखा सकता है, जहां समाजोपयोगी कार्य हो रहा हो और उसमें समाज के एक–दो लोग आड़े आ रहे हों, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है. सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर की यह मांग जायज़ है कि भूमि अधिग्रहण क़ानून को रद्द किया जाना चाहिए. चूंकि भूमि अधिग्रहण को लेकर भारत में कई जगह आंदोलन हो रहे हैं और लोग गुस्से में हैं. किसानों, आदिवासियों से जो ज़मीनें छीनी जा रही हैं, इसमें राजनेता, नौकरशाह, बिल्डर और कांट्रेक्टर शामिल हैं. मौजूदा क़ानून ब्रिटिश राज से भी बदतर है. ब्रिटिश क़ानून में कम से कम भूमि सार्वजनिक हित के कामों के लिए अर्जित करने का प्रावधान था, लेकिन प्रस्तावित स्वरूप में ज़मीन अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक हित की परिभाषा बदल दी गई है और निजी हितों को सार्वजनिक हित बताया जा रहा है. नागरिक से ज़मीन छीनना भी हिंसा का एक रूप है. सवाल यह भी है कि खेती की ज़मीन पर यूं ही उद्योग बनते रहे तो देश में एक दिन खाद्य सुरक्षा का ख़तरा पैदा हो जाएगा. अत: ज़मीन अधिग्रहण बिल के लिए कड़े मसौदे की ज़रूरत है.

सरकार ने समझौतों पर भी नहीं किया अमल

1. यह लिखित समझौता था कि टाउनशिप के लिए भूमि ज़बरदस्ती नहीं ली जाएगी. क़रार न करने वालों के प्रत्यावेदन पर क़ानूनी रूप से ज़मीन वापस करके उनके नाम दर्ज होगी, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि तानाशाही और दिखाई गई.

2. किसान क़रार कैंसिल कर भूमि वापसी के लिए लिखित प्रत्यावेदन कर सकेंगे. मुआवज़ा ले चुके हैं तो देय राशि के पेऑर्डर जमा करेंगे. इस संबंध में मंडल स्तरीय समिति प्रत्यावेदन पर संस्तुति करके राज्य समिति को भेजेगी. इस संबंध में प्रशासन और जेपी ग्रुप दोनों ने चुप्पी साध रखी है.

3. क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की क्षतिपूर्ति को अतिरिक्त राशि शासनादेश 19 अगस्त 2010 के अनुसार दी जाएगी, जो अभी तक नहीं मिली है.

4. यमुना एक्सप्रेस–वे के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवज़ा बढ़ाने के लिए शासन से संस्तुति की जाएगी, लेकिन यह संस्तुति नहीं की गई.

5. शासनादेश 19 अगस्त 2010 के अनुसार अगस्त में आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुक़दमे समाप्त किए जाएंगे, लेकिन अभी तक ये मुक़दमे वापस नहीं किए गए.

एक्सप्रेस–वे प्रोजेक्ट के भूमि अधिग्रहण

1. एक्सप्रेस–वे मेन रोड के तहत कुल अधिग्रहण में से 15 गांवों की 157.3852 हेक्टेयर भूमि आ रही है. इसके लिए अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है.

2. एक्सप्रेस–वे इंटरचेंज (अप–डाउन आने–जाने को सड़क) के तहत कुल अधिग्रहण में से तीन गांवों की 21.2815 हैक्टेयर भूमि आ रही है. यह अधिग्रहण भी पूरा हो चुका है.

3. एक्सप्रेस–वे फैसिलिटी के तहत कुल अधिग्रहण में गांव चौगान की 8.5 हेक्टेयर भूमि आ रही है. यह अधिग्रहण भी पूरा हो चुका है.

4. एक्सप्रेस–वे प्रोजेक्ट के तहत आगरा के 15 गांवों की 703.5311 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है.

5. एक्सप्रेस वे सर्विस रोड के तहत अधिग्रहण में से तीन गांचों की 10.6118 हेक्टेयर भूमि आ रही है. यहां केवल एक किसान से क़रार होना शेष रह गया है.

6. एक्सप्रेस–वे टाइनशिप के तहत कुल अधिग्रहण में से तीन–चार गांवों की 491.1715 हेक्टेयर भूमि आ रही है. ज़्यादातर अधिग्रहण हो चुका है, क़रीब 28 हेक्टेयर भूमि का अभी अधिग्रहण शेष रह गया है. इसमें से 18 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण छलेसर और 10 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण चौगान में किया जाना है.

एक्सप्रेस-वे मामले में अबतक हुए आंदोलन

- 16 अगस्त 2010 को पहली बार चौगान में अधिग्रहण के ख़िलाफ़ भड़की आग. ख़ूब तोड़फोड़ हुई, दो राइफलें लूट ली गईं.
- 17 अगस्त को अगले दिन पुलिस और ग्रामीणों के बीच ख़ूनी संघर्ष, सीओ–एसीएम समेत कई घायल, हवाई फायरिंग और आगज़नी हुई.
- 18 अगस्त 2010 को हाइवे पर भड़की आग, जाम के दौरान बवाल, कैबिनेट सचिव शशांक शेखर समझौते की पेशकश लेकर आगरा पहुंचे, मगर समझौता नहीं हो सका.
- 19 अगस्त 2010 को नोएडा से आगरा तक मुआवज़े की मांग को लेकर धरना शुरू.
- 20 अगस्त 2010 को कांग्रेस और रालोद किसानों के साथ आए.
- 22 अगस्त 2010 को हाइवे पर उतरे किसान, पथराव से मची अफ़रातफ़री.
- 23 अगस्त 2010 को धरनास्थल पर किसानों ने सामूहिक रूप से सिर मुंडवाया.
- 24 अगस्त को बुद्धि-शुद्धि यज्ञ.
- 25 अगस्त 2010 को फिर भड़की विरोध की आग. ग्रामीणों ने हाइवे पर कई वाहन फूंके. फायरिंग, पथराव. चार घंटे तक हाइवे पर यातायात ठप.
- बवाल में चार सौ ग्रामीणों के ख़िलाफ़ संगीन धाराओं में मुक़दमा, तीन जेल भेजे.
- 1 सितंबर 2010 को किसानों ने ख़ून से लिखी राष्ट्रपति को पाती.
- 3 सितंबर 2010 को सरकार के दूत बनकर किसानों के बीच पहुंचे उद्यानमंत्री, लेकिन बात नहीं बनी.
- 6 सितंबर 2010 को मुआवज़े की रक़म बढ़ाए जाने के साथ समझौता. तत्कालीन डी.एम. अमृत अभिजात ने तुड़वाया अनशन.

feedback@chauthiduniya.com

देश भर में किसी भी राजनीतिक दल को पूरे वर्ष कार्यक्रम चलाने के लिए काफ़ी धन की ज़रूरत होती है. एक रिपोर्ट के अनुसार प्रचार एवं यात्रा के मामले में भाजपाई नेता कांग्रेसियों से आगे दिखाई देते हैं.

मृतक के परिजन जो स्वयं भी पुलिसकर्मी हैं, की भी अनसुनी और अनदेखी कर रही है तो ऐसे में सामान्य पीड़ितों के साथ पुलिस का रवैया कैसा होता होगा समझा जा सकता है.

एक नज़र

पानी से हैपेटाइटिस और कैंसर का क़हर

मुज़फ़्फ़रनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव बोपाड़ा में प्रदूषित जल जानलेवा बनता जा रहा है. इस जल से हैपेटाइटिस व कैंसर जैसी घातक बीमारियां लोगों को लगातार अपनी चपेट में ले रही हैं. पिछले दिनों दो मरीज़ों की मौत हो गई और कई लोग इन बीमारियों से प्रभावित हैं. प्रशासन को कई बार इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन समस्या के निवारण के लिए अभी तक कोई क़दम नहीं उठाया गया. ग्राम प्रधान अरविंद कुमार का कहना है कि गांव के पास से निकल रहे गंदे नाले में फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषित जल बहता है. इससे गांव के सभी हैंडपंप व ट्यूबवैल आदि का पानी प्रदूषित हो गया है. यदि शाम को पानी भरकर रख दिया जाता है तो सुबह तक वह पीला हो जाता है. पिछले वर्ष डल्ल्यूएचओ व प्रशासनिक टीम ने भी गांव के पानी के सैंपल लिए थे व तत्कालीन कमिश्नर सुरेश चंद्रा का भी आगमन हुआ था. ग्रामीणों ने उनके सामने भी इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था. ग्रामीणों ने गांव में पानी की टंकी बनाने तथा गंदे नाले को पक्का कराने की मांग की थी जिससे रिस कर पानी नीचे ज़मीन में न जा सके. पिछले सप्ताह गांव के रामकुमार व हरपाल जो हैपेटाइटिस से पीड़ित थे, उनकी मौत हो चुकी है. उन्होंने अपना इलाज कई बड़े अस्पतालों में कराया, लेकिन वे ठीक नहीं हो सके. इस समय गांव के सोम, भंवरसिंह, संजय, अमित, पप्पन, विपिन, आदि कई ग्रामीण हैपेटाइटिस से पीड़ित हैं. चिकित्सकों ने प्रदूषित जल से बीमारियों का होना बताया है. डॉक्टर एस.के. गोयल का कहना है कि गांव का पानी प्रदूषित है तथा उनके पास हैपेटाइटिस से प्रभावित काफ़ी मरीज़ आ रहे हैं.

वाहन चोरी रोकने के लिए जीपीएस लगवाएं

नोएडा में पुलिस पब्लिक के बीच साझेदारी बढ़ाने के लिए पिछले दिनों सेक्टर 50 कम्युनिटी सेंटर में एक मीटिंग की गई. इसमें एसपी अलंकृता सिंह और सेक्टर 49 थाने के एसएचओ अभय प्रताप सिंह और आरडब्ल्यू पदाधिकारी मौजूद थे. लोगों की शिकायत सुनने के बाद एसपी ने कहा कि वाहन चोरी से निपटने के लिए प्रत्येक घर के सामने पुलिसकर्मी तो तैनात नहीं किया जा सकता. अगर लोग अपने वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगवा लें तो चोरी होने के बावजूद गाड़ी को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढना आसान हो सकता है. उन्होंने लोगों को इमरजेंसी कॉल सिस्टम के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि इस सिस्टम में 20 परिचितों के नंबर अपने मोबाइल में फीड कर के आपातकाल में उन्हें ख़तरे का मैसेज भेजा जा सकता है. उन्होंने सेक्टर में आने वाले कबाड़ियों, धोबियों और अन्य नौकरों का हमारी सुरक्षा संस्था के ज़रिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की सलाह भी दी.

सेनानी को प्रशासन ने सम्मान नहीं दिया

जौनपुर के बदलापुर क्षेत्र के गांव डोमपुर कठार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लालता प्रसाद के निधन के बाद प्रशासन की ओर से तिरंगा झंडा नहीं लाया गया और न गार्ड ऑफ ऑनर ही दिया गया. इस कारण स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोग भड़क उठे. बताते हैं कि सेनानी के निधन के बाद तहसील प्रशासन के अधिकारी उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन वे साथ में तिरंगा नहीं लाए थे. इससे सेनानी के पुत्र सुरेंद्र दुबे भड़क उठे और प्रशासन को कोसने लगे. इसके बाद वे स्वयं तिरंगा झंडा ख़रीद कर लाए और पिता के पार्थिव शरीर पर समस्मान चढ़ाया. इस बात को लेकर क्षेत्र के लोगों में भी आक्रोश देखा गया. स्वर्गीय दुबे को गार्ड ऑफ ऑनर न देने पर भी लोगों में गुस्सा देखा गया. उल्लेखनीय यह है कि पुलिस के जवान गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए आए तो थे, किंतु गार्ड ऑफ न देने का कारण उन्होंने सूर्यास्त होना बताया.

कॉलेजों की डिटेल ऑन लाइन होगी

अगले सत्र से उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेजों की जानकारी छात्रों को बेवसाइट के ज़रिए मिल जाया करेगी. इसके लिए कॉलेजों को बेवसाइट तैयार करने और इसमें कॉलेज से संबंधित सारी जानकारी देने के लिए उच्च शिक्षा परिषद के सदस्य अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा शासनादेश जारी किया गया है. अब हर कॉलेज की बेवसाइट पर छात्र को यह मालूम हो जाया करेगा कि उक्त कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहां किस–किस विषय की पढ़ाई की सुविधा है, किस विषय की फीस कितनी है और सीटें कितनी–कितनी हैं. आदेश का पालन न करने वाले कॉलेजों पर सख्त कार्रवाई शासन स्तर से की जाएगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthidunya.com

कृष्णा नदी का पानी हुआ ज़हरीला

भनेड़ा खेमचंद गांव के लिए अभिशाप बनी कृष्णा नदी के जल की 6 साल पहले की गई जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे. इस पर नदी को मृत घोषित कर दिया गया था. फिर भी नदी के जल को शुद्ध करने के लिए न तो शासन स्तर से कोई प्रयास हुए और न ही स्थानीय स्तर पर. नदी के प्रदूषण की कारक चीनी मिल और फैक्ट्रियों पर शिकंजा नहीं कसा जा सका.

सहारनपुर के नानौता विकास खंड के गांव खेमचंदपुर के लिए कृष्णा नदी काल बन चुकी है. शुगर मिल से निकलने वाले केमिकल युक्त अपशिष्ट ने कृष्णा नदी के पानी को काला कर दिया है. यही वजह है कि गांव का भूमिगत जल भी प्रदूषित हो चुका है. अब तक इस प्रदूषित जल से तीस ग्रामीण असमय काल के गाल में समा चुके हैं. हैंडपंपों से निकलने वाला दूषित जल पीकर गांव में घर–घर कैंसर, टीवी और त्वचा के रोगी तिल–तिल कर मरने को मजबूर हैं. गांव की बड़ी आबादी यहां से पलायन कर चुकी है, लेकिन प्रशासन–प्रशासन ने इस गांव की ओर झांकने की ज़हमत तक नहीं उठाई है.

ज़िला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर नानौता के गांव भनेड़ा खेमचंद को निर्मल गांव का दर्जा दिया गया था. गांव के प्रधान सुदेश राणा को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार भी मिल चुका है. तीन हज़ार की आबादी वाले इस गांव से सटी कृष्णा नदी का जल कभी इतना निर्मल था कि लोग नदी के पानी को ही पीते थे. यही कारण है कि गांव में कुआं तक नहीं था, लेकिन 1975 में नानौता में सरकारी शुगर मिल लगने के बाद ही इस गांव के दुर्दिन शुरू हो गए. शुगर मिल का केमिकल युक्त विषैला अपशिष्ट कृष्णा नदी में डाला जाने लगा और वर्तमान में हालत यह है कि इस नदी का पानी ज़हरीला हो गया है. यही विषैला जल ज़मीन के अंदर पहुंच जाने से हैंडपंप भी बदबूदार पीला पानी उगल रहे हैं. विषैले जल ने गांव की पूरी आबो–हवा को दूषित कर दिया है. इस गांव में घर–घर कैंसर, टीवी, चर्म रोग व पेट तथा आंत से संबंधित गंभीर बीमारियों के रोगी हो गए हैं. बीते माह अप्रैल में बारू सिंह, माला देवी, धारा, बुद्धु लुहार व सेवापाल की कैंसर व टीवी जैसी बीमारियों से मृत्यु हो चुकी है. दूषित जल पीने से 52 वर्षीया माला देवी के गुर्दे ख़राब हो गए थे और बाद में उसकी मृत्यु हो गई. इसी तरह चंद माह में गांव के मेहर सिंह, राजकुमार, रामशरण, शांति देवी, सेवाराम, सुखबीर सिंह, अशोक राणा, लक्ष्मणसिंह, अरम सिंह शर्मा आदि की दूषित जल के कारण कैंसर व अन्य बीमारियों से मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग ज़िंदगी और मौत के बीच आज भी जूझ रहे हैं. उनमें तीन पूर्व प्रधान भी शामिल हैं. मौत की नदी के भय से गांव से चंद वर्षों में ही 50 से ज़्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं. गांव के लोग कृष्णा नदी को अब मौत की नदी के नाम से पुकारने लगे हैं.

विषैले पानी की वजह से फैली बीमारियों ने आसपास के क्षेत्र में इतना आतंक है कि लोग इस गांव में वैवाहिक संबंध जोड़ने को तैयार नहीं हैं. यूं तो यह मौत रूपी नदी अन्य गांवों से भी गुज़रती है, पर अन्य गांवों की आबादी इसके तट से काफ़ी दूर निवास करती है. इसके चलते इन गांवों में इतना असर नहीं. मामले की शिकायत मुख्यमंत्री मायावती से लेकर कांग्रेस महासचिव अशोक गहलौत तक से की गई. 8 अगस्त 2006 को तत्कालीन डीएम को कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे, पर समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया. भनेड़ा खेमचंद गांव के लिए अभिशाप बनी कृष्णा नदी के जल की 6 साल पहले की गई जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे. इस पर नदी को मृत घोषित कर दिया गया था. फिर भी नदी के जल को शुद्ध करने के लिए न तो शासन स्तर से कोई प्रयास हुए और न ही स्थानीय स्तर पर. नदी के प्रदूषण की कारक चीनी मिल व फैक्ट्रियों पर शिकंजा नहीं कसा जा सका.

20 जुलाई 2006 को ज़िला प्रशासन द्वारा कृष्णा नदी के दो नमूने लिए. उनका पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट देहरादून की प्रयोगशाला में परीक्षण कराया गया. प्रयोगशाला ने जो रिपोर्ट दी उसे देखकर प्रशासन दंग रह गया. परीक्षण के परिणामों से ज्ञात हुआ कि भनेड़ा गांव के निकट इस नदी के जल में लैड की मात्रा 0.12 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जबकि इस भारी तत्व का निर्धारित स्तर 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर तय है. इसी तरह से क्रोमियम तत्व 0.10 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, पर इस नदी में 3.50 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया. इतना ही नहीं तब गांव में लगे हैंडपंप के जल के नमूने का रंग न केवल हल्का भूरा पाया गया, बल्कि जांच में वह अत्यधिक प्रदूषित निकला. जांच में परिणाम निकला कि यह नदी पूरी तरह से मृत हो चुकी हैं. इसका जल पूरी तरह से अशुद्ध है. कृष्णा नदी नानौता, मेरठ के क़स्बों से होते हुए गुज़रती है. बरनाला से होकर हिंडन नदी में मिल जाती है. इतने सालों में भी नदी के जल को जल को शुद्ध करने का कोई जतन नहीं हुआ.

शिखा जौलान
feedback@chauthidunya.com

कई उद्योग भी दोषी हैं

प्रदूषण की प्रतीक कृष्णा नदी का प्रारंभ नानौता की गल्ला मिल, शराब फैक्ट्री और मधुसूदन घी फैक्ट्री के गंदे पानी के नालों से होता है. यह नाले भनेड़ा खेमचंद के पास आकर मिलते हैं. बाद में इसमें नानौता, थाना भवन, सिक्का, रमाला के क़रीब आधा दर्जन उद्योगों का प्रदूषण भी मिल जाता है.

थानाध्यक्ष के हत्यारों का सुराग नहीं

राकेश कुमार यादव

उत्तर प्रदेश पुलिस पर कभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए.एन. मुल्ला द्वारा मुकदमे के फैसले के दौरान की गई टिप्पणी कि पुलिस अपराधियों का एक संगठित गिरोह है, का फिर एक ज्वलंत उदाहरण देखने को मिला. जब फ़ैज़ाबाद जनपद के थाना पटरंगा के वर्ष 2005–06 बैच में उपनिरीक्षक पद पर चयनित हुए 36 वर्षीय थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस मौत को पुलिस ने आत्महत्या बताया, लेकिन मृतक के परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताया. पुलिस की कार्यशैली संदेह पर आधारित होती है, लेकिन मृतक थानाध्यक्ष पटरंगा सर्वेश कुमार की मौत को पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा आत्महत्या क़रार देना अपने–आप में संदिग्ध है. तमाम फ़र्ज़ी मुठभेड़ों और इनमें हुई मौतों, पुलिस अभिरक्षा में किए गए टॉर्चर से हुई मौतों आदि आरोपों में आए दिन घिरी रहने वाली पुलिस जब अपने ही विभाग के एक अधिकारी की संदेहात्मक मौत से पल्ला झाड़ रही है. मृतक के परिजन जो स्वयं भी पुलिसकर्मी हैं, की भी अनसुनी और अनदेखी कर रही है तो ऐसे में सामान्य पीड़ितों के साथ पुलिस का रवैया कैसा होता होगा समझा जा सकता है. बहरहाल, पुलिस को मृतक के परिजनों की अपेक्षाओं के अनुरूप संपूर्ण मामले को पुलिस विभाग से इतर किसी ख़ुफ़िया एजेंसी को सौंप कर संपूर्ण मामले का ख़ुलासा कराना चाहिए. इस घटना में पुलिस की कार्यप्रणाली पर पुलिस विभाग के ही मृतक के परिजनों द्वारा उंगली उठाई गई है, जो स्वयं भी प्रदेश पुलिस विभाग का पुलिसकर्मी है. मृतक सर्वेश कुमार वर्ष 2006–07 में सीतापुर जनपद के पुलिस ट्रेनिंग केंद्र पर प्रशिक्षण लेकर वर्ष 2007 से 2010 तक क्रमशः फ़ैज़ाबाद जनपद की अयोध्या कोतवाली थाना तारून एवं राम जन्मभूमि परिसर पर एसआई के रूप में तैनात रहा था. जनवरी 2011 में थानाध्यक्ष पद पर प्रोन्नत वह पहली बार पटरंगा थाने पर नियुक्त था. नियुक्ति के चार माह के अंदर ही उसकी इस तरह रहस्यमय रूप में हुई. मौत लोगों में चर्चा का विषय बनकर रह गई है. ज्ञात हो कि पटरंगा थाना फ़ैज़ाबाद जनपद की सीमा पर स्थित जनपद बाराबंकी की रुदौली तहसील के अंतर्गत है और रुदौली तहसील फ़ैज़ाबाद में जुड़ जाने के कारण अब पटरंगा भी फ़ैज़ाबाद के अंतर्गत है. बाराबंकी जनपद मादक द्रव्यों के उत्पादन एवं उनके रूप को परिवर्तित करके उच्चस्तरीय तस्करी कराने के लिए जाना जाता है. इस तस्करी में तस्करों का सहयोग करने और बदले में मोटी रक़म कमाने के नाम पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सेंट्रल एक्साइज़, नार्कोटिक्स, कस्टम जैसे विभागों को भी नज़रंदाज़ किया जाता है. 29/30 अप्रैल की मध्य रात्रि में सर्वेश कुमार सर्विस रिवाल्वर से पुलिस की वर्दी

में थाना परिसर के निजी कक्ष में मरे था. लोगों में चर्चा है कि कानपुर जनपद के थाना सचेंडी क्षेत्र के ग्राम मकरनपुर निवासी सर्वेश कुमार की ईमानदारी व लोकप्रियता ही शायद उनके मौत की वजह बनी.

परिजनों द्वारा उसकी मौत से पर्दा उठाने की मांग को भी पुलिस ने दबाने की कोशिश की. मृतक दरोगा के पीड़ित परिजनों द्वारा मामले की उच्चस्तरीय ख़ुफ़िया एजेंसी द्वारा जांच कराए जाने की मांग और न्याय पाने की मंशा मीडिया के समक्ष की गई. मीडिया के लिए भी यह अपने कर्तव्य निर्वहन का ज्वलंत सवाल सामने खड़ा है. जो भी हो थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार के भाई शशि सोनकर द्वारा थाना पटरंगा में अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ धारा 302 आई.पी.सी. मुकदमा अपराध संख्या 249/2011 का अपराध भी काफ़ी मशक्कत के बाद लिखा गया. इस सारे प्रकरण की विवेचना रुदौली के थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही है.

feedback@chauthidunya.com

एक नज़र

एक माह का घरेलू बिजली बिल पैंतालिस लाख

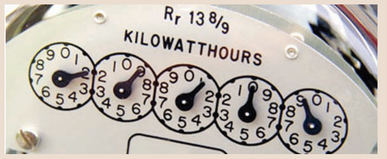

बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर के मोहल्ला अंसारियान में बिजली विभाग की लापरवाही और ग़लत रीडिंग के चलते एक व्यक्ति के घरेलू बिजली का एक माह का बिल तक़रीबन 45 लाख रुपये आया है. पीड़ित के उपभोक्ता फोरम में जाने की कवायद के बाद विभाग हरकत में आया और जांच के बाद बिल ठीक करने की बात कर रहा है. मोहम्मद हामिद पुत्र अब्दुल शमद के घर का अप्रैल माह का बिजली का बिल पैंतालीस लाख इक्यावन हज़ार चार सौ साठ रुपये का आया. अब्दुल शमद के पुत्र फ़राज़ ने बताया कि हर महीने सवा तीन से साढ़े तीन सौ रुपये बिजली का बिल आता था. अप्रैल महीने का इतना बिल देखा तो सिर चकरा गया. एसडीओ विद्युत से जब इस बाबत बात करने का प्रयास किया तो उनसे मुलाक़ात नहीं हो पाई. पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने के बाद ही विभाग हरकत में आया. फ़राज़ ने बताया कि विभागीय अधिकारी मामले की जांच करवाकर बिल ठीक करने की बात कर रहे हैं.

लिपिक ने दो कर्मचारियों के मनमाने ग्रेड बढ़ा दिए

अंबेडकर नगर के कृषि कार्यालय में बिल लिपिक द्वारा दो कर्मचारियों का ग्रेड पे किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही लगाकर वेतन बिल तैयार कर दिया गया. इतना ही नहीं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन बिल भी बिना अर्जित अवकाश स्वीकृत कराए दिया गया. उपकृषि निदेशक ने पूरे मामले में ज़िला कृषि अधिकारी को जवाब–तलब कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया. यह कृषि विभाग में लंबे समय से विवादों में रहा है. नया मामला मनमाने ढंग से वेतन बिल तैयार करने का है. मामले का ख़ुलासा तब हुआ जब ज़िला कृषि रक्षा अधिकारी के कर्मचारियों के मार्च और अप्रैल का वेतन बिल हस्ताक्षर करने के लिए उपकृषि निदेशक के समक्ष पहुंचा. पता चला है कि बिल लिपिक द्वारा सुभाषचंद्र श्रीवास्तव लिपिक व संजीव कुमार राय लिपिक का ग्रेड पे बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के ही लगा दिया गया है. वेतन बिल में 2800 से बढ़ाकर राशि 4200 कर दी गई. इसे उप कृषि निदेशक ने गंभीरता से लेते हुए पूरा वेतन बिल रोक दिया. डीडी कृषि यूपी सिंह ने ज़िला कृषि अधिकारी को पत्र लिखा है. इसमें वेतन बिल मनमाने ढंग से ग्रेड पे लगाए जाने का उल्लेख करने के साथ ही कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रविराय का वेतन भी बिना अर्जित अवकाश स्वीकृत कराए बिना बना दिया गया है. लाभ के लिए बिना स्वीकृति के ही उच्च ग्रेड पे लगाकर बिल बनाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है. कहा गया है कि यह अधिकारी को धोखे में रखकर वित्तीय अनियमितता के प्रयास का मामला है. सिंह ने ज़िला कृषि अधिकारी को बिल लिपिक से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए पूरा ब्यौरा मांगा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthidunya.com

भ्रष्टाचार की जड़

राजनीतिक ढांचे को बदलने की ज़रूरत

सभी राजनीतिक पार्टियां ख़ुद को यह दिखाती हैं कि वह किसी ख़ास विचारधारा के लिए समर्पित हैं और इसके लिए ही संघर्ष कर रही हैं, लेकिन हक़ीक़त में ऐसा है नहीं. विचारधारा तो केवल उनके आवरण में है, आचरण में नहीं. राजनीतिक पार्टियां यह प्रदर्शित नहीं करती कि पार्टी फंड उसके पास माफ़िया, पूंजीपतियों और दलालबाज़ारियों से आ रहा है. जबकि सभी पार्टियों के पास फंड आता इन्हीं स्रोतों से है. हमारे देश में भ्रष्टाचार का अंकुर राजनीतिक आचरण से ही उपजा है. हर राजनीतिक पार्टी अपना फंड और बाहुबल बढ़ाने के लिए ही धनवान, आपराधिक और बाहुबलियों को टिकट देती है. राजनीतिक दल हर वर्ष सदस्यता अभियान भी चलाते हैं और संगठन का चुनाव भी वार्ड से लेकर ज़िला, प्रांत और केंद्रीय स्तर तक कराते हैं. ऊपर से दिखाई देता है कि पार्टी में सबकुछ लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न हुआ है, पार्टी के पास फंड भी कार्यकर्ताओं की सदस्यता से ही जुटाया गया है, लेकिन हक़ीक़त में न किसी पार्टी में सदस्यता अभियान ईमानदारी से चलता है, न सदस्यता अभियान से जुटे फंड से पार्टी की गतिविधियों पर कोई असर पड़ता है और न पार्टी के संगठनात्मक चुनावों में ही ईमानदारी बरती जाती है. पार्टी के बड़े ज़िला पदाधिकारी जो हर राजनीतिक दल में मिले–चुने ही होते हैं, वे सदस्यता अभियान की कॉपियों को आपस में बांट लेते हैं. इन कॉपियों को अपने–अपने व्यावसायिक संस्थानों में या अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में लोगों से भरवाने के लिए बांट देते हैं. लोग भाग–दौड़कर अपने जानने वालों के नामों से इन सदस्यता कॉपियों को भर देते हैं. सभी कॉपियों का पूरा भुगतान दिग्गज नेता अपनी जेब से करते हैं. ज़िला पदाधिकारी अपने ख़ास लोगों को जो सदस्यता कॉपियां भरवाने में भूमिका निभाते हैं, उनको पार्टी का सक्रिय सदस्य बनवा देते हैं. हर पार्टी की साधारण सदस्यता की फीस अमूमन पांच रुपये और सक्रिय सदस्यता की फीस 25 रुपये है. इस तरह हमारे देश में बड़े से बड़े राष्ट्रीय दलों की अधिकतम सदस्यता एक करोड़ भी मान सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी का वार्षिक फंड 35–40 करोड़ रुपये बैठता है, जबकि इतने रुपये का फंड किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए ऊंट के मुंह में ज़ीरे के समान है.

जिस तरह सदस्यता अभियान में ज्ञानापूर्ति की जाती है उसी तरह संगठन के चुनाव में भी ज्ञानापूरी की जाती है. पार्टी में कुछ प्रतिशत सदस्य अपनी सक्रियता और कर्मठता के बल पर जुगाड़ की तरह टिमटिमाते हैं तो पार्टी के दिग्गज समीकरण बनाकर पार्टी पदाधिकारियों के नामों के बीच छोटे पदों पर इनके नाम भी तय कर देते हैं. आम सभा में इसका अनुमोदन हो जाता है. किसी नाम पर कोई विवाद या प्रतिद्वंद्विता दिखलाई पड़ती है तो प्रांतीय पदाधिकारी की मध्यस्थता से इसका निदान कर लेते हैं. ज़्यादातर मामलों में पार्टी सुप्रीमो की ही चलती है. बसपा धन अर्जित करने के मामले में सबसे आगे है. एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस के मुताबिक़ सत्तासीन होने के दो साल बाद ही बसपा के पार्टी फंड में 251 करोड़ रुपये हो गए थे. वर्ष 2008–09 में पार्टी फंड 69 करोड़ रुपये से बढ़कर 182 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा. यह वृद्धि 161 फीसदी है, जो देश की किसी भी पार्टी से अधिक है. बसपा ने अपने दानदाताओं के नामों का ख़ुलासा नहीं किया है. वर्ष 2008–09 में कांग्रेस के फंड में 220 करोड़ से बढ़कर 496 करोड़ रुपये थे. यह बढ़ोतरी क़रीब 125 फ़ीसदी की है. पार्टी के पास सबसे ज़्यादा 717.69 करोड़ रुपये का फंड है. वहीं

भाजपा के पास पार्टी फंड में 343 करोड़ रुपये थे. सीपीएम के पास 122.53 करोड़ रुपये फंड में जमा थे. क्या कार्यकर्ताओं की सदस्यता से इतना फंड जुटाया जा सकता है? हमारे देश में राजनीति व्यवसाय है. राजनीतिक दलों के केंद्रीय कार्यालय कॉरपोरेट मॉडल के हैं, इनमें इसी प्रकार के पदाधिकारी, कर्मचारी और उपकरणों की व्यवस्था है. एक रिपोर्ट के अनुसार प्रचार एवं यात्रा के मामले में भाजपाई नेता कांग्रेसियों से आगे दिखाई देते हैं.

एक साल में भाजपा ने प्रचार पर 34.96 करोड़, यात्रा पर 16.52 करोड़ और बैठकों पर 9.18 करोड़ रुपये ख़र्च किए थे. कांग्रेसी नेता भी पार्टी फंड पर ख़ूब यात्रा करते हैं. कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2007–08 के दौरान अपने नेताओं की यात्रा और प्रवास पर एक साल में पूरे दस करोड़ रुपये ख़र्च किए थे. कांग्रेस पार्टी ने अपने गाड़ियों के रखरखाव पर एक साल में एक करोड़ रुपये ख़र्च कर दिए. भाजपा ने इस अवधि में अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए जहां 25.89 लाख रुपये की मदद की वहीं चुनावी सर्वेक्षण पर इससे भी ज़्यादा 27.09 लाख रुपये ख़र्च कर दिए. पार्टी ने वित्त वर्ष 2007–08 के दौरान एक साथ 45 स्कॉर्पियो ख़रीदी. सिर्फ़ इन्हीं पर पार्टी का 3.66 करोड़ रुपये का ख़र्च आया. पार्टी फंड से 25 लाख रुपये की आलीशान रफ्तोरा कार भी आ गई. सारे ख़र्चों को मिलाकर राष्ट्रीय पार्टी के वर्ष भर में एक अरब रुपये के आसपास ख़र्च होते हों और पार्टी की सदस्यता से मात्र 35–40 करोड़ रुपये ही आए तो बाक़ी के पैसों के इंतज़ाम के लिए भ्रष्टाचार करना ज़रूरी हो ही जाता है. सभी दलों ने मिलकर संसद में क़ानून पास कराया कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर न राजनीतिक पार्टियों को कर देय होगा और न चंदा देने वाले को. आयकर की धारा 13ए के अंतर्गत हर राजनीतिक दल को यह लाभ बराबर मिलता चला आ रहा है. किसी राजनीतिक दल को जो संस्थान या व्यक्ति करोड़ों रुपये का फंड देते हैं तो निश्चित ही वे पार्टी की सरकार बन जाने पर इससे कई गुना लाभ पाने की सोचेंगे ही. सरकार न भी बने तो संसद या विधानसभा में दानदाताओं के हितरक्षा में ये लोग खड़े ही रहेंगे. सरकार बनने पर राजनीतिक पार्टियां अपने दानदाताओं को ख़ुश करने के लिए शासन द्वारा किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाने के लिए क़दम उठाती हैं. यही है पार्टी का भ्रष्टाचार जो चंदा लेने से शुरू हुआ था. राजनेता अपने फायदे के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अपने परिजनों को शामिल करने के लिए अनेक तरह के फ़र्ज़ीवाड़े करते हैं. केंद्र के पूर्व संचारमंत्री एवं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री सुखराम के घर से 3.61 करोड़ रुपये नक़द बरामद किए गये थे. वे इस पैसे का हिसाब नहीं दे सके थे, भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें तीन साल क़ैद की सजा सुनाई गई थी. तब स्पेशल जज वी.के.महेश्वरी ने समाज में फैले भ्रष्टाचार पर सख़्त टिप्पणी की थी कि लोकसेवक जिस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यह स्थिति समाज के लिए बेहद ख़तरनाक है. राजनीतिक भ्रष्टाचार निम्नतम स्तर पर है और इसके दूरगामी दुष्परिणाम होंगे. भ्रष्टाचार के दलदल से तभी निकला जा सकता है जब इसके लिए ईमानदारी से कोशिश हो. भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में सीबीआई को आम जनता का शिकार बनना पड़ता है. राजनीतिक भ्रष्टाचार के अधिकांश मामलों में सीबीआई अपने हाथ खड़े कर देती है. सीबीआई के निदेशक अश्विनी कुमार ने एक साक्षात्कार में स्वीकार था कि उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार से निबटना सीबीआई के बूते की बात नहीं है. इसके लिए केंद्रीय स्तर पर लोकपाल जैसी अथॉरिटी का गठन बहुत ज़रूरी है.

राजेंद्र सारथी
feedback@chauthidunya.com